हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 16 मार्च, 2017 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाहन आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल आरम्भ

तारांकित प्रश्न

16/03/2017/1100/RKS/AS/1

<u>प्रश्न संख्याः 3660</u>

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, यह सरकार बड़ा दावा करती है कि हम बड़ी पारदर्शिता से काम करते हैं और कोई भी चीज़ छिपाते नहीं हैं। यह प्रश्न पिछले सत्र का था और अभी तक सूचना ही एकत्रित की जा रही है। यह सरकार की कारगुज़ारी को दर्शाता है कि सरकार कितनी एफिशियंट है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसी सत्र में वांछित सूचना दे दी जाएगी?

Speaker: Hon'ble Health and Family Welfare Minister on behalf of the Hon'ble Chief Minister.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय, यह सरकार पूरी जवाबदेही और पारदर्शिता से काम करती है। आपका जो प्रश्न था वह इतना विस्तृत है कि सभी सरकारी विभागों,

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

16.03.2017/1105/SLS-AS-1

प्रश्न संख्या : 3660 ....क्रमागत

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ....जारी

बोर्ड़ों और निगमों में कितने-कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। इससे संबंधित 61 कार्यालयों की सूचना अभी तक हमारे पास आई है जिनमें 21 कार्पोरेशंज और बोर्ड़ों की भी सूचना शामिल है। 18 बोर्ड़ों और निगमों की सूचना आनी अभी शेष है तथा अभी 25

विभागों से भी सूचना नहीं आई है। हम कोशिश करेंगे कि सूचना इकट्ठी कर इसी सत्र में आपको विस्तृत सूचना दी जाए। हम अधूरी सूचना नहीं देना चाहते हैं। आपको पूरी सूचना देंगे और पूरी तसल्ली करवाएंगे।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, चोर दरवाजे से भर्तियां की जा रही हैं और जब हम सूचना मांग रहे हैं तो वह सूचना नहीं दी जा रही है। फिर मंत्री जी कह रहे हैं कि बड़ी पारदर्शिता के साथ सरकार चल रही है। ...(व्यवधान)... रविन्द्र रवि जी भी इसमें प्रश्न पूछना चाह रहे थे लेकिन उन्हें आप अलौ नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष : मंत्री जी ने कह तो दिया है कि सूचना एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है और उसे इसी सत्र में देने की कोशिश की जाएगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर ये प्रश्न को पढ़ेंगे तो उसके अनुसार, जो कर्मचारी पहले से ही अनुबंध पर लगे हैं, इन्होंने उनके बारे में पूछा है कि उनमें से कितनों को नियमित किया गया है। यह नहीं पूछा कि कितने लोग भर्ती किए गए हैं। इसमें बैकडोर का प्रश्न कहां पैदा होता है? हमने कहा कि आपको विस्तृत तौर पर सूचना देने की कोशिश करेंगे।

समाप्त

16.03.2017/1105/SLS-AS-2

प्रश्न संख्या : 3665

श्री पवन काजल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह प्रश्न बैकलॉग का है। पिछले सत्र में भी मैंने यही प्रश्न पूछा था। उसमें जवाब आया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के बैकलॉग को भरने का निर्णय लिया गया है। मैंने पूछा था कि क्या उसी तर्ज़ पर सरकार ओ.बी.सी. का बैकलॉग भरने का भी विचार रखती है। उसमें उत्तर आया था कि यह मामला सरकार के स्तर पर चर्चा में है। जो

ओ.बी.सी. का बैकलॉग है, उसे भरने के बारे में पीछे कैबिनेट में भी चर्चा हुई थी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आने वाले समय में उसको भरेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह मामला सरकार के विचाराधीन है। इन्होंने पूछा था कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का बैकलॉग भरने के बारे में सरकार गंभीर है? हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के बैकलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरेंगे। लेकिन जो ओ.बी.सी. का प्रश्न तथा डी.पी. और पी.टी.आई. के बारे में इन्होंने पूछा था, हमने उसकी सूचना शिक्षा विभाग से मंगवाई है। बैकलॉग पूर्ण करने हेतु ओ.बी.सी. को भी इसमें शामिल किया गया है। उनका बैकलॉग भरने की प्रक्रिया जारी है। हम कोशिश करेंगे कि इसी सत्र में आपको इसका उत्तर विस्तृत तौर पर दे दिया जाए।

16.03.2017/1105/SLS-AS-3

प्रश्न संख्या : 3842

श्री इन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में पशुधन के महत्व को ध्यान में रखते हुए आदरणीय धूमल साहब की पिछली सरकार ने ये योजना प्रदेश में लांच की थी जिसके तहत हर पंचायत में एक-एक पशु औषधालय खोलने की बात की गई थी। जो प्रश्न का उत्तर मुझे मिला है उसके अनुसार केवल 1251 औषधालय ही प्रदेश में आज तक खुले हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्योंकि हमारी कुल पंचायतें 3243 हैं, इसलिए जो पंचायतें बाकी बची हैं वहां पर औषधालय कब तक खुलेंगे तथा इस सरकार ने अपने कार्यकाल में पिछले साढ़े चार सालों में ऐसे कितने औषधालय खोले हैं? यह सूचना मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

जारी ..श्री गर्ग जी द्वारा

16/03/2017/1110/RG/DC/1

प्रश्न सं. 3842---क्रमागत

श्री इन्द्र सिंह के पश्चात के पश्चात

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस मामले में कुछ कन्फयूजन में हैं क्योंकि 'मुख्य मंत्री आरोग्य पशुधन योजना' वहां शुरू की गई थी जिस पंचायत में एक भी औषधालय नहीं था। इसलिए वर्ष 2010 में 186 डिस्पैंसरी खोली गईं, वर्ष 2011 में 826, वर्ष 2012 में 238 और वर्ष 2013 में पांच डिस्पैंसरीज़ खोली गई थीं। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, तो इस याऐजना में केवल वे ही पंचायतें आती हैं जहां पर हमारा कोई भी पशु औषधालय नहीं है। इसलिए सभी जगह इस समय हमारे पशु औषधालय मुख्य मंत्री आरोग्य पशुधन योजना के अन्तर्गत खुले हैं और आगे भी वहीं खोले जाएंगे जहां हमारे पास कोई भी पशु औषधालय नहीं होंगे।

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि सड़कों पर जो बीमार आवारा पशु घूमते हैं या किसी वजह से वे घायल हो जाते हैं क्या उनकी चिकित्सा का भी इन्होंने कोई बन्दोबस्त करने का विचार किया है? दूसरे, जो सांड़ सड़कों पर घूमते हैं, वे आदमियों को घायल कर देते हैं या मार भी देते हैं, तो उनकी स्टैरलाईजेशन के बारे में भी क्या माननीय मंत्री जी ने कुछ सोचा है ताकि वे शांत हो जाएं?

Speaker : This subject is not connected to this question.

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला प्रश्न मेरा यह है कि इन औषधालयों में जो फार्मासिस्ट्ज हैं, जैसे और जगह पर फार्मासिस्ट्ज को एन.पी.ए. मिलता है, तो क्या इनको भी एन.पी.ए. देने के बारे में सरकार सोच रही है?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पहला प्रश्न किया था कि वह तो इससे संबंधित नहीं है। दूसरा, जो फार्मासिस्ट्ज से संबंधित प्रश्न इन्होंने पूछा है, जब ये फार्मासिस्ट्ज लगे थे तब इनको 5000/-रु. प्रतिमाह दिया जाता था और अब इनको हम 7000/-रुपये प्रतिमाह दे रहे हैं।

डॉ. राजीव बिन्दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके विभाग की जो पॉली क्लीनिक्ज अभी चलाई गई हैं और पहले से भी चल रही हैं उनमें ज्यादातर पॉली क्लीनिक्ज शहरी क्षेत्रों में

16/03/2017/1110/RG/DC/2

हैं और टॉऊन के बीचो-बीच वे हैं जिनमें 4-5-6 विशेषज्ञ बैठे हुए हैं और वहां पशुओं को पहुंचाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि शहर में पशुओं का लाना कठिन होता है। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए जो विशेषज्ञ या पॉली क्लीनिक्ज हैं उनको उन क्षेत्रों में पहुंचाने का माननीय मंत्री जी प्रयास करेंगे जहां वास्तव में पशुधन है? ताकि इनका लाभ वहां भी मिल सके।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इनका प्रश्न इससे संबंधित नहीं है। परन्तु जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, **तो पॉली क्लीनिक्ज में चार विशेषज्ञ डॉक्टर्ज होते हैं, यदि इस तरह हमें लगेगा और जहां शहर में पशु लाना मुश्किल होंगे, तो इस पर भी ऐग्जामिन कर लिया जाएगा।**

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया है कि 1251 ऐसे पशु औषधालय हैं अर्थात गोपाल सहायकों की नियुक्ति उनमें की गई है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इनके जिम्मे कौन-कौन सा दायित्व है? इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से आज बढ़ती हुई आवारा पशुओं की संख्या है उसमें अधिकांश बछड़े छोड़े जाते हैं। तो क्या इनको ये दायित्व देंगे कि जैसे ही बछड़े छोड़े जाते हैं उनको स्टैरलाईज करके उनके रजिस्टर में दर्ज कर दें ताकि सांड़ की समस्या तो कम-से-कम खत्म हो।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। ये जो पंचायत वैटरीनरी असिसटैंट्स हैं इनका काम ए.आई. फैसिलिटी प्रदान करना और पशुओं का इलाज करना है। स्टरलाईजेशन का हम इसमें तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे जितने भी अस्पताल हैं वहां हम कर रहे हैं और इसमें अभी तक कोई सुविधा नहीं दी गई है।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2010 में प्रदेश में माननीय प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में सरकार थी, तो उस समय इस योजना को शुरू किया गया था। उस समय निर्णय किया गया कि हर पंचायत में इस योजना के अन्तर्गत एक संस्थान खोला जाए।

एम.एस. द्वारा जारी

16/03/2017/1115/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 3842 क्रमागत---
श्री रविन्द्र सिंह जारी---------

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में इस समय जो हमारी 3226 पंचायतें हैं इनमें से कितनी पंचायतों में यह "मुख्य मंत्री आरोग्य पशुधन योजना" या अन्य किसी योजना के अंतर्गत संस्थान खुल गए हैं तथा अभी कितनी पंचायतों में खोलने शेष हैं? जो बची हुई शेष पंचायतें हैं उनमें आप कब तक यह सुविधा उपलब्ध करवा देंगे? दूसरे, उस समय पंचायतों को कहा गया था कि संस्थान के लिए एकॉमोडेशन आप प्रोवाइड करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान में सरकार की क्या नीति है? जिन पंचायतों ने भूमि विभाग के नाम करवा दी है क्या उन पंचायतों के भवनों के निर्माण के लिए सरकार प्राथमिकता देगी?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, मैं इनको बताना चाहता हूं कि इसकी वही पॉलिसी है जो आपके समय में थी। उसमें फ्री एकॉमोडेशन दी जाती है और फ्री एकॉमोडेशन के ऊपर ही "मुख्य मंत्री आरोग्य पशुधन योजना" की डिस्पेंसरी खुलती है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो पंचायतें बची हुई थीं ये उन्हीं में खुली हैं। इसलिए कोई-न-कोई संस्थान हरेक पंचायत में है, यह बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

प्रश्न समाप्त

16/03/2017/1115/MS/AG/2

प्रश्न संख्याः 3843

श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष जी, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 2452 पात्र युवाओं को "कौशल विकास भत्ता" दिया गया है, उन्हें यह भत्ता किस आधार पर दिया गया है तथा इसकी चयन प्रक्रिया क्या है? दूसरे, इस योजना को प्रदेश में कब से शुरू किया गया है? इसके अलावा, इस योजना में केन्द्र सरकार का कितना योगदान है?

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यह शत-प्रतिशत हिमाचल सरकार द्वारा पोषित योजना है और इसमें केन्द्र सरकार का कोई रोल नहीं है। आपसे पहले माननीय सदस्या श्रीमती सरवीन चौधरी जी ने भी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान यह उल्लेख किया था कि "कौशल विकास भत्ता योजना" का पैसा केन्द्र से आ रहा है और यह बात हम जाकर जनता को बताएंगे। मैं यहां यह स्पष्ट कर दूं कि "कौशल विकास भत्ता योजना" शुद्ध हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है। हिमाचल प्रदेश सरकार हर साल इसके लिए 100 करोड़ रुपये बजट का निर्धारण करती है और वर्ष 2013 में यह योजना शुरू हुई थी। अभी तक इस योजना पर कुल 124 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और 1,62,553 युवाओं को इससे फायदा हुआ है। जहां तक मण्डी जिले का सवाल है तो वहां 19,775 लोगों ने इससे फायदा लिया है तथा आपके चुनाव क्षेत्र के 2452 लोग इसमें शामिल हैं। आपको मैंने आपके चुनाव क्षेत्र की पूरी लिस्ट मुहैया करवा दी है और साथ में मोबाइल नम्बर भी दे दिए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि यह चुनाव के दृष्टिगत भी आपका प्रश्न होगा। इसी तरह से जहां तक इसकी शर्तों का सवाल है तो इसके लिए 16 से 36 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए और उसकी पारिवारिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए तथा किसी भी रोज़गार कार्यालय में वह व्यक्ति पंजीकृत होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनके लिए शैक्षणिक योग्यता बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है अन्यथा इसके लिए आठवीं पास क्वालिफिकेशन रखी गई है।

सिर्फ मिस्त्री, बढ़ई, लोहार और पलम्बर इत्यादि ट्रेड्स के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है।

अगला प्रश्न श्री जे0एस0 द्वारा-----

16.03.2017/1120/जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 3844

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, यह ट्रांसमिशन लाइन पार्वती/ कोल डैम की जो गई है वह तकनीकी दृष्टि से जिस प्रकार से नियम है उन नियमों को ताक पर रखते हुए और उसके साथ-साथ में स्थानीय जनता को पूछे बिना उनसे सलाह किए बिना ट्रांसमिशन लाइन जोड़ दी गई। उसके बाद स्थिति यह हो गई कि बहुत सारी जगह ट्रांसमिशन लाइन जो ऊपर से गई है उसके नीचे चाहे खेत है, चाहे लोगों के घर है वहां पर लोगों को करंट के झटके लग रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर यहां पर दिया गया है उसमें भी स्वीकार किया गया है। ग्राम पंचायत सरोआ, ग्राम पंचायत तांदी, ग्राम पंचायत वाहवा, ग्राम पंचायत खारसी, ग्राम पंचायत बैहरी और ग्राम पंचायत नौण भी है जो कि नाचन विधान सभा क्षेत्र का हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि घर के आंगन में कपड़े सुखाने के लिए तार लगाई गई है अगर उस तार को टैस्ट पिन से टच करें तो वह जल जाता है। वहां की स्थानीय जनता इसके बारे में बार-बार डी0सी0 व अन्य अधिकारियों से मिली लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह बहुत गम्भीर मामला है। जब यह लाइन बिछाई गई तो पेड़ काट दिए गए। वहां पर जो प्राईवेट लैंड में लोग थे उनको कम्पनसैंशन नहीं दिया गया । घरों के ऊपर से वह लाइन बिछा दी गई है। वहां पर लोगों को अपने घरों की छतों पर जाना भी मुश्किल हो गया है। घर में रहना लोगों को मुश्किल हो गया है। क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जहां-जहां, जिन-जिन टॉवर्ज का आपने जिक्र किया है, टॉवर नम्बर, 78 से 83,98,99,103 व 107 और आपने इस बात को भी कहा कि वहां पर हमने चीफ इलैक्टिकल इंस्पैक्टर को भेज करके इसका निरीक्षण

करवाया है। जहां-जहां वर्तमान स्थिति में इस करंट का प्रवाह है क्या उसको हटाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं? वहां पर दहशत के माहौल में लोग जी रहे हैं। क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इस सारे मामले में एक टीम का गठन करके उनको वहां पर भेजिए और

16.03.2017/1120/जेके/एजी/2

वहां के लोगों को इस दहशत के माहौल से बाहर निकालने के लिए जो भी ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, उठाए जाए और उसके लिए क्या मंत्री जी विभाग को आदेश देंगें?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस लाइन का सवाल है यह लाइन जो हमारे इन्टर नेशनल टेंडर हैं उसके हिसाब से बिछाई गई है। इस लाइन के लिए लगाए गए टावर नम्बर 78 से 83, 98,99,103 व 107 के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सरोआ, ग्राम पंचायत वाहवा, ग्राम पंचायत खारसी तथा ग्राम पंचायत बैहरी के ग्रामीणों द्वारा यह शिकायत की गई थी कि उक्त टावरों के कारण करंट के झटके महसूस हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में उक्त टावरों का निरीक्षण मुख्य विद्युत निरीक्षक, हि0प्र0 विद्युत निरीक्षणालय, शिमला से दिनांक 03 से 05.03.2015 को करवाया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि टावर संख्या 103 के निकट स्थित गांव भारसी के आसपास के खेतों में तथा टावर संख्या 107 के निकट स्थित गांव नौण में बेली राम के घर के आसपास करंट का प्रवाह पाया गया। शेष अन्य गांव में भी उक्त लाइन का निरीक्षण किया गया तथा कहीं भी करंट का प्रवाह नहीं पाया गया।

पार्वती /कोल डैम ट्रांसमिशन लाइन से लगने वाले करंट के प्रभाव को कम करने के लिए मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा मैसर्ज पार्वती कोल डैम ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटिड (PKTCL)को टावर के साथ स्थित गांवों में रहने वाले लोगों को करंट लगने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दिए गए सुझावों की अनुपालना कम्पनी प्रबन्धन द्वारा अमल में लाई गई है तथा इसके अन्तर्गत टावर नं0 78 से 83,98,99,103 व 107 की Effective Earthing

कर दी गई है। टावर नं0 103 पर तारों की जमीन से दूरी 8.2 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दी है। टावर न0 80 व 81 के बीच में एक चीड़ का वृक्ष वन विभाग की भूमि पर स्थित था जिसे वन विभाग द्वारा काट दिया गया है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

16.03.2017/1125/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 3844 क्रमागत

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री क्रमागतः

इसके अतिरिक्त टावर नं0-107 के साथ लगने वाले मकान की छत से निकले हुए सरियों की कटाई के बारे में दिए गए सुझाव के अनुसार श्री बेली राम द्वारा वहां कार्य करने से इंकार कर दिया है।

सर, वहां पर एक मकान है, उस मकान की छत के ऊपर सरिये निकले हुए हैं, उन सरियों को काट कर वहां की समस्या दूर होगी और वह उन सरियों को काटने नहीं दे रहा है तो मैं इसमें माननीय सदस्य से सहायता चाहूंगा।

श्री विनोद कुमारः माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा और इनके ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि जिन बेली राम जी के ये बात कर रहे हैं वह मेरी विधान सभा क्षेत्र के बैहरी गांव के रहने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जिन-जिन जगहों पर टावर लगाये गए हैं, एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि उसकी सहमति से टावर लगाये गए हैं।

दूसरी बात, जिसकी जगह पर टावर लगे हैं किसी किसान को 50 हजार रुपये, किसी किसान को 20 हजार रुपये और कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनकी जगह पर टावर लगाये हैं लेकिन अभी तक उनको पैसे भी नहीं दिये गये हैं। उनके बार-बार विरोध करने के बावजूद भी उनको जो जगह का उचित मुआवजा मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा। जिन बेली राम जी के घर की ये बात कर रहे हैं वह टावर लाइन लगने से पहले का बना हुआ है। उसको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। पुलिस के माध्यम से, डी0सी0 के माध्यम से उस व्यक्ति को बार-बार धमकाया जा रहा है। जिसके वहां पर फलदार पौधे आते हैं,

उन्हें फलदार पौधों का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। प्रशासन की ओर से एक परसैंट भी उन किसानों की मदद नहीं की जा रही है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को निश्चित करेंगे कि जिन किसानों के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है उनके साथ अत्याचार न हो। आपके माध्यम से क्या उन किसानों को इंसाफ मिलेगा? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः सर, यह लाइन तो बड़ी पहले की लग गई है और जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, अत्याचार

16.03.2017/1125/SS-AG/2

उन किसानों के साथ बहुत पहले का हो चुका है, अब मैं नहीं करूंगा और जैसे ये कह रहे हैं कि उनके साथ अत्याचार हुआ है उसको दूर किया जायेगा।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, यह जवाब बिल्कुल सैल्फ-कंट्राडिक्टरी है। एक तरह स्वीकार किया जा रहा है कि कुछेक टावर में करंट का प्रवाह पाया गया। दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि हमने उसकी इफैक्टिव अर्थिंग की है। उसके बाद तीसरी बात आपने कही कि टावर लाइन की हाइट को भी बढ़ाया है। कोई भी ऐसा टावर नहीं है जिसकी ग्राउंड क्लीयरैंस को बढ़ाया गया है। वह उतनी की उतनी ही है। एक बात यह है।

दूसरी बात, इफैक्टिव अर्थिंग करने के बावजूद भी आज वर्तमान स्थिति में वहां करंट का प्रवाह चल रहा है। हम यह बात कह रहे हैं। क्या आप एक टीम गठित करेंगे ताकि जो लोग दहशत में रह रहे हैं, उन्हें उससे निजात मिल सके? बच्चों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। किसानों को अपने खेत में फसल लगाना मुश्किल हो गया है। इस दहशत के माहौल में अगर आपके अनुसान वहां करंट नहीं भी है तो क्या वहां पर लोगों के बीच जा कर टीम गठित करके इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ये-ये हमने कर दिया है, इसके अलावा अगर और भी कुछ करने की ज़रूरत होगी तो हम वह भी करेंगे लेकिन आपको दहशत में रहने की आवश्यकता नहीं है?

तीसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो कम्पनसेशन की बात कर रहे हैं, जिस बेली राम के घर की ये बात कर रहे हैं वह घर पहले से बना है। तो उसके

ऊपर से टावर लाइन को दाएं-बाएं से किया जा सकता था, उसकी गुंजाइश थी लेकिन उसके बावजूद ट्रांसमिशन लाइन वालों ने कहा कि लाइन यहीं से जायेगी। उस आदमी को अपने घर में रहना मुश्किल हो गया है। न उसको घर के लिए कम्पनसेशन दिया जा रहा है ताकि वह दूसरी जगह घर बना सके। क्या इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जिनको इसके कारण नुकसान हुआ है, पेड़ कटे हैं उनको उचित कम्पनसेशन मिले? लेकिन उनको कम्पनसेशन नहीं मिला। जिनका मकान करंट की जद में आ गया है, अगर उनको दूसरी जगह मकान बनाना है तो क्या उनको हायर साइड पर कम्पनसेशन दिया जायेगा ताकि कम-से-कम उनको रिहैब्लिटेट किया जाए? इन सारी बातों को ले करके मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि आप इसका समाधान करने के लिए सही और स्टीक जवाब दें।

जारी श्रीमती के0एस0

16.03.2017/1130/केएस/एएस/1

प्रश्न संख्या : 3844 जारी....

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न करंट लग जाने पर कम्पनसेशन के बारे में है। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि लोग डर में रह रहे हैं, अब मैं क्या बताऊं? मैं एक टीम बनाकर 24 घण्टे तो वहां रख नहीं सकता।

श्री जय राम ठाकुरः मंत्री जी, हम तो यह कह रहे हैं कि वहां पर जाओ और सच्चाई देखकर आओ। वहां पर जाता ही कोई नहीं है।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः तो मैं वहां जा कर क्या खम्भे के साथ लटकूंगा? मैं कह रहा हूं कि मैं वहां टीम भेजूंगा। वह टीम वहां पर चक्कर लगा कर आ जाएगी और जब उस टीम को करंट नहीं लगेगा तो लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगें कि आपको करंट नहीं लगेगा? वहां टीम जाएगी और देखकर आएगी। वह वहां लोगों को समझाएगी। वैसे ये तारें तो ऐसी है कि अगर आपस में ज़रा सा भी टकरा जाएं तो अपने आप ही डिस्कनैक्ट हो जाती है। वहां पर करंट नहीं रहता।

16.03.2017/1130/केएस/एएस/2

प्रश्न संख्याः 3845

श्री राकेश कालिया:अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, मैंने उसको डिटेल में पढ़ा है। आपने कहा है कि वर्ष 2012-13 में भरवाईं, अम्ब और जोल क्योंकि चिन्तपूरनी विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है, उसके ऊपर 5.4 करोड़ रुपये खर्च हुए और मेरा विधान सभा क्षेत्र जिसमें मात्र एक सब-डिविज़न आती है, उसमें 2.9 करोड़ रु0 खर्च हुए। और वर्ष 2013-14 में 5.6 करोड़ रु0 खर्च हुए भरवाईं, अम्ब और जोल में, एक कन्सिच्युएंसी है चिन्तपूरनी। इसका थोड़ा सा हिस्सा बंगाणा में होता है और गगरेट में 3 करोड़ रु0 खर्च हुए। यहां भी 2 करोड़ रु0 का फर्क है। वर्ष 2014-15 में अम्ब, भरवाई और जोल में लगभग 4 करोड़ रु0 खर्च हुए और मेरे चुनाव क्षेत्र में मेरे सब डिविज़न में 2.7 करोड़ रु0 खर्च हुए। वर्ष 2015-16 में भी ऐसा ही है। साढ़े पांच करोड़ रु0 अम्ब, जोल और भरवाईं सब डिविज़नों में खर्च हुए और मेरे सब डिविज़न में 3.31 करोड़ रु0 खर्च हुए। तो यह जो फर्क आ रहा है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार सालों में साढ़े नौ करोड़ रु0 खर्च हुए हैं और चिन्तपूरनी विधान सभा क्षेत्र में 19 करोड़ रु0 खर्च हुए हैं। लगभग 10 करोड़ रु0 का अन्तर है । कर्नल साहब ने मुझे पत्र लिखा हैः Mr. Kalia, the roads of the Constituency of Shri Virender Kanwar are very good then your Constituency, either Shri Virender Kanwar belongs to the Opposition Party. तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ यह जो अनियमितता हुई है, अगर कहीं गलती से हुई है, अध्यक्ष जी, यहां पर ई.एन.सी. साहब भी बैठे हैं, और सचिव, लोक निर्माण विभाग भी बैठे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 10 करोड़ रु0 कम खर्च हुए हैं जबकि सड़कों का घनत्व भी वहां ज्यादा है और सड़कें भी ज्यादा हैं। सड़कों की दशा भी खराब है। मैंने मुख्य मंत्री महोदय को कई बार पत्र भी लिखा है। उन्होंने एक करोड़ रु0 इस बार एक्स्ट्रा भी दिए हैं लेकिन जो 9 करोड़ रु0 का अन्तर आ गया है, क्या मंत्री जी उसको पूरा करने का वायदा करते हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय, जिला ऊना में पी.डब्ल्यू.डी. के तीन मण्डल हैं और उसमें आठ सब डिविज़न हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने विस्तृत सूचना दी है जिसमें ऊना उप-मण्डल है, मैंहतपुर उप-मण्डल है, हरोली उप-

मण्डल है, बंगाणा उप-मण्डल है, जोल उपमण्डल है और भरवाईं उप-मण्डल है, गगरेट उप-मण्डल है और अम्ब उप-मण्डल है।

16.03.2017/1130/केएस/एएस/3

अगर हम इन तीन-चार सालों का देखें तो भरवाईं उप-मण्डल में 6 करोड़ 50 लाख 82 हजार खर्च हुआ है। गगरेट उप-मण्डल में 11 करोड़ 33 लाख 32 हजार खर्च हुआ है, अम्ब उप-मण्डल में 6 करोड़ 50 लाख 84 हजार रु0 खर्च हुए हैं। इस तरीके से जो गगरेट उप-मण्डल है, उसमें 11 लाख 33 हजार रु0 खर्च हुए हैं । जितना भी यह मेंटिनैंस का पैसा है, यह नुकसान के मुताबिक होता है। बरसात में नुकसान हो जाए, बाढ़ आ जाए या

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

16.3.2017/1135/av/as/1

प्रश्न संख्या : 3845---------- क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (प्राधिकृत) -------- जारी

कोई डंगे गिर जाए तो उसके अनुसार एस0डी0ओ0 एक्सियन को जो रिपोर्ट भेजता है या फिर आगे एक्सियन एस0ई0 को भेजता है उसके मुताबिक उसकी मैंटीनेंस का बंटवारा किया जाता है। अगर माननीय सदस्य के हिसाब से कुछ कमी रही गई है तो हम विभाग को कहेंगे कि उस कमी को पूरा किया जाए।

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, जैसे मंत्री जी ने कहा कि यह बंटवारा ज्यादा बारिश या ज्यादा नुकसान होने के मुताबिक किया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि चिंतपूर्णी तो लाहौल-स्पिति में नहीं है और गगरेट भी पाकिस्तान में नहीं है। अगर बारिश गगरेट में होती है तो लगभग चिन्तपूर्णी में भी होती है। चिन्तपूर्णी में तीन उप मण्डल आते हैं वहां पर बुल्डोजर और जे0सी0बी0 इत्यादि लगी रहती है। साथ में, मैंटीनेंस का सारा पैसा भी वहां लगा रहता है। कुछ लोग वहां यह बात फैलाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि इसकी तो मुख्य मंत्री से बनती ही नहीं है आप यहां काम करो। वहां पर जो इस प्रकार की

अनियमितता हो रही है तो मेहरबानी करके आप मेरे साथ भी न्याय कीजिए। मैंने इस बारे में मुख्य मंत्री जी को बहुत सारे पत्र लिखे हैं। जैसे कर्नल जी ने मुझे पत्र लिखा है कि Kalia Ji, you are less efficient than Shri Kanwar, तो ऐसी बातें मेरे ऊपर न आए क्योंकि चुनाव का साल है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है मैं उसके लिए आपका आभारी भी हूं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ऊना जिला में गत चार वर्षों में सड़कों के रख-रखाव एवं मुरम्मत हेतु लोक निर्माण विभाग को कुल 74,54,6000/- रुपये की धनराशि आबंटित की गई है जिसका ब्यौरा सब डिविजन वाईज दिया गया है। अगर डिविजन वाइज बात करें तो भरवाईं मण्डल में 24,34,98,000/- रुपये की राशि खर्च की गई है। बंगाणा मंडल में 16.51 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। ऊना मण्डल में 33,67,40,000/- रुपये मैंटीनैंस और सड़कों के रख-रखाव पर खर्च किए गये हैं। फिर भी अगर माननीय सदस्य को कोई परेशानी होगी तो उस कमी को भी पूरा करेंगे।

समाप्त

16.3.2017/1135/av/as/2

प्रश्न संख्या : 3846

श्री गुलाब सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह जो महत्वाकांक्षी 'जायका' परियोजना है इसका एग्रीमैंट पिछली धूमल सरकार के समय में हुआ था। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसके मेन फीचर्स क्या हैं? आपने जिन 9 परियोजनाओं का ब्यौरा दिया है इसमें तो आपने सिर्फ पाइपें ले की हैं या पानी के कुछ हैंड पम्प लगाये हैं। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है जबकि आपने अपने जवाब में कहा है कि ये सभी साथ-के-साथ कम्पलीट हो गई है जबकि ये अभी सारी-की-सारी अधूरी है। यह एक बहुत बड़ा प्रोजैक्ट आया हुआ है। इस प्रोजैक्ट का मुख्य उद्देश्य डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रिकल्चर क्रोप्स की तरफ ध्यान देना है, सिर्फ पाइपें बिछाकर के तो यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यहां पर प्रश्न करके यही चीज साबित करना चाहते थे कि यह स्कीम धूमल साहब के समय में चली है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह स्कीम उसी समय से चली है और अभी भी चालू है। यह परियोजना कुल 321 करोड़ रुपये की है और इसका पीरियड वर्ष 2011 से 2018 तक है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मण्डी यानि कुल 5 जिलों में शुरू की है तथा इसकी टोटल स्कीम 210 हैं।

श्री वर्मा द्वारा जारी

16/03/2017/1140/टी0सी0वी0/डी0सी0/1
प्रश्न संख्याः 3846 ..... क्रमागत

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एंव ऊर्जा मंत्री ..... जारी।

इनमें से 150 कंप्लीट हो चुकी हैं और 60 स्कीम्ज़ अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। इसी तरह से मण्डी में टोटल 62 स्कीम्ज़ हैं। क्रॉप डाईवर्सिफिकेशन हम उसी इलाके में कर सकते हैं जहां इरीगेशन का प्रावधान हों। आपकी स्कीमें ओपन चैनल की हैं, शायद वहां पर पाइपें नहीं बिछी हुई हैं। अगर ये स्कीमें अधूरी हैं, तो उनको पूरा किया जायेगा। मैं इसकी इंक्वायरी कर लेता हूं और इनको कंप्लीट करेंगे।

16/03/2017/1140/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

प्रश्न संख्याः 3847

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो सूचना सभापटल पर रखी है, उसके अनुसार ठियोग-खडापत्थर-हाटकोटी-रोहडू सड़क के निर्माण हेतु 322.76 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत हुई हैं। इसमें दिनांक 15 फरवरी, 2017 तक 250.28 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है और इस कार्य को 30

जून, 2017 तक पूर्ण कर लिया जाएगा दर्शाया गया है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि यदि यह कार्य 30 जून, 2017 तक पूर्ण नहीं होता है, तो क्या इस कार्य को पूर्ण करने के लिए समय और बढ़ाया जाएगा?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय, हर साल संभव कोशिश की जाएगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और काफी समय से ये लटकी हुई है। इसके 2 बार टेंडर करने पड़े और वर्ल्ड बैंक की सहायता से इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये सड़क 2 हिस्सों में बांटी गई है। पहला हिस्सा - ठियोग-कोटखाई-खड़ापत्थर, जो लगभग 48 किलोमीटर हैं। इसमें 18.500 किलोमीटर सड़क के कटान का प्रावधान है, जिसमें से 17.750 कि0मी0 सड़क का कार्य कंप्लीट हो चुका है और 710 मीटर बकाया है। इसमें टारिंग का काम 48 कि0मी0 में से लगभग 36 कि0मी0 पूरा हो चुका है। इस सड़क में 218 पुलियों का निर्माण किया जाना था जिनमें से 31 पुलियों का काम कंप्लीट हो चुका है और 56 पुलियों का निर्माण कार्य युद्व स्तर पर चला हुआ है। इसमें 7 पुल बनने हैं, जिनमें से एक पुल का निर्माण कंप्लीट हो चुका है और 4 पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अध्यक्ष महोदय, इसका दूसरा हिस्सा- खड़ापत्थर-हाटकोटी-रोहडू सड़क हैं। इस सड़क की लम्बाई 32.684 कि0मी0 है और इसमें सड़क का कटान 25 कि0मी0 होना था लेकिन इसमें 25.904 कि0मी0 कटान हो चुका है और 130 मीटर कटान होना बकाया है। इस सड़क में टारिंग 32.684 कि0मी0 में होनी थी, जिसमें से 28.273 कि0मी0 पर टारिंग कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें 125 पुलियों का निर्माण होना था जिनमें से 109 कंप्लीट हो चुकी हैं और 12 पुलियों का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। इसके अलावा 5 पुल बनाये जाने थे और 5 पुलों का काम प्रगति पर है। जो ठेकेदार इन कार्य को कर रहे हैं, उनको हिदायत जारी कर दी गई है कि ये काम हर हालत में 30 जून 2017 तक पूरा हो जाना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि वर्ल्ड बैंक ने हमें जो लोन दिया था, उसमें हमारी लगभग 90 करोड़ की सेविंग भी हो रही है।

16/03/2017/1140/टी0सी0वी0/डी0सी0/3

प्रश्न संख्याः 3848

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भाग "क" में आपने कहा है कि 13वें वित्तायोग की धनराशि उपलब्ध करवाई गई थी। प्रदेश में यह कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई गई थी? इसके "ख" भाग में आपने सूची प्रदान की है कि

श्रीमती एन0एस0 ..... द्वारा जारी

16/03/2017/1145/ एन0एस0/डी0सी0 /1

प्रश्न संख्याः 3848 -- क्रमागत

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर ----- जारी

13वें वित्त आयोग का पैसा जो खर्च नहीं हुआ है। आपने इसका कुल टोटल 15 करोड़ 37 लाख 60 हजार 194 रूपये की राशि दी है। तीसरा, हमने कहा था कि ग्राम पंचायतों से पैसा वापिस मांगा जा रहा है। इसके जवाब में आपने कहा है कि जी नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वास्तविकता यह है कि विकास खंडों के द्वारा जो राशि खर्च नहीं की गई है और हमने पंचायतों के सेक्रेटरी और बी0डी0ओ0 को लिख करके चिट्ठी दी है। कई पंचायतों ने पैसा वापिस भी किया है और कई पंचायतों को अभी देने को शेष है। लेकिन उनको पैसा वापिस करने के लिए प्रैशराईज किया जा रहा है। आपने यह भी कहा है कि उस पैसे को स्थायी सम्पत्तियों के निर्माण हेतु खर्च किया जाएगा। मंत्री महोदय यह बताने की कृपा भी करें कि ये स्थायी सम्पत्तियां कौन-सी हो सकती हैं? जो धनराशि वापिस हुई है, क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि उसी ग्राम पंचायत को वापिस की जाएगी और जिस कार्य के लिए ये राशि दी गई थी उसी कार्य में खर्च की जाएगी? दूसरा, जिन ग्राम पंचायतों ने राशि वापिस नहीं लौटाई है, उनको वापिस करने के लिए प्रैशराईज नहीं किया जाएगा?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 13वें वित्त आयोग के ऊपर वर्ष 2009 का शेयर लेकर 2014-15 तक लगभग 539 करोड़ रूपया प्राप्त हुआ था। 539 करोड़ में से 347 करोड़ रूपये की जनरल ग्रांट आई थी। मैं माननीय सदस्य के ध्यान

में लाना चाहता हूं कि 152 करोड़ रूपये परफोरमैंस ग्रांट आई थी। परफोरमैंस ग्रांट स्टेट के ऊपर निर्भर करती थी कि उसको स्टेट कहां खर्च करे। हमने उसके लिए उसी वक्त आदेश दिए कि जैसे हमारी जनरल ग्रांट आई थी ,उसको भी उसी प्रपोरशनेट में सभी जिलों में बांट दिया जाए। प्रपोरशनेट में 50 प्रतिशत जिला परिषद, 30 प्रतिशत पंचायत समिति और 20 प्रतिशत ग्राम पंचायत के लिए दिया गया। पीछे यहां पर एक प्रश्न आया कि बहुत सी पंचायतों का पैसा विकास खंडों में अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। यदि अनयूटिलाइज पैसा पड़ा हुआ है तो आप अपने विधान सभा क्षेत्र की स्कीमें देखें तब आपको पता चलेगा कि कहीं पर 20,000 और कहीं पर 30,000 रूपये की राशि दी गई है। क्या पंचायत के अंदर 20,000 और 30,000 रूपये में कोई स्कीमें बन सकती है? जिस

16/03/2017/1145/ एन0एस0/डी0सी0 /2

तरीके से पैसा बांटा गया है उससे वह इनफरास्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। इसलिए विभाग ने यह आदेश दिए कि वह पैसा दोबारा से डी0पी0ओ0 के पास आए और उसको कन्सालिडेट करने के बाद उन्हीं की अनुशंसा पर एस्टिमेट के साथ पैसा आए। कई जगहों पर पैसा एफ0सी0ए0 की वजह और कहीं किसी डिसप्यूट के कारण ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस वजह से पैसा कई जगहों पर यूटिलाइज नहीं हुआ है। आप इनफरास्ट्रक्चर बनाने की बात कह रहे हैं तो उसके लिए हमने कहा है कि जो हमारे पास परफोरमैंस ग्रांट आई थी उसमें से कुछ पैसा बचा हुआ है और इस पैसे से पंचायत घर, जिला परिषद भवन बन सकते हैं। परन्तु अभी तक हमने डी0पी0ओ0 को आदेश दिए हैं और वे अनुशंसा मांग रहे हैं तथा उसके बाद ही हम इस पैसे को आबंटन करेंगे।

Speaker: One more supplementary only.

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो लिखित में उत्तर दिया है। उसमें इन्होंने कहा है कि हम राशि को वापिस नहीं मांग रहे हैं और इसके जवाब में इन्होंने लिखा है, जी नहीं। अब जो लिखित में दिया है वह सही है या फिर जो ये जुबानी कह रहे हैं, वह सही है। मैंने जिला परिषद और विकास खंडों के बारे में नहीं पूछा है, केवल मात्र ग्राम पंचायतों का ही पूछा है। आपने लिखित उत्तर में कहा है 'नहीं'। दूसरा, प्रदेश में कुछ विकास खंड ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरी राशि खर्च कर दी है। मैं अभी नग्गर विकास खंड

में 47 लाख के लगभग राशि खर्च नहीं हुई है और नग्गर विकास खंड में ही यानि कुल्लू जिला में

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

16/03/2017/1150/RKS/AG/1

प्रश्न संख्याः 3848... जारी

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर...जारी

ही 20 लाख रुपये की धनराशि खर्च नहीं हुई है। धनराशि खर्च नहीं होना क्या सरकारी अधिकारियों की गलती है या ग्राम पंचायतों की गलती है? कुल्लू जिला के निरमंड विकास खंड द्वारा सारी-की-सारी राशि खर्च की गई है। आपने यह हिसाब दिया है कि वहां पर कोई भी अनसपेंट धन नहीं है। जिन विकास खंडो में इतनी भारी राशि अनसपेंट पड़ी हुई है, क्या सरकार उसके लिए कोई जिम्मेदारी तय करेगी? मेरा आपसे निवेदन है कि जो धनराशि पंचायतों में शेष है, उस धनराशि को आप वापस न मांगे। दूसरा, जो पैसा जिस कार्य के लिए दिया था, उन्हीं कामों पर वह पैसा खर्च किया जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पंचायत में ब्लॉक स्तर पर जो पैसा पड़ा होता है, जो 13 वें वित्तायोग का पैसा था, उस पैसे को युटिलाइज करने के बारे में हमने कहा है। क्योंकि मार्च, 2016 में 13वें वित्तायोग का प्रोजैक्ट बंद हो रहा था। इस पैसे को युटिलाइज करने के लिए हमने अनुशंसा मांगी थी। जिस ब्लॉक में पैसा युटिलाइज कर दिया गया, जैसे आप निरमंड ब्लॉक का शून्य बता रहे हैं परन्तु जो पैसा जिस ब्लॉक का है, वह उसी ब्लॉक में युटिलाइज करेंगे। पंचायत पैसे का आवंटन करती है और वह पैसा अनयुटिलाइज न रह जाए। इसके लिए अनुशंसा मांगी जा रही है। इस मंशा को देखते हुए उस पैसे को हमने इस तरीके से आवंटन करने का प्रयास किया है।

16/03/2017/1150/RKS/AG/2

<u>प्रश्न संख्याः 3849</u>

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना दी है उसमें इस समयावधि में मंत्रियों, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अधिकारियों के सरकारी मकानों की मरम्मत के लिए एक साल के भीतर 517.34 लाख रुपये से अधिक का खर्चा दर्शाया है। लेकिन जो क्लास थ्री और क्लास फोर कर्मचारी हैं उनके मकान जर्जर हो चुके हैं। उनके मकानों की छतें इस बार के तुफान में उड़ चुकी हैं। उन मकानों पर बहुत कम खर्चा सरकार द्वारा किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो आप मंत्रियों वगैरह के मकान में लेविश खर्चे कर रहे हैं क्या उनके स्थान पर क्लास थ्री और क्लास फोर कर्मचारियों के सरकारी मकानों में मरम्मत पर ज्यादा खर्चा करेंगे? दूसरा, जो क्लास थ्री और क्लास फोर कर्मचारियों के लिए शिमला में भवनो का निर्माण होना था, क्या आप उन मकानों को बनाने का प्रयास करेंगे? एलर्जली का ब्लॉक नं0-9 जो गिरा हुआ है, जिसके लिए बजट में पैसे का प्रोविजन भी किया हुआ था और माननीय धूमल जी ने इसका शिलान्यास किया था। क्या आप इन शिलान्यास हुए मकानों को बनाने के बारे में भी प्रयास करेंगे, ताकि जिन कर्मचारियों के पास भवन नहीं है उनको भवन मिल सके?

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

Health & Family Welfare Minister(Authorised): Mr. Speaker, Sir, he has asked for the information from 1st January, 2013 to 15th February, 2015. The total expenditure incurred is Rs. 9,30,76,000/-, which has been made by the PWD on the repair and maintenance of Government houses. The breakup is as under: - Ministers houses - Rs. 1,32,93,000/-; Chairman & Vice Chairman houses - Rs. 38,89,000/-; officers houses - Rs. 3,45,52,000/-; and Class-III & IV employees houses - Rs. 4,13,42,000/-. So your contention that on the houses of Ministers you have spent more and on the houses of Class-III & -IV you have spent less, I would like to tell you that we have spent Rs. 4.13 crores on the houses of Class-III & IV. So far as the construction of houses of Class-I & II are concerned, we have constructed eight houses as Type-I and eight quarters of Type-II in Nabha at the total cost of Rs. 2,06,91,000/- only. So your contention that you have spent more on the houses of Ministers and officers is not true.

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर के अनुसार 5.17 करोड़ रुपया मिनिस्टर्ज़, वाईस चेयरमैन और ऑफिसर्ज़ के हाउसिज के पर ख़र्च हुआ है और आपने कहा कि 4.13 करोड़ रुपया क्लास-3 और क्लास-4 कर्मचारियों के मकानों की मुरम्मत पर ख़र्चा किया गया है। मेरा कहना यह है कि जिन मकानों की मुरम्मत करने की ज़रूरत भी नहीं है, उनके ऊपर तो ख़र्चा आप 5.00 करोड़ रुपये से ज्यादा कर रहे हैं लेकिन जो शिमला में छोटे कर्मचारियों के ज्यादा मकान है, जो टूटे हुए हैं, जो मकान अंग्रेजों के समय के बने थे, जिन मकानों की छतें टूट गई हैं, उन मकानों में कोई काम नहीं हो रहा है, क्या आप उन मकानों के ऊपर और अधिक पैसा ख़र्च करने का प्रावधान करेंगे? जो 8 ब्लॉक्स आप नाभा में बना रहे हैं, क्या यह सत्य नहीं है कि वर्ष 2012 से पहले के जो 52 ब्लॉक्स बनने थे, यह उनमें से ही बचे हुए 8 ब्लॉक्स हैं जो अब बन रहे हैं? जो ब्लॉक एलर्ज़ली में बनना था, उसको तो आप छेड़ ही नहीं रहे हैं। आपने वहां का पैसा कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया है। क्या यह सही है?

16.03.2017/1155/SLS-AG-2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रह हैं कि 5.17 करोड़ रुपया ख़र्च किया गया on the residences of Ministers, Chairman and Vice-Chairman of corporations & boards and all officers who are locating at Shimla. We have spent Rs. 4,13,42,000/- for the repair and maintenance of Class-III & IV houses. So, the Government is very much concerned about the Class-III & IV employees and will say that they must be provided comfortable and better accommodation by giving proper repair and maintenance after interval. We have constructed 16 houses for Class-III & IV - eight Type-I houses and eight Type-II houses - costing about Rs. 2.06 crores. So, the process is still going on. We have not stopped the process. Wherever there would be requirement of course the Government will construct new houses for Class-III & IV employees subject to the availability of funds.

प्रोफ़ेसर प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी शब्दजाल में उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्य का प्रश्न था कि क्या आप बताएंगे कि मंत्रियों, चेयरमैन, वाईस चेयरमैन और ऑफिसर्ज़ के लिए बने रैजिडैंसिज की संख्या कितनी-कितनी है तथा क्लास-3 और क्लास-4 के लिए बने रैजिडैंसिज की संख्या कितनी है। सवाल यह है कि आप दोनों का अनुपात देखिए। इनकी संख्या में बहुत अंतर हैं और उस अनुपात से छोटे कर्मचारियों के रैजिडैंसिज पर बहुत कम पैसा ख़र्च हो रहा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिए विस्तृत तौर पर कहा है कि जो मिनिस्टर्ज़, चेयरमैन, वाईस चेयरमैन, चीफ सैक्रेटरी, एडिशनल चीफ सैक्रेटरीज या ऑफिसर्ज़ हैं, उनके टाईप-5 और टाईप-6 हाउसिज होते हैं जो कि बड़े हाउसिज होते हैं और उनकी मेंटेनैंस पर ख़र्चा भी ज्यादा होता है। जब सरकारें बदलती हैं तो नेचुरली इन हाउसिज में पेंट होता है, डिसटैंपर होता है और फर्निचर को चेंज करने की भी ज़रूरत पड़ती है। हम क्लास-3 और क्लास-4 कर्मचारी के हितों की पूरी रक्षा कर रहे हैं।

जारी ..श्री गर्ग जी द्वारा

16/03/2017/1200/RG/AS/1

प्रश्न सं.3849-- क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री---जारी

और हमारे सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों का कम्फर्ट देखना सरकार का काम है। हमारी सरकार निश्चित तौर पर सबका ध्यान रखती है। इसलिए जो खर्च किया गया है वह उसी अनुपात में खर्च हुआ है।

प्रश्नकाल समाप्त

16/03/2017/1200/RG/AS/2

<u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

अध्यक्ष : अब कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे। माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जे0पी0 सूचना प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 के खण्ड 18 के प्रावधानों के अन्तर्गत जे0पी0 विश्वविद्यालय, वाकनाघाट का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बीज़ अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज़ एवं जैविक उत्पादन

प्रमाणीकरण अभिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् का वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

16/03/2017/1200/RG/AS/3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे । अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :

i. समिति का **169वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 153वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है; और
ii. समिति का **170वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 154वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्री संजय रतन, सदस्य, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री संजय रतनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति का **68वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2012 में इंगित ऑडिट पैरों की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश कृषि पैकेजिंग इंडिया सीमित** से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

16/03/2017/1200/RG/AS/4

अध्यक्ष : अब श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

i. समिति का **20वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **परिवहन विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और
ii. समिति के **49वें मूल प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) (वर्ष 2006-07) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बने 24वें कार्रवाई प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

16/03/2017/1200/RG/AS/5

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए बजट अनुमान

सामान्य चर्चा

अध्यक्ष : अब वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमान पर सामान्य चर्चा होगी और वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों व वार्षिक वित्तीय विवरण पर आगे चर्चा का आरम्भ होगा। मेरे पास जो सूची आई है उसके अनुसार बहुत सारे वक्ता इस पर बोलने वाले हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि समय-सीमा में रहकर अपनी बात रखें। क्योंकि यह कोई जरूरी नहीं है कि पांच बजे के बाद सदन के समय से आगे जाकर चर्चा की जाए। ऐसा कभी ऐक्सैप्शनल केसिज़ में होता है। आज बोलने वाले लगभग 15 माननीय सदस्य हैं। यदि 10-10 मिनट बोलेंगे, तो ठीक रहेगा। अगर कोई बोलने से नहीं मानेगा, तो मैं उसका भाषण रिकॉर्ड नहीं कराऊंगा।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, पिछले चार साल तो हमें बोलने का मौका नहीं मिला और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी बोलने का मौका नहीं मिला। इसलिए अब तो हमें बोलने का समय दिया जाए और आज ही बोलना है, तो आज तो कम-से-कम कुछ कंसीडर करें।

अध्यक्ष : बोलिए, खूब बोलिए, बोलने से हम मना नहीं करते, लेकिन यह सोच लीजिए कि अगर ज्यादा बोलेंगे, तो दूसरे का समय आप लेंगे। जो समय ज्यादा लेगा, फिर दूसरे सदस्य का टाईम कट जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कल शुक्रवार है और लोगों ने जाना भी है। इसलिए ज्यादातर चर्चा आज ही कर लें। जितना होता है आज ही कर लें और आज शाम थोड़ी देर तक बैठ लेंगे क्योंकि कल लोगों ने जाना भी है।

एम.एस. द्वारा अध्यक्ष महोदय शुरू

16/03/2017/1205/MS/AS/1

अध्यक्ष : अब चर्चा में श्री नन्द लाल(मुख्य संसदीय सचिव) भाग लेंगे।

श्री नन्द लाल(मुख्य संसदीय सचिव): अध्यक्ष महोदय, 10 मार्च, 2017 को इस मान्य सदन में जो बजट अनुमान वर्ष 2017-18 के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किए हैं, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष जी, यह जो वर्ष 2017-18 का बजट है, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट है। हम सब जानते हैं कि यह बजट बड़ा डिटेल्ड/इलेबोरेटिड है। इसमें हरेक ऐस्पैक्ट को अच्छी तरह से समझा गया है और बताया गया है। यह माननीय मुख्य मंत्री जी का 20वां बजट है जो लगभग साढ़े चार घण्टे में यहां पढ़ा गया और यह एक रिकॉर्ड है। अध्यक्ष जी, इस बजट से हम समझते हैं कि समाज के हर वर्ग को फायदा हुआ है। वे चाहे विद्यार्थी, कृषक, बागवान, बेरोजगार नौजवान या इण्डस्ट्री से जुड़े हुए लोग हों। इस बजट में सबसे बड़ी बात यह है कि यह बजट टैक्स फ्री होने के साथ-साथ जो आम आदमी की जरूरत है कि उसके घर का चूल्हा जले, महंगाई न बढ़े और बहुत ज्यादा टैक्सिज न डाले जाएं, उस तरह का है। इस बजट का यह एक सबसे अहम ऐस्पैक्ट रहा है। उसके लिए हम मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहेंगे।

मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत बधाई है कि इन्होंने इस टर्म के पिछले जो चार बजट पढ़े, जैसा मैंने कहा कि यह बजट ऐतिहासिक बजट है, इस बात को हमें नहीं भूलना होगा। इसके बावजूद the Government of Himachal Pradesh is in financial constraints. इसमें अपने बहुत ही कम रिसोर्सिज के साथ चलते हुए जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने काम किया, वह अद्भूत है। यह भी हम जानते हैं कि इतनी लायबिलिटीज होने के बावजूद हालांकि ये लायबिलिटीज दो, तीन या चार साल की नहीं है Liabilities are piled up for years together. ये विरासत में मिली हुई हैं। इन लायबिलिटीज को जानते हुए फिर जिस तरह से प्रूडेंट फाइनैंशियल मैनेजमैंट इन्होंने दिखाया है, उसके लिए हम इनको बधाई देना चाहते हैं।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

16/03/2017/1205/MS/AS/2

इसमें एक सबसे अहम ऐस्पैक्ट यह है कि हमारे जो रिसोर्सिज का जनरेशन और रेवेन्यु का जनरेशन है उसको इन्होंने इसमें बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करके रखा है। ठीक है लायबिलिटीज हैं जिनमें कोई लॉग पेमैंट्स या रिपेमैंट्स हैं लेकिन सबको ध्यान में रखते हुए जो इनका रिसोर्सिज मैनेजमैंट है और जो रेवेन्यु अरेंज किया है, उसके लिए भी ये बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष जी, we all know that the Budget is an estimate of Revenue Receipts and Expenditure occurred. तो हमेशा देखा जाता है कि हमारे रेवेन्यु कहां से आ रहे हैं और हमारा खर्चा कैसे होता है। इस बजट पर जब डिबेट हुई तो हमने देखा कि खाली आलोचना के सिवाय we thought that we will get good inputs for the development of resources towards the revenue receipts in side. We will get some better inputs to suggest how to go for the allocation of funds in the various schemes. परन्तु पिछले तीन दिन से जो चर्चा यहां चल रही है उसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा। उसमें कोई सुझाव या सुधार की बात नहीं देखी। अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि शायद विपक्ष की मजबूरी भी है कि उनको बजट पर कुछ कहना होता है। They know it well that what all is happened. पिछले चार साल में जिस तरह का विकास हुआ है, जिस तरह के काम हुए हैं, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर देखिए, एजुकेशन का फील्ड देखिये या हैल्थ का फील्ड देखिये, हर फील्ड में बहुत ही अद्भूत विकास हुआ है। इसलिए जब ये बजट में देखते हैं क्योंकि

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

16.03.2017/1210/जेके/डीसी/1

श्री नंद लालः----**जारी**-----

बजट में वह भी दिया हुआ है। What the Government has done in the last four years, वह भी दिया हुआ है और 2017-18 का बजट है, what is proposed there यह पढ़ने में थोड़ी तकलीफ जरूर रहती है। इसमें एक बड़ी चीज जो मुझे नज़र आई It is only a fault finding exercise कि यह नहीं हुआ वह नहीं हुआ। जैसे कि मैं आपको

बताऊं कि पीछे जो स्कूल खुले, कॉलेज खुले और स्वास्थ्य संस्थान खुले उस पर एक ही राय विपक्ष की तरफ से है कि वहां पर स्कूल में टीचर्ज नहीं है इसलिए स्कूल नहीं खुलने चाहिए। कॉलेज में टीचर्ज नहीं है और कॉलेजिज़ नहीं खुलने चाहिए। मैं यह समझता हूं कि जो लोग सरकार में रहे हुए हैं उनको तो यह बात मालूम है कि why this gap is there? हमारा उद्देश्य है कि it is a welfare State, शिक्षा को हमने गांव-गांव तक पहुंचाना है। हर आदमी का, we talk about Right to Education, सरकार का फर्ज़ बनता है कि शिक्षा को वहां तक पहुंचाना है। स्वास्थ्य संस्थान हैं, दूर-दराज के जो लोग हैं, in the remote areas अगर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उससे वंचित रहें then it is not a welfare State. इस बात पर मुझे यह कहना है कि लोग जानते हैं कि ये जो वेकेंसिज हैं ये कैसे क्रिएट होगी? जब आप नए स्कूल खोलेंगे, नये कॉलेजिज़ खोलेंगे, अपग्रेड करेंगे there will be regular process of enrollment, रिक्रूटमैंट चल रहा है। But still there is a shortfall, यह शॉर्ट फॉल होना लाज़मी है। कोई भी संस्थान, कोई भी सैट अप ऐसा नहीं होगा जहां पर 100 प्रतिशत वेकैंसिज भरी होती है। सरकार के प्रयास से लग रहा है कि उसमें एक हजार से ऊपर एजुकेशन में लोग एन्रोल हो चुके हैं। नये भर्ती कर चुके हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि लोगों की हर डिपार्टमैंट में रिटायरमैंट भी होती है वह जो रिटायरमैंट है उसकी वजह से भी तो वेकैंसिज होती है, then those vacancies are filled later. जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने different departments में 19 हजार नौकरियां देने का वायदा किया है उससे क्या होगा ये जो कमी है उसको रोका जाएगा ताकि हमारे लोग उसमें आए। बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले और जो हमारी वेकैंसिज हैं वे भी पूरी हो जाएगी। फिर एक बात यह भी की गई कि घोषणाओं की सरकार है। एक सिम्पल सी बात है जैसे कि मैंने कहा there is a need to take education to the remotest part of the State

16.03.2017/1210/जेके/डीसी/2

स्वास्थ्य संस्थाएं भी वहां जानी चाहिए, आई0टी0आई0 कॉलेजिज़ वहां जाने चाहिए और इंजीनियर कॉलेजिज़ भी वहां पर जाने चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वह सब कुछ किया। that is also in the remote area खास करके जो कॉलेजिज़ हैं, कॉलेजिज ऐसी-ऐसी जगह में खुलें जहां गर्ल्ज एजुकेशन में फायदा हुआ, गर्ल्ज एजुकेशन में इज़ाफा हुआ

और जो हमारे गरीब लोग थे जो बाहर शहरों में नहीं जाते थे उनको घर में ही कॉलेजिज़ की सुविधा मिली। यह एक बहुत बड़ी बात है। मैं यह कहना चाहूंगा कि घोषणाओं की जब बात होती है जब माननीय मुख्य मंत्री जी अपने प्रदेश के अन्दर दौरे में होते हैं वह जहां पर जाते हैं, लोग उनके आगे अपनी मांग रखते हैं कि हमकों इस एरिया में क्योंकि यह इतना बड़ा एरिया है number of children इतने है इसलिए हमें यहां पर स्कूल चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी उनकी मांग को पूरा करते हैं। वे स्वास्थ्य संस्थान की मांग करते हैं कि प्राईमरी हैल्थ सेन्टर चाहिए। जब प्राईमरी हैल्थ सेन्टर की लोग मांग करेंगे, ऐसा नहीं कि वह वहीं पर अनाऊंस हो जाता है और वहीं पर सब कुछ हो जाता है उसकी सरकार एक फिजिबिल्टी रिपोर्ट बनाती है, उसके कुछ पैरामीटर्ज़ हैं and on the basis and on those parameters अपग्रेडेशन है, चाहे opening of new schools, institutions है। उस तरह से होता है। इसलिए घोषणाओं की सरकार कहना तर्कसंगत बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर थोड़ी सी चीजें गिनाना चाहूंगा कि पिछले चार सालों के अन्दर 14 नए सब डिविजन बनें, 10 तहसीलें बनी और 31 सब तहसीलें खोली गई। हम लोग उनको जा करके पूछें कि जिस एरिया में ये नये सब डिविजन खुले, जिस एरिया में तहसीलें व सब तहसीलें खुलीं उनको अपने काम में कितना फायदा मिला। यह उनसे जा कर पूछें यहां पर हमारे कहने से और यहां बैठ कर हम यह कहें कि यह खोलने से यह हुआ और वह खोलने से यह हुआ। because of the resources आज जो इतने सब डिविजन्ज खुलें हैं, इतनी जो तहसीलें व सब तहसीलें खुली हैं इससे लोगों के अपने काम घर बैठे हो रहे हैं। इसको नकारना मैं समझता हूं कि अच्छी बात नहीं है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

16.03.2017/1215/SS-DC/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री नन्द लाल) क्रमागतः

जैसे नये मेडिकल कॉलेजिज़ खुले, अभी देखिये, बड़ा ज़िक्र हो रहा है। यह सरकार का प्रयास है। नाहन, चम्बा और हमीरपुर कॉलेजिज़ खुले हैं उसके लिए भी हम माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। एक तो ऑलरेडी फंक्शनल हैं और दो के लिए भी

प्रोसैस चला हुआ है। यह बहुत बड़ी बात हो रही है। ई0एस0आई0सी0 हॉस्पिटल जो नेरचौंक, मंडी में है it has been taken over and it is a good thing. 21 सिविल हॉस्पिटल बने, 34 सी0एच0सीज़0 बनीं, 96 पी0एच0सीज़0 बनीं, 29 हैल्थ सब-सैंटर्ज़ खुले, 45 आयुर्वैदिक हैल्थ सैंटर्ज़ खुले। इस प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल के अंदर बहुत काम हुआ, यह जग-जाहिर है। पूरे हिमाचल के लोग इस बात को जानते हैं। People have been benefited. हैल्थ सर्विसिज़ में बहुत अच्छा काम हुआ।

इसी तरह से हमने स्कूलों की ऑलरेडी बात कर ली है। इंजीनियरिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, पॉलिटैक्निक कॉलेज है। इसी तरह से आई0आई0एम0, आई0आई0टी0 जैसे इंस्ट्यिूट हैं it is a big thing that how it has been taken up and we got it finally मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बहुत बात थी कि हम लोग लाइबिलिटी में हैं। हम लोग लोन के नीचे हैं। हम लोगों के रिसोर्सिज़ सब कुछ होते हुए कम हैं। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है Prudent Financial Management. यह बिल्कुल सही लिखा है। यह सब जानते हुए भी कि किस तरह उन्होंने विभिन्न स्कीमों और सैक्टर में बजट को एलोकेट किया हुआ है, इस बात के लिए हम उनकी तारीफ करना चाहेंगे। जब बजट पेश होता है तो लोगों को उम्मीद होती है कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर में उनको क्या-क्या मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ इस साल भी हिमाचल के लोगों को मालूम था कि माननीय मुख्य मंत्री अपना 20वां बजट पेश कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर कुछ-न-कुछ उनके लिए होगा। अब वह आपके सामने है। अब लोगों में एक फेथ बन चुका है। am telling you today लोगों में एक विश्वास बन चुका है कि माननीय मुख्य मंत्री, वीरभद्र सिंह जी की विकास के लिए क्या सोच है, क्या विज़न है, उसमें कोई दो राय नहीं हैं। इसीलिए कुछ लोग जो यह कहते हैं कि आप इधर आयेंगे और हम उधर जायेंगे तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि

16.03.2017/1215/SS-DC/2

ये जो सरकार के काम हैं इसको हिमाचल के सभी लोग देख रहे हैं और जो हम अंदर बैठकर निगेट करते हैं it is damaging us rather क्योंकि लोगों को पता है और

डैफिनेटली जिस तरह का डिस्कशन चल रहा है, मुझे विश्वास है कि इसका विपरीत इम्पैक्ट हिमाचल के लोगों पर होगा। वह देखेंगे कि अच्छे कामों के लिए भी सरकार को कोसा जाता है। हिमाचल के लोग इस बात पर रोष ज़रूर दिखायेंगे।

एजुकेशन के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि the illiteracy rate has reached 82.80% and the enrolment and quality of education of children, in the age group of 4-16, is number one in the Country. It is a matter of pride for all of us. और जिस तरह बोला जाता है कि स्कूल में टीचर नहीं हैं तो बहुत ही बौखलाहट दर्शाता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि we should not forget that आपके समय में, जो पिछली सरकार थी क्या उस समय सब ठीक था? हम डिटेल में नहीं जायेंगे, सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि क्या उस वक्त सब ठीक था? जो आज हर बात के लिए सरकार को कहा जाता है। इसीलिए जो सरकार की प्रायोरिटी है that is Education and Health. इस साल भी वित्तीय वर्ष में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने शिक्षा के क्षेत्र में 6204 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया है। टेक्निकल एजुकेशन के लिए अलग से 220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, हिमाचल के लोग उसके लिए धन्यवाद करेंगे।

हैल्थ में भी मैं ज्यादा न कहता हुआ इतना ही कहना चाहूंगा कि Health expenditure as per percentage of GSDP is 1.43% which is the second highest in the Country after Delhi. जो Infant Mortality रेट है has been reduced from 35 to 28 per thousand live births इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट में 1,720 करोड़ रुपया रखा हुआ है।

जारी श्रीमती के0एस0

16.03.2017/1220/केएस/एजी/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री नन्द लाल) जारी----

उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट इकोनॉमी की अगर बात करें, डवैल्पमैंट के रास्ते में जो पहाड़ी राज्यों के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश अग्रणी श्रेणी में है। The State economy grew at an average rate of 1.4 per cent taking the GDP of the State from Rs. 82,820/- crores in 2012-13. It was Rs. 1,13,667/- crores in 2015-16. एडवांस ऐस्टिमेट के हिसाब से 2016-17 का the gross GDP of Himachal has gone to Rs. 1,24,570/- crores. यह जो स्टेट का ग्रोथ रेट है in the last five years has been estimated at 7.4 per cent which is higher than the national growth of 6.8 per cent. The per-capita income of the State has been increased from Rs. 99,721/- in 2015-16 and it is expected to be Rs. 1,47,277/- in 2017. जो फाईनैंशियल मैनेजमैंट की बात हुई है इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि सितम्बर, 2015 में युनाईटेड नेशन ने एक एजैंडा 2030 तैयार किया था, उसमें सस्टेनेबल डवैल्पमैंट के लिए कुछ टारगेट रखे थे और टारगेट पूरा करने का समय वर्ष 2030 था। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि वह टारगेट उन्होंने पहले ही वर्ष 2022 तक पूरे करने के बारे में कहा है और सरकार ने मिशन डाक्युमैंट 2030 बनाना है जिसमें पहले सात साल में डवैल्पमैंट स्ट्रेटैजी होगी और तीन साल का ऐक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। यह भी एक बहुत बड़ी सोच है। It is official prudent financial management. केन्द्र सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं और एनुअल प्लान को साईड करके एक जो नीति आयोग का गठन किया है, मैं नहीं जानता कि नीति आयोग की जो मीटिंग होती है उसमें मैम्बर्ज़ जाते होंगें या नहीं जाते मगर उससे हमारे यहां काफी फ़र्क पड़ा। और तो और जो हमारे पंचायती राज संस्थाओं के लोग थे, जैसे जिला परिषद के मैम्बर हैं, पंचायत समिति के मैम्बर्ज़ हैं, वे भी चुने हुए नुमाइन्दें हैं, they go to their particular area and अपने एरिया में जा कर they have to do some developmental works जैसे कोई छोटी-मोटी पानी की स्कीमें

हैं, एम्बुलैंस रोड़ज़ हैं, कोई दूसरे काम हैं, they don't have anything with them. हम माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहेंगें कि उनके लिए भी इस बजट में

16.03.2017/1220/केएस/एजी/2

प्रोविज़न रखा around Rs. 48/- crores so that they can also have some funds with them for developmental activities to be taken in their areas. हमारी सरकार ने इस वर्ष एनुअल प्लान में 5700 करोड़ का जो एनुअल प्लान साईज़ रखा है । जिसमें एस.सी.एस.टी. प्लान में as per the norms 25 per cent and इसी तरह से in Tribal Sub Plan Rs. 513/- crores and Rs. 70/- crores for Backward Area Sub Plan रखा है। इसी तरह से यह सब जानते हुए कि कर्ज का बोझ है लेकिन डवैल्पमैंट एक्टिविटीज़ में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई कमी नहीं रखी है because welfare of the State and interest of the people इस बात को ये हमेशा ध्यान में रखते हैं। The MLALAD upto 2012-2013 was just Rs. 50/- lacs. बहुत कम थी। पिछले साल के बजट में it was raised to one crore rupees. हम मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहेंगें कि इस वक्त उन्होंने the limit has been raised to Rs. 1.10 crores. आप लोगों को भी धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि इससे the institution of MLA उसमें एक बड़ा डिग्निफाईड काम देखने को मिला है। इस इंस्टीट्यूशन का इन्होंने बहुत ध्यान रखा है। हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगें।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

16.3.2017/1225/av/ag/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री नन्द लाल) -------- जारी

इसी तरह से (---घंटी---) हमारी एम0एल0ए0 लैड की जो सैंक्शन जाती थी वह केवल डवैल्पमैंट एक्टिविटीज और कनस्ट्रक्शन पार्ट में खर्च होती थी। अब इसमें से राइडर हटा

करके दूसरे संस्थानों के ऑफिसिज में भी डिफरैंट डवैल्पमैंट एक्टिविटी करने के लिए बजट में प्रोविजन रखा हुआ है ताकि आप उसमें भी काम कर सको। पहले एम0एल0ए0 विभिन्न विकास कार्यों के लिए नाबार्ड को 70 करोड़ रुपये की योजनाएं प्रस्तुत कर सकता थे जिसको अब बढ़ाकर 80 करोड़ रुपये कर दिया है। We would like to thank the Hon'ble Chief Minister, all of use, that side also. बजट में बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। प्रदेश के दस जमा दो पास बेरोजगार युवाओं के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता अनाउंस करके उनका बहुत ध्यान रखा है। इसके अतिरिक्त डिसेबल यूथ के लिए 1500 रुपये प्रति माह भत्ता देने की घोषणा भी की है। स्किल डवैल्पमैंट अलाऊंस के लिए 100 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान रखा है। यहां पर मैं फूड सिक्योरिटी के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। We are the second State in the country today who could implement the Rajiv Gandhi Anna Yojna and more than 38 lacs people have been covered in that. जिनको तीन रुपये किलो चावल, दो रुपये किलो गेहूं मिलता है। It is history that we are the second State in the country to implement that Scheme. इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2007 में स्टेट सब्सिडी स्कीम बनाई जिसके अंतर्गत तीन तरह की दालें, दो लीटर तेल और नमक इत्यादि मिलता है। Any card holder, IRDP, BPL, APL and Antodaya - जितने भी लोग हैं या जिनको भी राशन मिलता है उनके लिए हर साल बजट में सफिशैंट प्रोविजन रहता है। इसके लिए इस बार 220 करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा गया है जिसके लिए हम माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। इसके अलावा

16.3.2017/1225/av/ag/2

मैं यह कहना चहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की इकोनोमी में होर्टिकल्चर का एक अहम रोल रहता है। होर्टिकल्चर के अंतर्गत डवैल्पमैंट प्रोजैक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक से 1134 करोड़ रुपये आया है जिसको इस साल से फंक्शनल बनाना है। उसमें मैं सरकार से यह आग्रह

करना चाहूंगा कि हमारे रामपुर के ननखड़ी एरिया में भी एक सी0ए0 स्टोर बने क्योंकि वहां भी लोगों की बहुत ज्यादा सेब की फसल होती है। उसको टाइम से मार्किट पहुंचाने में कई बार दिक्कत रहती है। वहां पर एक कोल्ड स्टोर होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया जाए। We have already identified the land and everything. इसी तरह से एग्रिकल्चर सैक्टर में बहुत काम हुए हैं और इस बार के बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसमें बहुत सारी स्कीमें लाई हैं। मैं यहां पर रोड की बात भी करना चाहूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रोड की बहुत ज्यादा पैंडेंसी थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वर्ष 2012 के बाद वहां सड़क निर्माण के क्षेत्र में जो काम हुआ है वह अपने आप में एक रिकार्ड है। ननखड़ी बस स्टैंड में एक सब डिपो बनना है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उसके लिए इस बजट में प्रावधान किया जाए ताकि वहां सब डिपो खुल सकें। रामपुर में एक पुल बनना है क्योंकि वहां पर शहर के अंदर बहुत कनजैशन है। ट्रैफिक की कनजैशन को दूर करने के लिए there is a place identified हमारा जो नया बस स्टैंड है उसके आगे को सतलुज रिवर पर एक पुल बनना है। उसके लिए भी इस बजट में प्रोविजन किया जाए ताकि वहां पर वह पुल लग जाए और रामपुर के अंदर ट्रैफिक कनजैशन दूर हो सके।

मैं यहां पर थोड़ी सी बात डीमोनिटाइजेशन पर भी करना चाहूंगा क्योंकि उस तरफ से भी इस विषय पर काफी बात की गई है।

श्री वर्मा द्वारा जारी

16/03/2017/1230/टी0सी0वी0/ए0एस0/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री नन्द लाल)..... जारी।

हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कालाधन निकालना बहुत जरूरी है। But it was done in a haste and without any proper preparation. आप आचनक से अलाऊंस करते हैं कि 500/1000 रूपये का नोट बन्द हो जाएगा। I am telling you that it was done without preparation.(व्यवधान)-स्लॉट छोटा है। The size of the note is slightly bigger. जब आप निकालेंगे तो ये बाहर नहीं आएगा। आर0बी0आई को चाहिए था sufficient currency to be made available to the people. मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा you have kept your hard earn money in the bank उसको निकालने के लिए आपको इजाज़त नहीं है। Rather it's a breach of our Fundamental Right, my hard earn money is in the bank but I cannot withdraw that money. उससे कितने लोगों को तकलीफ़ें हुई और कितने लोग उसके कारण मरे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि people lined up in the queue. कोई गिर कर मर रहे हैं। ये एक अच्छी बात नहीं रही। पिछले कल यू0पी0 और उत्तराखण्ड के इलेक्शन के बारे में बड़ा ज़िक्र हुआ। मैं यह कहना चाहूंगा कि Election is management and they are trained in that. Why you are talking only about Uttrakhand and Uttar Pradesh? मैनेजमेंट इस तरह से जैसे मणिपुर में मैनेजमेंट हो गया है। आपने गोवा में मैनेज कर लिया। Basically it is management. मैं यह कहना चाहूंगा कि डिमोनिटाइजेशन का वहां क्या फर्क हुआ, आप लोग सब जानते हैं कि हर हिन्दुस्तानी को इसमें दिक्कतें आई हैं। Slowly it is easing out, but initially the kind of suffering we have got, everybody knows it. -(घण्टी)-

Deputy Speaker: Please wind-up now.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री नन्द लाल): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट इस बार पेश किया है, यह अपने-आप में एक मिसाल है। मैं इस बजट का पुरज़ोर समर्थन करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

16/03/2017/1230/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने 2017-18 के बजट अनुमान पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका अग्रिम धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्य संसदीय सचिव हमारे जिले से आते हैं। ये अन्त में पूरा भाषण डिफेंड करने की नाकाम कोशिश करते हुए, डिमोनिटाइजेशन पर पहुंच गये। मैं इससे पहले कि अपनी बात प्रारम्भ करूं। 12 मार्च, 2017 को जब चुनाव के नतीजे आये, उसके दूसरे दिन, 'अमर ऊजाला' एक अख़बार छपता है और आप लोग भी उसको पढ़ते हैं। उसका सम्पदाकीय छपा है। जिसका शीर्षक है- धोया, निचौड़ा और सुखा डाला। मैं इसकी चंद लाईनें पढ़ूंगा- "कुछ होती है इच्छाएं, कुछ होती है कामनाएं, कुछ कामनाएं और भविष्यवाणी। बाकी होता है यर्थाथ। मोदी की विफलता की कामना से जिन लोगों ने अपनी इच्छाएं, कामनाएं, भविष्यवाणी बुन ली थी, उन्हें ज़बरदस्त धक्का लगा है। वे यर्थाथ का आश्य अपने निर्मित संदर्भों से नये व्याकरण में उगलना शुरू हो गये हैं, लेकिन आंखे मूंद लेने से तूफान शान्त नहीं हो जाता"। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये अख़बार है, आपने ये पूरा पढ़ा है -(व्यवधान)- हां चिट्ठियां भी आएगी, क्यों नहीं आएगी। अब राहुल गांधी तो चिट्ठी लिखने से रहे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपना 20वां बजट पेश किया और उस 20वें बजट के बारे में माननीय सदस्य श्री नन्दलाल जी कह रहे थे कि ऐतिहासिक बजट है। वह ज़रूर ऐतिहासिक है, क्योंकि 78 पेज़ पढ़ने के लिए साढ़े चार घण्टे तक वे खड़े रहे और सारे सदन को भी यहां बैठाये रखा। इनके मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य गहरी निंद्रा में यहां पर सोये हुए थे। उनको यह भी मालूम नहीं कि क्या पढ़ा गया। -(व्यवधान)-

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। -(व्यवधान)-Waht is this? What are you saying? ..(interruption)...This is absolutely wrong.

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी।

16/03/2017/1235/ एन0एस0/ए0एस0 /1

श्री सुरेश भारद्वाज----जारी

I am not yielding. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन 78 पेजों में हम बार-बार आगे पीछे पन्ने बदल कर देखते रहे लेकिन हमें वहां पर कुछ नहीं मिला। इस मान्य सदन में जब बजट पर चर्चा शुरू हुई तब माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने प्रदेश की सरकार और जनता का ध्यान इस और दिलाया था कि हिमाचल प्रदेश ऋण में ट्रैप हो रहा है। इनकी इस किताब के मुताबिक ऋण 38,568 करोड़ रूपये का है। अभी मालूम हुआ है कि ये इस वर्ष के लिए लगभग 7,000 करोड़ रूपये का ऋण लेने वाले हैं। केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने हमारे सांसद माननीय अनुराग ठाकुर जी को पत्र लिखा है और कहा है कि 31 मार्च तक 45,200 करोड़ रूपये का ऋण हिमाचल सरकार के ऊपर देय हो जाएगा। आज के ट्रिब्यून में इसके पूरे आंकड़े दिए गए हैं। इसमें स्पष्ट दर्शाया गया है कि हिमाचल के ऊपर वर्ष 2020 तक लगभग 63,000 करोड़ रूपये से अधिक का ऋण होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी बजट की किताब से जो भाषण पढ़ा है, उसमें कहा है कि केंद्र ने अपना बजट इस बार प्लान और नॉन-प्लान से हट करके बनाया है और प्रदेशों का भी उसी के अनुरूप बनना था, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना बजट प्लान और नॉन-प्लान में रखा है। 5700 करोड़ रूपये की प्लान इसमें पास कर दी गई है। इस 5700 करोड़ रूपये की प्लान में कर्ज़ का जो ब्याज देना है, वही 3500 करोड़ रूपये का है। यह इसी वर्ष 2017-18 का ब्याज है। इसके अतिरिक्त इसकी किश्तें भी देनी हैं। इसके अलावा वेतन और पेंशन्ज़ भी देनी हैं। मुख्य मंत्री महादेय की स्वयं स्वीकारोक्ति है कि पूंजीगत ढांचे के विकास के लिए हमारे पास कतई धन नहीं बचेगा, तो फिर इस प्रदेश का विकास कैसे होगा? आज हिमाचल प्रदेश का जो विकास हो रहा है वह तो केवल मात्र केंद्र सरकार यानि माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से हो रहा है। जिसने 90:10 की रेशो में हिमाचल प्रदेश को ढांचागत व्यय के लिए जो बाह्य योजनायें होती हैं, उसके लिए पैसा दिया है और उसी से आज विकास हो रहा है, वरना हिमाचल प्रदेश का विकास तो वैसे भी रूका हुआ है और इनके पास वेतन देने के लिए भी पैसा नहीं है। हम 13वें वित्तायोग की रेकमेन्डेशन्ज़ जानते हैं। 14वें वित्तायोग ने हिमाचल प्रदेश को जो पैसा दिया है वह 250 प्रतिशत से अधिक मिला है। जब केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार आई तब उन्होंने पैटर्न बदला। पहले कभी भी टैक्स डेवोल्यूशन 2-3 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ता था, लेकिन

----श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

श्री सुरेश भारद्वाज...जारी

इस बार उन्होंने सीधा-सीधा 32 परसेंट से बढ़ाकर 42 परसेंट किया जिसके कारण आज हिमाचल प्रदेश सरकार चल रही है। हम सरकार चलाने की बजाय शेरो-शायरी में फंसे हुए हैं। हम इधर-उधर उलझे हुए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो भी यहां पर लाया हूं। इसमें आपने कहा-'सर्वांगीण विकास कांग्रेस का वायदा।' 'स्वच्छ शासन और कुशल प्रशासन।' 'जवाबदेह एवं पारदर्शी सरकार और पांच वर्षों में विकसित हिमाचल।' अब मैं सरकार के नीतिगत दस्तावेज़ को यहां पर ला रहा हूं। आप अपने कुशल प्रशासन और स्वच्छ शासन की बात सुन सकते हैं। आपने टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन बना रखा है। हर रोज सरकार का एक नया अतिरिक्त मुख्य सचिव बन जाता है। जो प्रदेश के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्ज हैं, वे या तो केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं अथवा ट्रिब्यूनल में अपने अधिकारों के लिए केसिज़ कर रहे हैं। सीनियर मोस्ट ऑफिसर्ज जो मुख्य सचिव बनने की लाइन में थे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ज्यूडिशियल एक्शन के लिए मांग करनी पड़ रही है। यह हिमाचल प्रदेश के लिए शर्म की बात है। आपके टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन में वन विभाग में दो पोस्टें पी.सी.सी. एफ. की हैं लेकिन उसके विरुद्ध आपने 13 पी.सी.सी. एफ.लगा रखे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार हारे हुए और नकारे हुए प्रत्याशियों की सरकार है। यह सरकार टायर्ड, रिटायर्ड और हायर्ड लोगों की सरकार है। (व्यवधान)... कैबिनेट के मंत्रियों को तो यह मालूम नहीं होता कि क्या डिसिज़न होने वाला है। परिवहन मंत्री, श्री जी.एस. वाली जी ऑन रिकॉड है, जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की कि धर्मशाला में दूसरी राजधानी होगी। इन्होंने ई.टी.वी. के ऊपर इंटरव्यू दिया, जिसमें मैं भी डिबेट में था। इन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में मालूम नहीं है और न ही केबिनेट में इसका डिसिजन हुआ है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी यही ब्यान आया कि हमें राजधानी के

बारे में कुछ मालूम नहीं है। आज सरकार इनके द्वारा नहीं चल रही है और न ही इनको कोई पूछता है।

16/03/2017/1240/RKS/DC/2

जब माननीय मुख्य मंत्री जी भाषण देते हैं तो उनके पीछे श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और श्री सुधीर शर्मा जी जरूर बैठ होते हैं। कुछ चीजें जो माननीय मुख्य मंत्री जी को समझ न आए वे उनको पीछे से बताते रहते हैं। लेकिन नीतिगत डिसिज़न में उनका कोई योगदान नहीं होता है। कल माननीय इन्द्र सिंह जी अपने भाषण में बोल रहे थे कि जो प्रत्याशी मेरे से दो बार हार गए वे माननीय मुख्य मंत्री जी को एडवाइज दे रहे हैं। वे ऐसी एडवाइज दे रहे होंगे, जो उनके साथ हुआ, वह इस सरकार के साथ भी हो। इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। जो हमारे सर्विंग ऑफिसर्ज हैं वे ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं या केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

16.03.2017/1245/SLS-DC-1

श्री सुरेश भारद्वाज....जारी

सरकार पूरी-की-पूरी रिटायर्ड़ लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। इस तरह हिमाचल प्रदेश कहां जाएगा? इस तरह की एडवाइस के आधार पर आज मुख्य मंत्री जी काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की फाइनैंशियल मैनेजमैंट आज इसी आधार पर हो रही है जिसमें FRBM का भी कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। FRBM के मुताबिक रैवन्यु डैफिसिट 3% होना चाहिए और वह कम होता जाना चाहिए। आप इस सारे फाइनैंशियल डिसिप्लेन को तोड़ रहे हैं क्योंकि सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी जिम्मेबारी हो। बिना जिम्मेबारी

वाले जो ऑफिसर्ज़ लगाए हुए हैं, वह इस प्रकार के काम कर रहे हैं और ऐसे कामों के द्वारा सरकार को गुमराह कर रहे हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के मैनिफैस्टो में पहली बात कुशल प्रशासन की है जिसकी धज्जियां सबके सामने उड़ती हुई दिखाई देती हैं जब यहां पर किसी प्रकार का शासन-प्रशासन नहीं होता। आप ख़र्चे बढ़ाए जा रहे हैं और हारे हुए लोगों को तुरंत सबसे पहले बोर्ड़ों के चेयरमैन और वाईस चेयरमैन बना रहे हैं। उनका काम क्या है? अब तक बिल्डिंगों के उद्घाटन और शिलान्यास की बातें सुनी थीं। सड़क का उद्घाटन भी हो जाता था और कुछ लोकार्पण भी होते थे। लेकिन आजकल कहीं दीवार लगती है या डंगा लगता है तो इनके चेयरमैन और वाईस चेयरमैन उसका भी उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। उसमें ई-ट्वायलेट्स बन रही हैं। उनके उद्घाटन के लिए भी उन्हीं लोगों को वहां बुलाया जाता है क्योंकि एम.एल.ए. तो जाता नहीं है न ही इनको बुलाते हैं। इनको कोई पूछता ही नहीं है।

माननीय नन्द लाल जी रामपुर में सड़कों की बात कर रहे थे। इनसे पूछिए कि रामपुर में काशापाट सड़क बनी या नहीं। आज भी काशापाट के लोगों ने बस नहीं देखी है। आज हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जबकि वह माननीय वीरभद्र सिंह जी का गृह क्षेत्र है। फिर कह रहे थे कि हमने बस अड्डा बदल दिया। पता नहीं नन्द लाल जी को उसके बारे में किसी ने पूछा या नहीं पूछा, क्योंकि इस बारे में

16.03.2017/1245/SLS-DC-2

म्यूनिसिपल कमेटी रामपुर से ही पूछा गया है। उन्होंने वहां से बस अड्डा हटाकर पार्क बना दिया। पार्क किसलिए बना? वहां पर किसका होटल बना? उसकी खूबसूरती के लिए वह पार्क बनाया गया है। इस पर विचार करना चाहिए। यह हमारी चार्जशीट में है।

मैं आपकी चार्जशीट भी लाया हूं जिसमें आपने बड़े शब्दों में लिखा है - Himachal for sale. माननीय कौल सिंह ठाकुर जी उस वक्त अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय यहां वैल

में आकर नारे लगाया करते थे। माननीय सुजान सिंह पठानियां जी गीत गाया करते थे क्योंकि शेयरो-शायरी और गीतों की इनको आदत है। काम तो कभी करना होता नहीं है, हिमाचल प्रदेश चाहे जहां मरज़ी जाए, लेकिन गीत गाएंगे। चार्जशीट की यह बड़ी किताब लिख डाली। जो एक-दो केस इन्होंने बनाए भी, वह सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो रहे हैं। इसलिए इस सारी कवायद का कोई लाभ नहीं हुआ।

हमने जो अपनी चार्जशीट लगाई है, मैं उसकी कॉपी भी लाया हूं। उसमें भी हमने बताया है।...(व्यवधान)... आप इसको प्रूव करिए। *****।** यह हमारे इस आरोप-पत्र का शीर्षक है। आप इसकी इनवैस्टिगेशन करिए और फिर पता चलेगा कि कितने लोग यहां पर बैठते हैं, कितने लोग बाहर चले जाते हैं या कहीं तिहाड़ की ओर जाते हैं। इसलिए इस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए कि यह सरकार किस प्रकार से चल रही है।

*******अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

16.03.2017/1245/SLS-DC-3

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज विकास के नाम पर कहीं कोई ईंट हिल नहीं रही है। इस सरकार को बने चार साल से अधिक का समय हो गया है लेकिन विकास जहां था, वहीं ठप है। केवल मात्र घोषणाएं हो रही हैं और उसमें तहसीलें बना रहे हैं, उप-तहसीलें बना रहे हैं तथा पटवारखाने बना रहे हैं। हम पटवारखाना मांगते हैं तो कहते हैं, नहीं, तुमको तहसील मिलेगी। हम प्राइमरी स्कूल मांगते हैं, उसकी जगह कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी देंगे। ...(व्यवधान)...

उद्योग मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, *** शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए क्योंकि ये असंसदीय शब्द हैं।

श्री सुरेश भारद्वाज : आप शकधर की किताब ले आओ और देख लो, अगर यह उसमें मिलता है।

जारी ..श्री गर्ग जी द्वारा

*** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

16/03/2017/1250/RG/AG/1

---(व्यवधान)-----

संसदीय कार्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, इनके साथ जो यहां सदन में बैठे हुए हैं और जीतकर आए हैं उनको ये *** बता रहे हैं। इसलिए इसको कार्यवाही से निकाला जाए।

Deputy Speaker: I am expunging the remarks ***.

श्री सुरेश भारद्वाज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा चीजों पर नहीं जाऊंगा, केवल शहरी विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के बारे में बोलना चाहूंगा और शिमला तक सीमित रहूंगा।

उपाध्यक्ष : प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को आपत्ति इस मुहावरे पर है या कम संख्या बताई, इस पर आपत्ति है?

श्री सुरेश भारद्वाज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यह आज से नहीं है। जब अंग्रेज हिन्दुस्तान पर राज करते थे, तो उस समय अंग्रेजों ने ऊटी से राज करना शुरू किया। ऊटी, दार्जिलिंग, नैनीताल और मसूरी, वे सब जगह देखकर आए और शिमला उनको लंदन के समान लगा। यहां की जलवायु भी वहां की तरह है। इसलिए यहां राजधानी बनाई गई। इस राजधानी से सब-कंटीनेंट के पांच देश ऐडमिनिस्टर होते थे। हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और शिलॉन। उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश बना। यहां 35-36 छोटे-छोटे रजवाड़े थे उनको मिलाकर यहां की यह एक 'सी' क्लास स्टेट बनी। लेकिन वर्ष 1966 में हमारा जो बाकी पहाड़ी क्षेत्र पंजाब में था और शिमला भी उस समय पंजाब का ही हिस्सा होता था। लेकिन तब भी हिमाचल

प्रदेश की राजधानी शिमला ही थी। अलग राज्य बना था, कसुम्प्टी महासु जिले का हिमाचल का पार्ट था और शिमला पंजाब का हिस्सा था। लेकिन राजधानी शिमला में थी। उसके पश्चात वर्ष 1966 में जब पूरा एरिया मर्ज हुआ। उसके बाद भी डॉ. वाई.एस. परमार जिनको हिमाचल निर्माता कहते हैं, ये भी उनके चित्र पर 4 अगस्त को जाकर माल्यार्पण कर देते हैं। हालांकि उनके गांव बागथन को कभी सड़क नहीं पहुंचा सके। क्योंकि ये महात्मा गांधी के नाम पर सरकारें चलाते रहे। उनको भूल गए। डॉ. वाई.एस. परमार जी के

———————————————————————————————

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

16/03/2017/1250/RG/AG/2

नाम पर इन्होंने हिमाचल बनाया, लेकिन आज ये उनको भूल गए हैं। लेकिन उन्होंने भी शिमला को ही राजधानी रखा। उस समय वे भी दूसरी जगह राजधानी ले जा सकते थे। शिमला को उस समय विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। यहां पर राजधानी के लिए अलग से पैसा मिल सकता था। 7.19% पंजाब रि-ऑर्गनाईजेशन ऐक्ट के मुताबिक हमारा हिस्सा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने शिमला की हैरीटेज और इसकी वैल्यू को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के सीमित साधनों को देखते हुए सोचा कि हिमाचल में दूसरी राजधानी बनाना संभव नहीं है। किसी दूसरी जगह यदि विकास कार्यों पर लगाएंगे, सेब की खेती पर लगाएंगे, बिजली के प्रोजैक्ट्स पर लगाएंगे, तो अच्छा होगा। इसलिए उन्होंने शिमला को राजधानी रखा था। आज तो आप ऊपर बैठे-बैठे हमें एक भी कागज नहीं देते हैं और इस कम्प्युटर से ही हम सब लोग देख लेते हैं। यहां बैठे-बैठे आप सारी दुनिया को एक सैंकण्ड में मैसेज भेज सकते हैं। आज आपको क्या आवश्यकता पड़ी कि आप धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा कर रहे हैं? आप शिमला के साथ अन्याय कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके पैरा यहां पर गिना सकता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा है। जब शिमला को स्मार्ट सिटी बनना था, तो सबको मालूम था, केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार को अधिकार दिया था कि आप अपने शहरों में कम्पटीशन करवाइए। जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसको आप ईनाम दीजिए और उसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी का पता नहीं किसके प्रति

प्रेम है। उस समिति ने मीटिंग ही नहीं की। सर्कुलेशन से रेजूलूशन कर दिया। शिमला के 85 नंबर बनते थे, लेकिन उसके बाद शहरी विकास विभाग ने नंबर धर्मशाला के बढ़ाए। जबकि वहां जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्युअल मिशन था ही नहीं। फिर भी उसके नंबर दे दिए। ई न्यूज लैटर वहां था ही नहीं, फिर भी उसके नंबर दे दिए। वहां पर डबल काउन्टिंग सिस्टम था ही नहीं, 22,000 की तो सिर्फ वह म्युनिसपल कमेटी थी उसके भी नंबर दे दिए।

एम.एस. द्वारा जारी

16/03/2017/1255/MS/AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी---------

सारे नम्बर देकर शिमला के साथ अन्याय किया और मुख्य मंत्री जी ने अपने एक मंत्री के प्रेम के कारण धर्मशाला को "स्मार्ट सिटी" बनवा दिया और शिमला के साथ अन्याय किया है। मैंने इसी सदन में पूछा था कि आई0जी0एम0सी0 को आप ऑटोनोमस संस्थान या युनिवर्सिटी बनाएंगे? इस पर माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने कहा था कि यह जल्दी ही युनिवर्सिटी बन जाएगी। लेकिन जब घोषणा हुई और इस बजट में भी आपने कहा है कि मेडिकल युनिवर्सिटी मण्डी में बनेगी क्योंकि मण्डी से स्वास्थ्य मंत्री जी आते हैं। शिमला में इतने बड़े अस्पताल को आप बर्बाद करने में लगे हुए हैं। शिमला की फैकल्टी यहां से उठाकर कोई नाहन, कोई चम्बा और कोई नेरचौक भेजी जा रही है। यहां तक कि जो लैब अटैंडेंट्स/लैब असिस्टैंट्स हैं उनको भी यहां से तीसरे दिन ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि इन दूसरे अस्पतालों को एम0सी0आई0 की परमिशन मिल जाए। इतना ही नहीं केन्द्र सरकार से सुपर स्पेशियलिटी के लिए पैसा आया है लेकिन वह सुपर स्पेशियलिटी भी आई0जी0एम0सी0 में न खोलकर मल्याणा में खोली जा रही है क्योंकि शिमला मेरा चुनाव क्षेत्र है। यदि यहां पर सुपर स्पेशियलिटी नहीं होगी, कार्डियोलॉजी डिपार्टमैंट मल्याणा में होगा, मेडिकल डिपार्टमैंट आई0जी0एम0सी0 में होगा तो जब तक मरीज मल्याणा में पहुंचेगा तब तक तो उसका राम नाम सत हो जाएगा। यहां कमला नेहरू अस्पताल में महिलाओं के प्रसव होते हैं और गायनाकोलॉजी डिपार्टमैंट वहां पर है। मैं कह रहा था कि उसको भी बदलकर आप आई0जी0एम0सी0 के साथ जोड़िए क्योंकि मेडिसन,

सर्जरी और एनीस्थिसिया वाले आई0जी0एम0सी0 से ही वहां जाते हैं। अध्यक्ष जी, मैंने इसी सदन में यह मामला उठाया था उसका जवाब अभी नहीं आया है। माननीय अध्यक्ष जी ने उसका सरकार को नोटिस भी दिया था कि गर्भस्थ शिशु का टैस्ट करवाने के लिए दो-दो बार आई0जी0एम0सी0 जाना पड़ा जिसका परिणाम यह हुआ कि उस महिला का गर्भ में ही शिशु मर गया और मां को दोनों जगह चक्कर लगाने पड़े। अब इसी तरह का हाल आप सुपर स्पेशियलिटी को मल्याणा ले जाकर कर रहे हैं क्योंकि कुछ अधिकारी चाहते हैं कि वह वहां बने लेकिन कब बनेगा, पता नहीं है और तब तक उस पैसे का इस्तेमाल कहां होगा, इसका भी कोई पता नहीं है। इसलिए उसको भी वहां से बदल दिया जाएगा।

16/03/2017/1255/MS/AG/2

ट्रॉमा सेंटर का पैसा यहां पर आया है लेकिन वह ट्रॉमा सेंटर आज तक नहीं बन रहा है। हमने दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भवन बनाकर आपको दिया है और वह अस्पताल नेशनल हाइवे के पास है। वहां सीधी गाड़ी अंदर जाएगी इसलिए आप वहां ट्रॉमा सेंटर बनाइए और सुपर स्पेशियलिटी आप आई0जी0एम0सी0 में रहने दीजिए। अगर आवश्यकता हुई तो आप डैंटल कॉलेज को वहां से बदल सकते हैं लेकिन सुपर स्पेशियलिटी यदि यहां नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सुपर स्पेशियलिटी को आप यहां पर बनाइए। वास्तव में माननीय मंत्री जी को भी इन चीजों का मालूम नहीं होता है। निर्णय कहीं और जगह होते हैं और वहां से फैसला हो जाता है। अगर आपने युनिवर्सिटी बनानी है तो आई0जी0एम0सी0 इतना पुराना अस्पताल और कॉलेज है उसको क्यों नहीं ऑटोनोमस संस्थान बनाते? वहां सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर भी है। मल्याणा में उसके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसिज रख दिए जाएं बाकी जैसे एडवांस स्टडी सेंटर या बाकी सेंटर्ज हैं वे आई0जी0एम0सी0 में हो सकते हैं। लेकिन शिमला के साथ अन्याय करने का प्रयास किया जा रहा है इसलिए इसको शिमला में नहीं रखना है और शिमला से बाहर बदलनी है। स्मार्ट सिटी भी शिमला में नहीं बनाई जाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि यह सरकार हारे हुए नकारों की सरकार है। मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि सारा लोक निर्माण विभाग ठेकेदार चला रहे हैं, ठेकेदारों के सिर पर यह विभाग चल रहा है। यह मैं

नहीं कह रहा हूं बल्कि यह मुख्य मंत्री जी का रोहडू में दिया गया बयान है। इस सरकार को ठेकेदार और इस तरह के लोग चला रहे हैं तो सबकुछ किस तरह से होगा।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश भारद्वाजः हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, शिमला थी और शिमला ही रहेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी आप वहां पर एक-दो ऑफिसिज ले गए होंगे लेकिन आपको वहां पर कभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि कांगड़ा के लोग जानते हैं कि इससे उनको क्या फायदा है। वहां पर आपने एक विधान सभा

16/03/2017/1255/MS/AG/3

का भवन बना दिया है। हमारे लिए तो ठीक है कि हम वहां पर हर साल पिकनिक मनाने चले जाते हैं लेकिन धर्मशाला और कांगड़ा का कोई व्यक्ति उस विधान सभा को देखने भी नहीं आता है क्योंकि उनको वहां पर विकास की आवश्यकता है। विकास के लिए यदि वहां पर पैसा लगेगा तब वहां के लोगों को उसका फायदा होगा। -(व्यवधान)- आपको कुछ नहीं दिया है आपको झुनझुने दिए हैं। जब हिमाचल प्रदेश मर्ज हुआ था तो हिमाचल प्रदेश का मुख्य मंत्री भगत राम या राम चन्द्र जी को बनना चाहिए था या अन्य भी बड़े-बड़े जो नेता थे उनको बनना चाहिए था।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

16.03.2017/1300/जेके/एएस/1

श्री सुरेश भारद्वाजः---**जारी**---

आपको नहीं बनाया गया। अगर वहां पर कोई मुख्य मंत्री बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। चाहे शांता कुमार को बनाया है और चाहे प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी को बनाया है, इसलिए जगजीवन पाल जी आप भी इससे ऊपर निकलिए। .....(व्यवधान).....

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य प्लीज वाईंड अप, please wind-up now. आपका टाईम हो गया है।

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं वाईंड अप कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस बजट में बाकी भी बहुत सारी चीजों के बारे में कहा गया है लेकिन उसकी इम्प्लिमेंटेशन पिछले चार सालों से कुछ नहीं हुई, जैसे कि माननीय धूमल जी ने अपने वक्तव्य में पहले ही दिन कह दिया था। कोई भी स्कीम जो बनती है, शिलान्यास कर दिया दाड़नी का बागीचा में जहां पर मार्केटिंग की सब्जी मण्डी बनेंगी लेकिन आज तक वहां पर पत्थर तक नहीं हिला है। म्युनिसिपल कमेटी वाले वहां पर कुछ और बनाने के लिए घूम रहे हैं। यहां पर मार्केटिंग बोर्ड, मार्केटिंग कमेटियों में भ्रष्टाचार के अलावा उनको बाकी किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है। अब एक ही व्यक्ति एक ही जगह से आता है, उसको पहले मार्केटिंग कमेटी का एम0डी0 बना देते हैं और फिर उसको होर्टिकल्चर का डायरैक्टर बना देते हैं। उसके बाद वहां पर क्या-क्या होता है इसका कोई मालूम नहीं है? बाकी डिपार्टमैंट्स में भी किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है उसका भी मालूम नहीं है? हरेक विभाग में इस प्रकार की गतिविधियां हो रही है। शिमला में जोधा निवास में पार्किंग बनी। वहां पर पेड़ खड़े थे। हमारे नरेन्द्र बरागटा जी उस समय मंत्री थे उन्होंने उसका शिलान्यास किया था उसके बाद दो मंजिलें बन गई और ऊपर सरिए रख दिए गए थे। वर्ष 2003 में जब माननीय मुख्य मंत्री जी की सरकार आई थी तो सरिए कटवा दिए थे कि ये पेड़ यहां पर नहीं कटने चाहिए। ये हरे पेड़ रहने चाहिए और ऊपर की मंजिल नहीं बनेगी। लेकिन अब पिछले साल वे हरे पेड़ काट दिए गए, क्यों काट दिए गए उसकी इन्क्वारी होनी चाहिए? उनका सीधा-सीधा ट्री कमेटी से नहीं केबिनैट से मंजूरी दी गई।

16.03.2017/1300/जेके/एएस/2

Deputy Speaker: Please wind-up now, otherwise I will not allow.

श्री सुरेश भारद्वाजः उपाध्यक्ष महोदय, मैं वाईंड अप कर रहा हूं। एक-दो इश्यूज बोल करके वाईंड अप कर दूंगा। उसकी वहां पर ट्री कमेटी के बगैर उनको समाप्त कर दिया गया है। तारादेवी में जो पेड़ कटे थे उनका आज तक कुछ पता नहीं चला कि उसका क्या

हुआ है? केस बने हैं या नहीं बने हैं उसका कोई पता नहीं है। इसलिए यहां पर जो स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं वह स्वच्छ प्रशासन आपका कहां पर है? नौकरियां लग रही है और मेरे पास सुबह ही एक आदमी आया था कि आपके एजुकेशन के डिप्टी डायरैक्टर के ऑफिस में जो बैच वाईज नौकरियां लगती हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बैच के हिसाब से, लिस्ट के हिसाब से वहां बन जाने चाहिए। उनको टेलिफोन कर रहे हैं। .....(व्यवधान).....

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज वाईंड अप करिए।

श्री सुरेश भारद्वाजः उपाध्यक्ष जी, दो मिनट में खत्म कर रहा हूं।

उपाध्यक्षः दो मिनट नहीं I Please wind-up now. I have given you enough time.

श्री सुरेश भारद्वाजः उपाध्यक्ष महोदय, मैं चार साल कभी भी किसी विषय पर नहीं बोला। मैं दो मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं।

Deputy Speaker: Please conclude it in two minutes. I have already given you half an hour.

श्री सुरेश भारद्वाजः उपाध्यक्ष महोदय, कईयों ने 45-45 मिनट लिए है।

16.03.2017/1300/जेके/एएस/3

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य आपको पूरा आधा घंटा दिया है।

श्री सुरेश भारद्वाजः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहां पर पेड़ों का कटान हो रहा है। फिर यहां पर डिजास्टर मैनेजमैंट है। इस सरकार के हाल एक ही घटना से पता चल जाएंगे। इस बार 6 व 7 जनवरी को बर्फ गिरी। उस बर्फ गिरने के बाद यहां पर बिजली चली गई, पानी चला गया और सड़कें बन्द हो गई। डिजास्टर मैनेजमैंट कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया? डिजास्टर मैनेजमैंट के प्रदेश के जो उपाध्यक्ष है, वे जालंधर से

स्टेटमैंट दे रहे थे कि नोटबन्दी गलत हुई है। उनके नोट फंस गए होंगे इसलिए वे स्टेटमैंट्स दे रहे थे। शिमला के डी0सी0 उसके अध्यक्ष होते हैं। वे छुट्टी पर थे या किसी ट्रेनिंग में थे और वे भी यहां पर नहीं थे। मेयर और डिप्टी मेयर तो पूरे पांच साल विदेशों में ही घूमते रहे हैं। उनको तो विदेशों में घूमने का मौका मिल गया। शिमला में जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो मुख्य मंत्री जी कांगड़ा के दौरे पर होते हैं। कोई टैलिफोन नहीं सुनता। किसी ने भी टैलिफोन नहीं सुना। सात दिन तक बिजली नहीं आई। पानी बिजली के ऊपर निर्भर करता है और पानी भी नहीं आया। सड़कें ठीक नहीं हुई तो सरकार का हाल हिमाचल प्रदेश की राजधानी में यह है तो बाकी स्थानों पर क्या होगा इस बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं1 पिछले वर्ष शिमला में पीलिया हुआ था। माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं यह छोटी बात है और इसको ज्यादा बढ़ा रहे हैं। उससे 32 लोग मर गए। हजारों लोग बीमार हो गए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लोगों को, वी0आई0पी0 इलाकों में

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

16.03.2017/1305/SS-AS/1

श्री सुरेश भारद्वाज क्रमागतः

बैनमोर के इलाके में भी मलमूत्र पिलाया गया है और बहुत सारे ऑफिसर भी आई0जी0एम0सी0 में एडमिट थे, मैं उनको देखने गया था।

Deputy Speaker: Now please wind up.

श्री सुरेश भारद्वाजः सर, मैं लास्ट प्वाइंट बोल रहा हूं। मैं उनको वहां देखने गया था। इस प्रकार से शिमला की हालत कर रखी है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। यह सरकार केवलमात्र कोरी घोषणाओं की सरकार है। घोषणाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है या दूसरा काम भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके अलावा इस सरकार में कुछ नहीं है। इसलिए यह बजट खोखला बजट है। यह कर्मचारी विरोधी बजट है। कर्मचारियों के साथ चुनाव के समय जो

वायदा किया था, उसमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। कर्मचारियों को 4-9-14, ग्रेड पे और बाकी कोई चीज़ इस बजट में नहीं दी गई है। आउटसोर्स पर बैकडोर एंटरियां करवा रहे हैं।

Deputy Speaker: Please wind up otherwise I will not allow you.

श्री सुरेश भारद्वाजः सर, दो मिनट में वाइंड अप कर रहा हूं। आउटसोर्स पर कम्पनियां जो लोग भेज रही हैं वह किस आधार पर भेज रही हैं? वह किसकी कम्पनियां हैं, यह बताया जाए। शराब की कम्पनी में क्या हो रहा है, वह किस के द्वारा हो रही है उसकी भी इंक्वायरी की जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।

समाप्त

16.03.2017/1305/SS-AS/2

उपाध्यक्षः माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज जी ने अपने दिल की खूब भड़ास निकाली है। विपक्ष में हैं और इनका अधिकार भी है। इन्होंने तीन-चार बातें की हैं, एक तो ट्रॉमा सैंटर की बात की है। शायद इनको पता नहीं है कि लेवल-I का ट्रॉमा सैंटर आई0जी0एम0सी0, शिमला में ही खुलेगा। 56 करोड़ रुपये की वहां बिल्डिंग (ओ0पी0डी0) बन रही है। उसमें हमने दो फ्लोर ट्रॉमा सैंटर के लिए इयरमार्कड कर दिये हैं। ट्रॉमा सैंटर शिमला में खुलेगा। जहां तक सुपर-स्पैशलिटी की बात है, मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि ये मेरे साथ चलें, सुपर-स्पैशलिटी की 150 करोड़ की

बिल्डिंग और इक्विपमैंट इत्यादि होगा। ये बता दें कि शिमला में जगह कहां है। जगह नहीं है और जो दिल्ली की टीम आई थी उन्होंने कहा कि यह जगह सुपर-स्पैशलिटी के लिए स्यूट नहीं है इसलिए हमने मलाणा में फैसला किया है कि 150 बीघा जमीन हैल्थ डिपार्टमैंट के नाम कर रहे हैं। वहां हम कैंसर हॉस्पिटल भी शिफ्ट करेंगे, सुपर-स्पैशलिटी हॉस्पिटल भी बनायेंगे और जो भी एक्सपैंशन करनी होगी, वह करेंगे।

तीसरा, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यूनिवर्सिटी की बात की है। --(व्यवधान)--

उपाध्यक्षः आप प्लीज बैठिये। Let him speak.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः इन्होंने यूनिवर्सिटी की बात की है। इनके भाषण से पूरी तरह से क्षेत्रवाद की बदबू आ रही है। राजधानी के बारे में कहा, मेरे बारे में कहा। ठीक है लोगों ने पूछा कि क्या आप राजधानी मंडी खोलना चाहते हैं तो मैंने कहा कि दो या तीन राजधानी नहीं हो सकती हैं। राजधानी एक ही होगी। कैबिनेट में इसका फैसला होगा और कैबिनेट में फैसला हुआ। जब मामला कैबिनेट में आया तो पूरी डिस्कशन के बाद हमने कहा कि सैकिंड विंटर कैपिटल धर्मशाला में खोली जाए।

जहां तक ये मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, यह तो मुख्य मंत्री जी को श्रेय जाता है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी हमने मंडी नेरचौंक में जो ई0एस0आई0 कारपोरेशन की साढ़े

800 करोड़ की बिल्डिंग बनी है वहां खोलने का फैसला किया है। मैं एक बात और सदन में बताना चाहता हूं कि चार पार्लियामैंटरी कांस्टीचुऐंसीज़ हैं। शिमला पार्लियामैंटरी कांस्टीचुऐंसी में प्राइवेट और सरकारी मिलाकर 10-11 यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमीरपुर पार्लियामैंटरी कांस्टीचुऐंसी में भी एक यूनिवर्सिटी है। हमारी कांगड़ा पार्लियामैंटरी कांस्टीचुऐंसी में भी यूनिवर्सिटियां हैं। सैंट्रल यूनिवर्सिटी है, दूसरे बोर्ड हैं। लेकिन मंडी एक ऐसी पार्लियामैंटरी कांस्टीचुऐंसी थी जहां कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है और वहां आधे से

ज्यादा एरिया हिमाचल का पड़ता है। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, मेरे अनुरोध पर नहीं बल्कि मुख्य मंत्री जी ने खुद कहा --(व्यवधान)--

Deputy Speaker: Please, be seated. Let him speak.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः सुनिये, मैं भी आपकी बात सुनता रहा। अब मेरी बात भी सुनिये। यह विपक्ष हमेशा क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने की बात करता है जबकि कांग्रेस पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश को एक नज़र से देखती है। पूरे हिमाचल प्रदेश का समान विकास करना चाहती है। इसलिए हमने कहा कि नीचे के जो पांच-छः जिले हैं उनको भी उसका फायदा मिले और लोग वहां मिलें। अगर वहां विधान सभा बनाई है तो वह भी कांग्रेस पार्टी ने ही धर्मशाला में बनाई है। अगर दो-तीन महीने के लिए कैपिटल वहां चली जाती है और हम लोग वहां बैठते हैं तो प्रशासन जनता के द्वार पहुंचाने की कांग्रेस पार्टी की योजना है। मेरे ख्याल में इनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

जारी श्रीमती के0एस0

16.03.2017/1310/केएस/डीसी/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी---

मुख्य मंत्री महोदय हमेशा ठीक कहते हैं कि विपक्ष के लोग हमेशा क्षेत्रवाद, जातिवाद और पता नहीं क्या-क्या वाद करते हैं, हम इनका विरोध करते हैं।

उपाध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक स्थगित की जाती है।

16.3.2017/1420/av/ag/1

सदन की कार्यवाही दोपहर के भोजनोपरांत 2.20 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।

उपाध्यक्ष : अभी 12 माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। आप पक्ष और विपक्ष की तरफ से डिसाइड कर लीजिए कि प्रत्येक सदस्य के लिए कितना-कितना समय निश्चित किया जाए। (---व्यवधान---) आप लोग बताइए कि कितने-कितने मिनट बोलना है। (---व्यवधान---) तो फिर प्रत्येक सदस्य के लिए 20-20 मिनट का समय निश्चित कर लेते हैं और 20 मिनट के बाद मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा। किसी भी सदस्य को 20 मिनट से ऊपर समय नहीं मिलेगा।

अब माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी चर्चा में भाग लेंगी।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्री वर्मा द्वारा जारी

16/03/2017/1425/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

Irrigation & Public Health Minister: Hon'ble Deputy Speaker, Sir, I would like to say few things. माननीय मुख्य मंत्री जी ने 83 वर्ष की आयु में साढ़े चार घण्टे में हिमाचल प्रदेश का 20वां बजट पेश किया है जो कि अपने आप में एक मिसाल हैं। उन्होने यह बजट बहुत ही साधारण रूप से पेश किया है। माननीय मुख्य मंत्री बड़ी शान्ति और सोच समझ से प्रदेश की सरकार चला रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस अनुभव की हम बार-बार बात करते हैं, उसकी मिसाल यह बजट है। इस बजट में शायद ही कोई वर्ग होगा जिसको इसमें लाभ न दिया गया हो। इस बजट में गरीबों का विशेष ध्यान रखा गया है। आप लोग कई बार नाराज़ भी होते हैं, लेकिन हम सच्चाई की बात करते हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी बड़े उदार है, वे पक्ष के साथ-साथ विपक्ष के माननीय सदस्यों का भी ख्याल रखते हैं। इस बज़ट में जो गरीब वर्ग हैं, उसके लिए बड़ी राहत दी गई है। लोकतंत्र में 20वां बजट पेश करने का मतलब होता है कि जनता ने हमें प्रदेश को आगे ले जाने का मौका दिया है। आज प्रदेश जिस ऊंचाई पर पहुंचा है यह हमारी सरकार ने जो प्रदेश के हित में काम किये हैं, उन सबका परिणाम हैं और मुझे यह जानकर अच्छा लगता है कि आज प्रदेश किस मंजिल पर पहुंचा है। लेकिन इस प्रदेश को और भी मजबूत करने की ज़रूरत हैं। इसके लिए हम कोशिश और मेहनत भी कर रहे हैं। इस बज़ट के माध्यम से

अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को भी फ़ायदा दिया गया है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी अच्छी सोच रखते हैं और सदभावना से सभी से बात करते हैं। -(व्यवधान)-I am not used to that. उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले चार वर्षों में राज्य आर्थिकी औसतन 7.4 प्रतिशत से बढी है जिससे राज्य का सकल घरेलू उत्पादन बढ़कर 1,24,570 करोड़ हो गया है। गत् 5 वर्षों में प्रदेश के वास्तविक वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत अनुमानित है जो कि इसी काल की राष्ट्रीय वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत से अधिक हैं। इसका वर्ष 2016-17 में 1,47,277 रूपये होने का अनुमान है। ये किसने किया है, ये विकास के क्षेत्र में एक रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि हमारे प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था कैसी है? अध्यक्ष जी। am so sorry. I am sorry. उपाध्यक्ष जी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है।

श्रीमती एन0एस0 ..... द्वारा जारी।

16/03/2017/1430/ एन0एस0/ए0जी0 /1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री ----- जारी

मैं कोई गाली नहीं दे रही हूं। यह शान्ति से बैठ कर सुनने की बात है। मुझे बोलने की आदत है और मैं कोई बुरी बात नहीं कह रही हूं। हम खुशी की बात कर रहे हैं। आप इसमें शान्ति से रहिए। आपको इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप आराम से सुनिए। ऐसे नाचने से कोई फायदा नहीं होता है। आप शान्ति से बैठिए। अगर आप इस बजट भाषण के बारे में सुनना चाहते हैं तो आप शान्ति से बैठिए और इसको सुनिए। हम लोग भी आप लोगों की तरह ऐसे ही बैठते हैं। अगर आप आराम से बैठ करके नहीं सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप (सत्ता पक्ष) चुप रहिए और इनको (विपक्ष) को बोलने दीजिए।। am so sorry. I am just telling. उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी बजट में 19,000 नौकरियों की सही घोषणा की है और बेरोजगारी भत्ते का तोहफा सही दिया है। यह प्रदेश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ी बात है। यह नौजवानों के लिए नई आशा की किरण है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में आउटसोर्स वाले कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने का इंतजाम किया है और इसका ऐलान माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। यह एक खुशी की बात है। यह बजट आम जनता के लिए भी बहुत अच्छा रहा है। मैं समझती हूं कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाना बहुत आवश्यक है और इससे हज़ारों युवाओं को लाभ होगा। यह कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इस बात को समझती हूं क्योंकि हम भी इतने सालों से काम कर रहे हैं। इस बारे में हरेक आदमी को पता होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने बजट पर कई प्रकार की टिप्पणियां की हैं। विपक्ष वालों ने इस बजट को आंकड़ों का मायाजाल बताया है और झूठी घोषणायें करार दिया है। हम जानते हैं कि अब चुनाव आने वाला है तो ये लोग कई प्रकार की बातें कर रहे हैं। मुझे कई बार हैरानी होती है कि पूर्व सरकार ने जाते समय कर्मचारियों तथा बेरोजगारों के लिए बहुत झूठे-झूठे आश्वासन दिए थे। हमें पता है कि पिछली सरकार के समय में क्या हुआ था? लेकिन वैसी फितरत हमारी नहीं है। हमारी फितरत हमेशा सही रहती है।

16/03/2017/1430/ एन0एस0/ए0जी0 /2

हमें पिछले टर्म में कैसा लगा और इस टर्म में कैसा लग रहा है, इसके बारे में हम कह सकते हैं। कांग्रेस सरकार ने जो वायदे किए थे, उनको हमेशा पूरा किया है। बजट में जो भी आंकड़े दर्शाये गए हैं वे सही हैं। कांग्रेस सरकार जो बोलती है उसको पूरा भी करती है। हम झूठी घोषणायें नहीं करते हैं। हमें इस प्रदेश की सेवा करने पर गर्व महसूस होता है। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसके लिए हमें बहुत गर्व महसूस होता है। माननीय मुख्य मंत्री जी हर वक्त काम करते हैं और कभी चुपचाप नहीं बैठते हैं। उन्होंने अपने काम के लिए हमेशा समय निकाला है। आप इस बात को सोचिए कि वे कितने अन्दाज से काम करते हैं। इससे हमारी जनता का बहुत शान मिलती है कि ऐसा मुख्य मंत्री इस प्रदेश को मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, लोगों ने इस बजट को पढ़ लिया है और वे इस बजट की सराहना कर रहे हैं। विरोध करना विपक्ष वालों की मजबूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आई.पी.एच. विभाग और बागवानी क्षेत्र के

बारे में बात करना चाहती हूं क्योंकि यह मेरा विभाग है। मेरी हमेशा यह कोशिश रही है कि पानी की स्कीमों में आ रही कमियों को दूर किया जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 19,000 नौकरियों का तोहफा दे दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बार बजट में आई.पी.एच. विभाग के लिए लगभग 2238 करोड़ रूपये का प्रावधान बिजली खर्च के लिए किया है। यह बजट आम जनता को राहत देने वाला बजट है। इससे प्रदेश में नई योजनाएं तैयार होंगी। वर्ष 2017-18 में 38 नई फील्ट्रेशन्ज़ और

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

16/03/2017/1435/RKS/AS/1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्री... जारी

83 वर्तमान इकाइयों को मरम्मत करने के लिए 20 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है। आपको मालूम है कि पिछली बार आई.पी. एच. विभाग के पानी के स्टोरेज टैंकों में बहुत गंदा पानी आया था। कई लोगों की गंदे पानी के कारण मृत्यु भी हो गई थी। यह एक बड़ी दुखदायी बात थी। मैं इसके बारे मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि हमने पानी के सभी स्टोरेज टैंकों में ताला लगाने के आदेश दे दिए हैं ताकि कोई भी स्टोरेज टैंक खुला न रहे। स्टोरेज टैंक बिल्कुल लॉक्ड होने चाहिए। यह हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा विभागीय परियोजनाओं के लिए मोनिटरिंग सिस्टम को स्थापित करने की जरूरत है और यह हमने किया भी है। अब हमें पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। पहले कुछ लोगों ने इसके लिए हमें बहुत बदनाम किया था। मैं यह कहना चाहती हूं कि कसूर किसी का नहीं होता है पर कई बार गलतियां हो जाती है। जो कमियां रही हैं उनको दूर करना हमारा कर्त्तव्य है। सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, राज्य क्षेत्र में कृषि, ग्रामीण विभाग एवं किसानों की सहभागिता से परिणाम आधारित कमान्द क्षेत्र विकास

गतिविधियां प्रारम्भ करेगा। इस कार्य के लिए 75 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इससे कृषि व बागवानी के क्षेत्र में बल मिलेगा। इससे किसानों को लाभ होगा और अधूरी योजनाएं समयबद्ध पूरी हो इसका एलान भी किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी इन चीजों के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016-17 में अधूरी पेयजलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने के लिए 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की है। 1277 बस्तियों को जल उपलब्ध हो गया है। कहीं पर कोई कमी न रहे उस पर हमें ध्यान दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 में भी लगभग 160 जलापूर्ति एवं 70 सिंचाई योजनाओं को क्रमशः 100 करोड़ रुपये तथा 60 करोड़ की लागत से पूरा किया जाएगा। हम अपने टैन्योर में हर कार्य को पूरा करेंगे। 837 करोड़ रुपये की लागत वाली विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित परियोजना द्वारा शिमला शहर में कोल डैम से 24 घंटे जलापूर्ति

16/03/2017/1435/RKS/AS/2

की जाएगी। पानी के बिना लोगों को बहुत परेशानी होती है। हमे भी शर्म महसूस होती है। पानी उपलब्ध करवाना हमारा कर्त्तव्य बनता है। हमें ठीक से काम करना चाहिए और ऐसा करने की हमेशा हमारी कोशिश रहती है। वर्ष 2017-18 में 670 करोड़ रुपये की लागत वाली ब्रिक्स न्यू डवेलपमैंट बैंक से वित्त पोषित नई पेयजल योजना का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे भी लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। जिस कार्य के लिए पैसे की जरूरत थी उस कार्य के लिए हमने बजट का प्रावधान किया है। पहले पेयजल सुविधाओं के लिए 3,267 करोड़ रुपये का प्रावधान था जिससे फेस-1 और फेस-2 में भी काम हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बागवानी के क्षेत्र के लिए

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ....जारी

बजट में 13 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। इसका लाभ सभी बागवानों को मिलना चाहिए। बागवानी के लिए बजट में 424 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हम सभी लोग कुछ-न-कुछ बागवानी करते ही हैं। हम सब जानते हैं कि किवी का फल यहां एक नया फल है। हम किवी का उत्पादन पहली बार प्लास्टिक क्रेट में करने की पहल कर रहे हैं और उसके लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। वैसे तो हमारे कई किसम के फल हैं जैसे कि सेव है, नाशपाती है। पर हम चाहते हैं कि यहां पर किवी का उत्पादन भी किया जाए। जहां तक वर्ष 2016-17 की बात है, सरकार ने बागवानी के लिए 286 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी।

सरकार ने बागवानों को उपकरणों पर उपदान की सुविधा भी जारी रखी है। इन बातों से आज बागवान खुश हैं कि उन्हें कई नई बातें करने और देखने को मिल रही हैं। पहले कई चीजों की कमी हो जाती थी जो इस बार नहीं हो पाई क्योंकि इस बार हमने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है।

हम युवाओं के लिए डिशु कल्चर की बात कर रहे हैं। उन्हें पॉली हाऊस निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके लिए युवाओं के लिए पाठ्यक्रम भी तैयार किए गए हैं और इसके लिए 3.00 करोड़ रुपये के बजट का भी प्रावधान किया गया है। मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि हर चीज ठीक से की जाए, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए और कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए। हम उनकी बातों को समझते हैं कि हमें इस तरह से चलना है। यह सोच हमें अच्छी भी लगती है।

महोदय, फसल बीमा योजना का लाभ देने के लिए भी प्रदेश भर में कार्य किया जा रहा है। इसी तरह प्रदेश भर में मौसम संबंधी जानकारी अर्जित करने के लिए सरकार की ओर से नए केंद्र खोलने की भी योजना है। बागवानों को सेव, प्लम, आड़ू और अन्य रसदार फलों

पर फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया है तथा आगे भी दिया जाएगा। इसके लिए बजट में 20.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान

16.03.2017/1440/SLS-AS-2

रखा गया है। जैसे-जैसे पैसा उपलब्ध हो रहा है, सरकार उसी तरीके से काम कर रही है।

महोदय, कुछ चुने हुए ब्लॉक्स में बागवानों को कंपनियों से पौध संरक्षण सामग्री सीधे खरीदने के लिए पायलट प्रोजैक्ट आधार पर अनुमति दी गई है। साथ ही बागवानों को ऑन लाईन उपदान सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी। इस बारे में हर बागवान को सूचित करने की हमारी कोशिश है। यह हमारा कर्तव्य है।

महोदय, चम्बा, हमीरपुर, ऊना, मण्डी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा आदि सब स्थानों पर किसानों को किवी के पौधे विकसित करने के लिए 50% उपदान दिया जाएगा। इस काम को जल्दी-से-जल्दी किया जाएगा। इसके लिए बजट में 4.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ओलावृष्टि को लेकर भी यहां चर्चा हुई है। अभी भी ओलावृष्टि चल रही है। इससे बचाने के लिए 25 लाख वर्गमीटर क्षेत्र को संरक्षित खेती के अंतर्गत लाया जाएगा। एंटी हेलगन की बात बहुत की जाती है। एंटी हेलगन एक बड़ी मुसीबत बन गई है। पूर्व मंत्री जी ने कोशिश की थी कि हम एंटी हेलगन उपलब्ध करवाएं। उन्होंने इन्हें लगाने की कोशिश की भी थी लेकिन वह केवल एक ही चली और बाकी दोनों-की-दोनों फेल हो गईं थीं। पर इस वक्त उस पर बड़ा शेर-शराबा हो रहा है। लोग कहते हैं कि लगाइए या पैसे उपलब्ध करवाइए। लेकिन इसके लिए करोड़ों रुपये कोई नहीं दे सकता। वह ज़रूरी भी नहीं है। संसार की कोई जगह ऐसी नहीं है जहां आपको एंटी हेलगन की बात मिलेगी।

जारी ..श्रीमती मन्जू द्वारा

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जारी--------

कोई भी मुल्क एंटी हेलनेट नहीं देता है। यह पहली बार हमारी सरकार ने कोशिश की है और अभी भी कोशिश जारी है। मैंने सभी बागवानों को कहा है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एंटी हेलनेट लगाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम एंटी हेलनेट पर सबको उपदान दे रहे हैं और उसको 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत कर दिया है ताकि उनकी फसल बच जाए।

युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हम उन्हें टिशु कल्चर तथा पॉलीहाउस निर्माण में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे तथा ग्रामीण युवाओं के लिए छोटे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी तैयार करेंगे और इसके लिए 3 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। "फसल बीमा योजना" के तहत प्रदेश में मौसम संबंधी जानकारी के लिए नये केन्द्र खोलने की सरकार की योजना है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कुछ ही दूरी पर जलवायु परिवर्तन से मौसम संबंधी जानकारी सही ढंग से नहीं हो रही है जिससे मौसम आधारित फसल बीमा योजना का पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। इसलिए पूरे प्रदेश में मौसम संबंधी जानकारी के लिए और केन्द्र खोले जाएंगे। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

अध्यक्ष जी, कृषि तथा बागवानी के क्षेत्रीय कर्मचारी अपना ज्यादा समय अभिलेख रखने तथा आदानों के वितरण में लगाते हैं। हम चुने हुए खण्डों में पात्र बागवानों/कृषकों को कम्पनियों से पौध संरक्षण सामग्री सीधे क्रय करने की पायलट आधार पर अनुमति देने का प्रावधान कर रहे हैं और ऐसे कृषक सब्सिडी का प्रस्ताव ऑनलाइन भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

इसी तरह से फल, फूलों तथा पौधों को विकसित करने के लिए 50 प्रतिशत उपदान दे रहे हैं तथा इसके लिए 4 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। बागवानी फसलों को

ओलावृष्टि से बचाने के लिए 25 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को संरक्षित खेती में लाया जाएगा जिसमें एंटी हेलनेट का क्षेत्र भी शामिल होगा। इसी तरह से 2 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को

16/03/2017/1445/MS/AS/2

संरक्षित खेती के अंतर्गत लाया जाएगा जिसमें फूलों और उच्च मूल्य की सब्जियों का उत्पादन होगा।

उपाध्यक्ष जी, कृषि किसानों और बागवानों की रोजी-रोटी का जरिया है और इससे उनकी आमदनी में भी इजाफा होता है। हमारी कोशिश है कि हम बागवानों/किसानों की बेहतरी के लिए अधिक-से-अधिक योजनाएं बनाएं।

मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित 1134 करोड़ रुपये की बागवानी विकास परियोजना को वर्ष 2017-18 में पूर्ण रूप से परिचालित किया जाएगा। हम इस फण्ड को विश्व बैंक से 3-4 वर्ष पूर्व लाए हैं और इसका लाभ बागवानों को हो रहा है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

16.03.2017/1450/जेके/एएस/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः..... जारी----

आने वाले समय में भी होगा। इस परियोजना के तहत बागवानी से जुड़ी तमाम समस्याओं, चाहे उत्तम किस्म का पौधा उपलब्ध करवाना चाहते हैं, वह कराइए और पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर उसको उपलब्ध भी करना है और करवाना भी है। किसानों को भी बताना है और बागीचों में भी काम करना है। सिंचाई का काम भी करना है। मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को यदि अपग्रेड करने के समाधान का प्रयोजन किया गया है, इसीलिए हमने इसको किया है। इस परियोजना को विश्व बैंक में उसके द्वारा कोशिश की जा रही है तथा आगामी छः

वर्षों में इम्प्लिमैंटेशन की जाएगी। उसके साथ-साथ परियोजना को कार्यन्वित करने हेतु प्रदेश में बागवानी क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की अपेक्षा है। मैं जानती हूं और ज्यादा समय आपका नहीं ले रही हूं। थोड़ा सा शोर्ट कर रही हूं। कोशिश कर रही हूं कि शोर्ट करूं और जो जरूरी-जरूरी है उसको यहां पर बोलूं। छोटे से मेरे अब दो प्वाईंट हैं। आपको मैं यह कहना चाहती हूं कि यहां पर हमारे सभी साथी लोग हैं हम चाहे इधर हैं या उधर हैं हम सब साथी लोग हैं। प्रदेश में कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आम, लीची और अमरूद जब आप पैदा करते हैं और इन फलों को सभी खाते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इसके भी क्लस्टर बनाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में क्या नहीं हो सकता है यहां पर सभी कुछ हो सकता है। आप लोग सभी मेहनती भी हैं और काम भी कर सकते हैं। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि हिमाचल में वित्तीय संसाधन बहुत ही सीमित हैं। यह माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुभव का ही कमाल है कि केन्द्र के असहयोग के बावजूद भी इतनी योजनाओं को मोबिलाईज करना या रोजगार के अवसर सृजित करना उस कार्य को पूरा करने के लिए बजट का प्रावधान करना भी जरूरी है, इसलिए हम चाहते हैं कि इन सब बातों को समझ लें। हो सकता है कि मेरी कहीं पर गलतियां भी हो तो ध्यान रख लें। आज मैं आई0टी0 की बात करना चाहती हूं। आई0टी0 भी आज हमारे पास बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है। हर

16.03.2017/1450/जेके/एएस/2

साल हम नम्बर-2 में जाते हैं। हिन्दुस्तान में हम आई0टी0 में नम्बर-2 में ही आते थे। अब आई0टी0 का युग है। उसका सरकार आधुनिक तकनीकी से हर क्षेत्र में प्रयास कर रही है। इसमें लड़के-लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जानती हूं कि इसमें हर क्षेत्र में प्रयास हो रहा है। इससे एफिशिएंसी आएगी वहीं ज़वाबदेही और जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करना जरूरी है। उससे वे सीख भी जाते हैं। मैं जानती हूं कि इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने लगभग हर विभाग में ई-गवर्नेंस प्रणाली विकसित की है। मैं पिछले चार सालों से देख रही हूं कि सभी कुछ ठीक चल रहा है। यही नहीं सरकार ने आई0टी0 क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से शिमला तथा कांगड़ा जिलों में STPI के माध्यम से सॉफ्टवेयर

टैक्नोलॉजी पार्क को स्थापित करने का फैसला लिया है। हम समझते हैं कि शिमला में एक सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क का काम शुरू हो । हाल ही में प्रदेश की सरकार ने स्वीकृति दी है, जिसमें कम से कम 400 आई0टी0 प्रोफैशनलिस्ट यानि जो योग्य हैं उनको रोजगार प्राप्त होगा। हम तो कांगड़ा एयरपोर्ट की भी बात कर रहे हैं कि आई0टी0 पार्क की स्थापना माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि इसको हमने जरूर करना है। इसकी घोषणा की है और वे चाहते भी हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी की धन्यवादी हूं कि जो भी काम हमने उनसे कहा उन्होंने उसको माना। हमें अच्छा लगता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप सब लोग यहां पर शांति से बैठे हैं, लेकिन यदि विपक्ष के लोग शांति से सुनें तो अच्छा रहेगा। आप लोग शांति से बैठिए। मेरा सभी सदस्यों से आग्रह रहेगा कि विरोध के बजाय एकजुट हो करके केन्द्रीय सरकार से राज्य के हिस्से में विभिन्न योजनाओं के तहत पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने का आग्रह करें।

श्री एस0 एस0 द्वारा जारी-------

16.03.2017/1455/SS-AS/1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री क्रमागतः

यह हिमाचल के विकास का प्रश्न है। यह किसका विकास है? यह आपके क्षेत्र का भी विकास है। --(व्यवधान)--- अब आप शांति क्यों नहीं रख सकते। हम आपके सामने तो कभी बोलते नहीं हैं, अगर आपको सुनना पसन्द नहीं है तो आपकी मर्जी है। परन्तु हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि यह हिमाचल के विकास का बजट है। इसमें खाली हमारा नहीं बल्कि सभी का विकास है। राजनीतिक विचाराधारा से ऊपर उठकर जो सामूहिक प्रयास किये हैं, वे होने चाहिए थे। ऐसा मेरा मानना है। अगर आप सब लोग अच्छे व्यक्ति बनते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो सभी के लिए अच्छा होगा। नहीं तो कभी खूबसूरती नहीं रहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2017-18 के लिए जो बजट पेश किया है उसमें प्रदेश का चौतरफा विकास होगा। यह हमें पूरा विश्वास है। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं। इतना ही कह सकती हूं, ज्यादा समय बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आशा करती हूं कि किसानों, बागवानों, गरीबों के लिए यह बजट है। पानी व्यवस्था सबसे मुश्किल बात है जिसको हम सम्भाल कर रख रहे हैं। आप सबका धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल।

16.03.2017/1455/SS-AS/2

उपाध्यक्षः अब श्री वीरेन्द्र कंवर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री वीरेन्द्र कंवरः माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान प्रस्तुत किये और यह माननीय मुख्य मंत्री जी का 20वां बजट था। इसमें हम सब मानते हैं कि इस प्रदेश के अंदर शासन करने और बजट प्रस्तुत करने का एक लम्बा अनुभव माननीय मुख्य मंत्री जी का रहा है। अगर हम बजट को देखते हैं तो बहुत सारी बातें बीच में कही गईं। लेकिन जब आता है कि करना कहां से है तो लास्ट में कहा गया कि 77.45 हिस्सा केन्द्रीय अनुदान, रेवेन्यू रिसीट्स से प्राप्त होगा। लेकिन जो 22.55 का हिस्सा है जिससे ही यह सब कुछ होना है वह हम लोन लेकर पूरा करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष जी, एक लम्बा अनुभव है। एक स्टेट्समैन की भावना से यह बजट प्रस्तुत होना चाहिए था। लेकिन इसमें ये सारी चीज़ें दिखती नहीं हैं। 20 वर्ष का बहुत बड़ा टाइम होता है। 20 वर्ष के अंदर छोटे-छोटे देश बहुत ज्यादा विकसित हो गए। हमारे पड़ोस में कई मुल्क ऐसे हैं जोकि हिमाचल से भी छोटे देश हैं चाहे वह दुबई या सिंगापुर है अगर हम वहां पर देखते हैं तो वहां रेत के सिवाय कुछ नहीं है, मरूस्थल है। लेकिन वे लोग हमसे बहुत ज्यादा विकसित हो गए। परन्तु हमने उनसे कोई अनुभव नहीं सीखा। हिमाचल प्रदेश में हर तरह का मौसम होता है। पहाड़ों की खूबसूरती भी यहां पर है। यहां पर पानी भी है, जहां से हाईडल जनरेशन की बहुत ज्यादा सम्भावना है। यहां पर पंजाब से लगते जो सीमांत प्रदेश

हैं वहां पर एग्रीकल्चर की सम्भावना है। हमारे यहां जो अपर बैल्ट है इसमें सेब और पर्यटन की बहुत ज्यादा सम्भावना है।

जारी श्रीमती के0एस0

16.03.2017/1500/केएस/डीसी/1

श्री वीरेन्द्र कंवर जारी----

लेकिन अगर हम देखें, राजनीतिक भावना के साथ बजट प्रस्तुत करते रहे। हमने कभी हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर कोई कोशिश नहीं की। अगर हम आज से 20-30 वर्ष पहले की बात सोचें तो उस समय भी हमारी ये ही समस्याएं थी। सड़कें हमारी जीवन रेखाएं हैं लेकिन सड़के भी नहीं थी और यहां पर पीने का पानी भी नहीं था। शिक्षण संस्थाएं नहीं थी, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी। 20 बजट प्रस्तुत करने के बाद मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान हो पाया हो। वर्ष 2007 का जब बजट प्रस्तुत किया, चुनावी वर्ष था, उस समय भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनेकों घोषणाएं की। हम समझ सकते हैं कि चुनावी दृष्टि से आप ये सारी चीजें कर रहे हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार रिपीट हो गई? मुख्य मंत्री जी जब-जब भी सत्ता में रहे, बिना बजट से संस्थाएं खोलते गए तो क्या सरकार दोबारा से सत्ता में आ गई? उनका जो यह तुज़ुर्बा था वह इन पांच वर्षों में दिखना चाहिए था। उनका अनुभव इस बजट में दर्शाया जाना चाहिए था । लेकिन हम उधार ले कर संस्थाएं खोलते जा रहे हैं। अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो इन चार-पांच वर्षों के अंदर 21 सिविल हॉस्पिटल, 34 सी.एच.सी., 29 सब सैंटर्ज़ और 45 आयुर्वेदिक संस्थान हिमाचल प्रदेश के अंदर खोल दिए गए। अरे, यह काम तो आप 20 वर्ष पहले भी बिना बजट के कर सकते थे। उस समय सारे खोल देते तो आज तक कम से कम हर जगह डॉक्टर्ज़ तो पहुंच जाते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करुं। 12-13 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं लेकिन अगर गांव के अंदर रात को फर्स्ट एड लेनी हो तो एक भी डॉक्टर नहीं मिलता। मैं धन्यवाद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने रायपुर मैदान में एक सिविल डिस्पैंसरी की घोषणा की थी । अपने चार वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने उस डिस्पैंसरी का उद्घाटन भी किया। बाकी 6 जो उद्घाटन और शिलान्यास किए, वह माननीय धूमल जी के समय की स्वीकृत योजनाओं के किए।

16.03.2017/1500/केएस/डीसी/2

जिस एक सिविल डिस्पैंसरी का इन्होंने उद्घाटन किया, आज तक उसमें डॉक्टर नहीं बैठ पाया है। वहां पर ताला लटका हुआ है। वहां पर सफाई कर्मचारी ही तैनात है शायद अब कोई फार्मासिस्ट वहां पर चला गया है। पूरे कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर एक भी ऐसा संस्थान नहीं है जिसमें रात्रि सेवा या फर्स्ट एड लोगों को मिल सके। आदरणीय धूमल जी ने सी.एच.सी. बंगाणा बनाया था। वहां पर दो करोड़ रु0 से ओ.पी.डी. का भवन भी बनाया । वहां पर 108 नं0 एम्बुलैंस भी दी गई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चार डॉक्टर वहां पर तैनात रहते थे। उससे क्षेत्र के लोगों को लाभ होता था। अच्छा होता कि विधानसभा क्षेत्र वाईज़ एक-एक हॉस्पिटल ऐसा होता जहां पर 5-6 डॉक्टर होते। वहां पर आपातकालीन सेवाएं मिलती। वहां पर ही 100 प्रतिशत सजेरियन ऑप्रेशन होते लेकिन कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर एक भी हॉस्पिटल नहीं है। रात्रि को वहां पर डॉक्टर नहीं मिलता। वहां पर अगर एक्सिडैंट्स होते हैं तो ऊना पहुंचते-पहुंचते कई लोगों की मौत हो जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं की ऐसी स्थिति है। सब सैंटरों की तो मैं बात ही नहीं करुंगा। आज ऊना जिला की भी यही हालत है। ऊना जिला का जो हॉस्पिटल है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

16.3.2017/1505/av/dc/1

श्री वीरेन्द्र कंवर ------- जारी

वह 30 साल पहले शुरू हुआ था और उसके बाद उसमें एक भी अतिरिक्त कमरा नहीं जुड़ा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी यहां से चले गये हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे विधान सभा क्षेत्र वाइज कम-से-कम एक अस्पताल ऐसा होना चाहिए जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। उसमें डॉक्टर्ज की भी पूरी स्ट्रैंथ होनी चाहिए। मैंने पिछले दिनों भी कहा कि खानागलां में गये जहां पर लोगों ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर की स्थाई नियुक्ति नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने उस पी0एच0सी0 को सी0एच0सी0 कर दिया। उसका फट्टा तो बदल गया मगर वहां पर अभी तक एक ही डॉक्टर है। वहां पर डॉक्टर्ज की पोस्टें नहीं भरी गई और न ही वहां पर क्रियेट हुई। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारा ऊना एक ऐसा जिला है जहां पर ऐक्सप्रैस हाईवेज हैं। उन हाईवेज पर बहुत सारे ऐक्सिडैंट होते हैं। मैंने पिछले बजट सत्र के दौरान एक प्रश्न के माध्यम से जानना चाहा था कि पिछले दो वर्षों के अंदर ऊना जिला के अंदर कितने रोड ऐक्सिडैंट हुए। उसके उत्तर में बताया गया था कि 280 लोगों की मृत्यु और 450 लोग घायल हुए। मैंने कहा कि इतनी ज्यादा केजुअल्टी तो पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध लड़ने के दौरान भी नहीं हुई। मैंने उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन मांगा था और कहा था कि आप उन हाईवेज के ऊपर ब्लैक स्पोट का सर्वेक्षण करवाकर उनको ठीक करवाइए। वहां पर जगह-जगह स्पीड ब्रेकर लगाइए तथा ट्रैफिक विंग को स्ट्रैन्थन कीजिए। वहां पर बाहर से जो टूरिस्ट आता है चाहे बाबा बड़भाग सिंह के लिए आता है, चाहे चिन्तपूर्णी के लिए आता है या बाबा बालक नाथ के लिए आता है। वहां पर एक अनमेनेजेबल जो ट्रेफिक आती है, वह चाहे टैम्पुओं में आती है या कई बार दस-दस मोटर साइकिल चले होते हैं और उन मोटर साइकिलों के भी साइलैंसर खोल दिए होते हैं। उनसे इतनी आवाज आती है कि आगे चले

हुए मोटर साइकिल वाले का वैसे ही घबरा कर ऐक्सिडैंट हो जाता है। कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जब ऐक्सिडैंट न हो। मगर हमें लगता है कि विधान सभा के अंदर बोलना

16.3.2017/1505/av/dc/2

और बाहर बोलना बराबर है। इस संदर्भ में एक पैसे की भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। मैं स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करूंगा। आज कांगड़ा में बहुत बड़ा मेडिकल कालेज है। मण्डी में ई0एस0आई0 का बहुत बड़ा अस्पताल बना है। शिमला में आई0जी0एम0सी0 है। लेकिन हमारे सीमान्त जिला ऊना के लिए कोई भी प्रोजैक्ट नहीं है। वहां के लिए कोई मेडिकल कालेज नहीं है। अगर कांगड़ा से पी0जी0आई0 के लिए कोई मरीज जाता है तो वह ऊना में रुककर फर्स्ट एड ले सकता है। ट्रामा सैंटर शिमला के लिए जरूरी है। आप कम-से-कम केंद्र सरकार से ऊना के लिए ट्रामा सैंटर की मांग तो कर दीजिए। गर्मियों के दिनों में जब कभी कोई बीमारी होती है तो वहां एक-एक बिस्तर के ऊपर तीन-तीन मरीज लेटे होते हैं। वहां कोई ऐसा कमरा नहीं है जिसको बाकी आने वाले मरीजों के लिए उपलब्ध करवा सकें। उसकी बिल्डिंग का विस्तार होना चाहिए। आप कम-से-कम उसके लिए प्रोजैक्ट तो भेजिए। केंद्र में बैठी नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बड़ी उदार है। आप जैसे ही उस प्रोजैक्ट को भेजेंगे वह हमारे लिए स्वीकृत होगा।

अगर शिक्षण संस्थाओं की बात करें तो उनकी भी यही हालत है। 42 नये कालेज खोल दिए और

श्री वर्मा द्वारा जारी

16/03/2017/1510/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

श्री वीरेन्द्र कंवर.... जारी।

कॉलेजिज़ की कुल स्ट्रेंथ 119 हो गई हैं। हम अपने नौजवानों को क्या देना चाहत हैं? उनके अंदर एक हुनर क्रिएट करने के लिए, जो आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने

कहा है कि हम इस देश के अंदर स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से ऐसे नौजवान पैदा करना चाहते है, जिनके पास डिग्रियां भले ही न हो, लेकिन उनके पास कोई-न कोई हुनर अवश्य होना चाहिए। ऐसे वोकेशनल इंस्टीट्यूशन्ज़ खोले जा रहे हैं, लेकिन आज बहुत सारी जगह में ऐसा है, जहां 2-2 छात्र हैं और 4-4 स्कूल लगातार उसी श्रेणी में हैं। हम उनके भविष्य को संवार रहे हैं या उनके भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। ऐसे ही वैटरिनरी हॉस्पिटल्ज़ का हाल है। हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमें उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए था। पिछले दिनों चम्बा जिला के माननीय सदस्य श्री हंस राज जी बोल रहे थे, उनसे पूर्व सिरमौर जिला के माननीय सदस्य यहां पर बोल रहे थे कि उनके विधान सभा क्षेत्रों की हालत इतनी खराब है कि वहां पर 70-70 स्कूल ऐसे हैं, जहां पर भवन नहीं हैं। आज जरूरत है कि हम अपना पैसा एडमिनिस्ट्रेटिव में खर्च करने के वजाय, इस पैसे का गरीब जनता के लिए सदुपयोग करें। हम प्रदेश के अंदर फिज़ूल खर्ची को रोकते, लेकिन हमने हमने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस के लोग बड़े-बड़े नारे लगाकर सत्ता में आये थे, लेकिन किसी भी वर्ग की समस्या का समाधान नहीं हुआ। यदि हम साढ़े चार वर्षों का कार्यकाल देखें हैं, तो जो किसानों की समस्या थी, विधान सभा चुनाव के अंदर हम जाते थे, तो कांग्रेस के लोग कहते थे, ये बंदर हमीरपुर से लाकर यहां पर छोड़ दिए हैं। हमीरपुर में कहते थे, ये बंदर मण्डी से लाकर हमीरपुर में छोड़ दिए हैं। यदि हम (कांग्रेस) सत्ता में आएंगे तो हम एक वर्ष के अंदर-अंदर इस समस्या का समाधान कर देंगे। माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले विधान सभा सत्र में मैंने प्रश्न लगाया था। ये प्रश्न संख्या 3637 था और 22-12-2016 को यह प्रश्न लगा था। मैंने पूछा था कि 2 वर्षों के अंदर सरकार ने बानर पकड़ने के लिए कितना खर्च किया है? इनका जवाब था कि 82 लाख 23 हजार रूपये बंदर पकड़ने के लिए खर्च किए हैं। आजकल ये वानर नसबंदी सेंटर मनिमेकिंग मशीन बन गए हैं। मैंने फिर पूछा कि कितने वानर पकड़े गये? इन्होंने कहा कि 19,433 वानर पकड़े गये और ऐस-ऐसी जगह पर वानर पकड़े, जहां पहले कभी वानर थे ही नहीं। उन जगहों पर आज भी वानर नहीं हैं जैसे थानाकलां, धमांदरी, नंगल-

16/03/2017/1510/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

सलांगड़ी, घंडावल, मिलाप और मदनपुर। यहां पर न तो वानर पहले थे और न ही यहां पर आज वानर हैं, तो फिर इन्होंने वानर कहां से पकड़े हैं? आज यहां पर सरकार नाम की

कोई चीज़ नहीं है। हर जगह नया घोटाला है। जब पिछली सरकार थी, ये ठीक है कि हम इस दिशा में ज्यादा कामयाब नहीं हो पाये, लेकिन हमने प्रयास किये, आदरणीय धूमल जी ने ही वानर संरक्षण पार्क बनाने की घोषणा की थी और ये पार्क बनाए भी थे, लेकिन इस जानवर की प्रवृत्ति ऐसी है कि यह एक जगह नहीं टिकता है। हम उसमें सफल नहीं हुए फिर हमने वानर नसबंदी करके वानरों की संख्या कम करने का प्रयास किया, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 4 वर्षों में कोई सत्र ऐसा नहीं है, जिसमें हमने चर्चा नहीं की।

श्रीमती एन0एस0 ..... द्वारा जारी।

16/03/2017/1515/ एन0एस0/डी0सी0 /1

श्री वीरेन्द्र कंवर ----- जारी

हमने गऊओं के ऊपर भी चर्चा की। हमने वानर नसबंदी के ऊपर भी चर्चा की है। माननीय मुख्य मंत्री जी जब इस चर्चा का उत्तर देते हैं तो वे बड़े भावुक हो करके और बड़े विशाल हृदय से जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि लंदन में एक बार कबूतर घुस गए और उनको दाना डाला गया, उस दाने के अंदर दवाई मिलायी गई, हम इसमें ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे लेकिन आज वानरों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज किसान दुःखी हैं। आज जब हम लोगों के बीच से सत्र के लिए आते हैं तो वे कहते हैं कि वहां पर जा करके यह आवाज जरूर उठाना। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हम साढ़े चार वर्ष में भाषणवाजी के सिवाय कुछ नहीं कर पाये। (घंटी) आज वही हाल गऊशालाओं का है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिए और फिर यहां पर चर्चा हुई कि गऊशालाएं कलस्टर्ज़ में खोली जाएं। हमने कितनी गऊशालाएं शुरू कर दीं और जो गऊशालाएं शुरू भी हुई, उनको 2-3 लाख रूपये की राशि दे करके तथा लोगों ने भावुक हो करके उन गऊओं को बांध भी लिया लेकिन अब वह सारी बात उनके गले पड़ गई है। वे

लोग पशुपालन विभाग के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। जिलाधीश के पास जाते हैं, वहां पर भी कोई पैसा नहीं मिलता है। आज किसानों की समस्या ज्यूं-की-त्यूं बनी हुई है। आज इस दिशा की तरफ हम कोई भी काम नहीं कर पाये हैं। यहां पर एक 'मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना' आई है। पिछली बार भी इसमें 30 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान था। इसमें कहा गया है कि किसानों को 60 प्रतिशत सबसिडी दी जाएगी। इस मान्य सदन में प्रश्न लगा और उसका जवाब आया कि इस योजना के तहत एक भी व्यक्ति ने अप्लाई नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने साल भर क्या किया? क्या आप उसकी समीक्षा तिमाही (quaterly) नहीं कर सकते थे? इसका अर्थ यही हुआ कि आप लोगों को समझाने में नाकाम रहे हैं। इस योजना में जो सोलर फैंसिंग थी, वह इतनी

16/03/2017/1515/ एन0एस0/डी0सी0 /2

महंगी थी कि उसे आम किसान अफोर्ड नहीं कर सकता था। माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर लगभग 92 लाख रूपये की राशि जो वानर पकड़ने के लिए लगाई गई है, उससे पूरे क्षेत्र की वूडलैंड की फैंसिंग हो जानी थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस इतने बड़े घोटाले की इन्कवारी करवायेंगे? कहां से वानर पकड़े गए और कहां उनको छोड़ा गया, क्या आप इसका पूरा डिटेल मंगवायेंगे? इससे तो अच्छा होता आप उस अस्पताल को ही वहां से उठा लेते। लोग अपने आप उनकी चिन्ता कर लेंगे। आप कहते हैं कि हमने इनको मारने की परमिशन दे दी है। आप यह भी तय नहीं कर पाये कि इनको कौन मारेगा? प्रदेश में जैसे खैर के पैसे मिलते है अगर वैसे ही वानरों के भी पैसे मिलते तब प्रदेश में एक भी वानर नहीं मिलना था। यह कहते हैं कि हमने वर्ष 2017-18 के लिए लक्ष्य रखा है कि हम 15,000 हैक्टेयर भूमि पर वन लगायेंगे। वन मंत्री जी आप चार साल का तो जवाब दीजिए। पहले सारे वन जला दिये और जो बचे थे, वे काट लिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। प्लांटेशन में एक भी पौधे का सरवाईवल रेट नहीं मिलता है। आज मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं कि वहां पर आजकल खैर का कटान लगा हुआ है। मुझे आज सुबह फोन आ रहे थे कि अम्बेहड़ा

धीरज पंचायत में एक तरूंग गांव है, वहां की वार्ड मैम्बर मंदिर में लाईट बंद करने के लिए गई तो उसने कुछ आवाज सुनी और उसने सोचा कि यहां पर सरकारी क्षेत्र के जंगल से कोई खैर काट रहा है, वह आगे गई और उसने उनको कहा कि आप सरकारी जंगल से खैर क्यों काट रहे हैं, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूं। उन्होंने उसका फोन ले लिया और छीना-झपटी शुरू कर दी। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी

16/03/2017/1520/RKS/AS/1

श्री वीरेन्द्र कंवर... जारी

हमने इसके बारे में विभाग को भी अवगत करवाया कि गांव कोठी व चराड़ा में खुदरो दरख्तान व वन क्षेत्र में एक भी पौधा नहीं बचा है।

Deputy Speaker: Please wind-up.

श्री वीरेन्द्र कंवरः उपाध्यक्ष महोदय, खुले तौर पर वहां लूट हो रही है। आज प्रदेश में सबसे बुरी स्थिति अगर किसी विभाग की है तो वह सिंचाई विभाग है। पीने के पानी के लिए जितनी गालियां हम आज कल सुन रहे हैं, उतनी गालियां हमने अपनी सरकार के समय में नहीं सुनी थी। 'दिव्या हिमाचल' अखबार में पिछले कल पानी के बारे में बहुत बड़ी खबर आई थी। मोमनहर पंचायत के अंदर पिछले 10 दिनों से पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। रामगढ़धार पेयेजल योजना पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। बरनोह से जो 17 पंचायतों के लिए पेयजल योजना जाती है, वहां सर्दियों के दिनों में ही गांवों में पीने का पानी नहीं है तो गर्मियों में क्या स्थिति होगी? मैंने अपनी विधायक प्राथमिकता में मोमनहर, रामगढ़धार की ऑगमैंटेशन के लिए दो डी.पी.आर्ज बनाकर भेजी थी। वे डी.पी.आर्ज. नाबार्ड में जा चुकी है। लेकिन पिछले डेढ़ वर्ष से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमैंट की हालत भी ऐसी ही है। आज क्लालिटी का स्तर गिरा हुआ है। आज बुश कटिंग और बर्म

रिपेयर के नाम पर करोड़ों रूपये का घोटाला हो रहा है। मैं केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को 61 नेशनल हाईवे दिए। मेरे क्षेत्र के दो नेशनल हाईवे भोटा-ऊना वाया लठैणी-मंदली है, जहां पर लठैणी-मंदली में पुल भी इसी पैसे से बनेगा। मेरे एक विधान सभा प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुई है। मैं इस बात से हैरान हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन की कॉपी मेरे पास पड़ी हई है। हमने कहा कि इसकी डी.पी.आर्ज. बनाइए लेकिन आज तक डी.पी.आर्ज. का टेंडर ही हुआ है। इसमें आगे की कार्रवाई नहीं हो पाई है।

16/03/2017/1520/RKS/AS/2

Deputy Speaker: Please wind-up. I am calling the next speaker. अब समय नहीं मिलेगा। पूरे 27 मिनट होने जा रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र कंवर: सर, दो मिनट। मैं वाईंड-अप कर रहा हूं। आज बहुत सारी समस्याएं हमारे क्षेत्र की हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में मिनी सचिवालय, बस-स्टैंड और रोजगार कार्यालय की घोषणाएं की है। कला संस्कृति विभाग द्वारा एक भवन समूर में बनाया जा रहा है। आदरणीय धूमल जी ने उस भवन का शिलान्यास किया था और उस समय उस भवन का काम तेजी से चला हुआ था। लेकिन आज वह काम बंद पड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वह मई-जून तक महामहिम राज्यपाल से हस्ताक्षरित होकर आ जाएगा। उसमें सिर्फ दो महीने का समय है। उसके बाद कोड-ऑफ-कंडक्ट लग जाएगा और फिर चुनाव आ जाएंगे। यह थोथी घोषणाएं हैं। यह चुनावी बजट है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने चुनावी बजट प्रस्तुत किया है परन्तु जनता नासमझ नहीं है। जनता वही जवाब देगी जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के अंदर दिया। फिर आप कहेंगे कि ई.वी.एम. मशीनें खराब थीं। मोदी जी ने ई.वी.एम. मशीनों में गड़बड़ कर दी।

Deputy Speaker: Not to be recorded now, I am calling next speaker, Shri Sohan Lal Ji.

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी..

16.03.2017/1525/SLS-AG-1

श्री सोहन लाल (मुख्य संसदीय सचिव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 10 मार्च को जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2017-18 का बजट इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है, जिसकी चर्चा माननीय सदन में हो रही है, आपने मुझे इस चर्चा में हिस्सा लेने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

जैसे कि पिछले 4 वर्षों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किए, उन्हीं बजटों की भांति यह बजट भी प्रदेश के लिए डवलपमैंट ओरिएंटिड बजट प्रस्तुत हुआ है। जैसे कि पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में विकास की एक नई गाथा लिखी गई है; विकास के हर क्षेत्र में इस सरकार ने काम किया है, उसी तर्ज़ पर इस बजट से भी, मैं समझता हूं कि आने वाले इस वर्ष में विकास के और कार्य होंगे जिससे हिमाचल प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचेगा।

गत 4 वर्षों में हमारी सरकार ने विकास के हर क्षेत्र में काम किया है। चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़कें हैं, चाहे प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की बात है या जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं की बात है, उन पर हमारी सरकार ने काम किया है।

शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि इन 4 वर्षों में हमने 42 कॉलेजिज प्रदेश में खोले जो अपने आपमें एक रिकॉर्ड है। जहां इन कॉलेजों को खोला वहीं इनके लिए पदों का भी सृजन किया और कॉलेज भवन निर्माण के लिए 5-5 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किया। बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं कि पीछे जो कॉलेजिज खुले, उनके लिए भवन निर्माण के कार्य शुरू हो चुके हैं। अभी मात्र एक महीना पहले मेरे चुनाव क्षेत्र में एक कॉलेज की घोषणा हुई, उसके लिए पोस्टें भी स्वीकृत हो गई हैं और

उसके लिए बजट भी सरकार ने मुहैया करवा दिया है। यह इस बात का सबूत है कि सरकार की केवल कोरी घोषणाएं नहीं हैं बल्कि यथार्थ में काम हो रहा है। घोषणाओं में हमारी सरकार विश्वास नहीं रखती बल्कि काम करने में विश्वास रखती है। 1328 स्कूल हमारी सरकार ने अपग्रेड किए हैं। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की तुलना पिछली भाजपा सरकार से करें तो इन्होंने अपन

16.03.2017/1525/SLS-AG-2

समय में 778 स्कूल, जो पूर्व कांग्रेस सरकार ने अपग्रेड किए थे, उनको डी-नोटिफाई किया था। 158 स्कूल तो बंद ही कर दिए गए थे। लेकिन हमारी सरकार ने इतने ज्यादा स्कूल अपग्रेड किए हैं ताकि शिक्षा का विस्तार पूरे प्रदेश में हो और उसका लाभ हर गांव, हर कस्बे में पहुंचे। हमारे विपक्ष के सदस्य कहते हैं कि स्कूल खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अब भी जब हम अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, अब भी हमारे पास लोगों के सुझाव और मांग आती है कि हमारे शिक्षा संस्थान को अपग्रेड किया जाए या वे मांग करते हैं कि हमें नया स्कूल खोल कर दीजिए। मैं समझता हूं कि जो यह कहते हैं कि स्कूल खोलने और अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है; यह तथ्यों के विपरीत है। हमने स्कूल ही नहीं खोले बल्कि इनके लिए बाकायदा 10000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति भी हमारी सरकार कर चुकी है और यह प्रासैस अभी भी जारी है। 500 के लगभग अध्यापकों की भर्तियों का प्रोसैस आजकल चल रहा है। इसके साथ जहां शिक्षा के लिए हमारी सरकार ने कार्य किया, साथ ही शिक्षा को जॉब ओरिएंटिड बनाने के लिए भी कार्य किया ताकि हमारे विद्यार्थी अपने आपमें सक्षम हों। उनके लिए रोज़गार उपलब्ध हों, इसके लिए सरकार ने वोकेशनल ऐजुकेशन का भी शुरुआत की है और 850 स्कूलों में वोकेशनल ऐजुकेशन शुरू हुई है।

जारी ..श्रीमती मन्जू द्वारा

16/03/2017/1530/MS/AG/1

श्री सोहन लाल जारी--------

इसका निश्चित तौर से हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, स्वास्थ्य जो विकास का एक अहम बिन्दु है और सीधे रूप में हर आदमी से जुड़ा है उसके ऊपर भी हमारी प्रदेश सरकार ने बहुत काम किया है। प्रदेश में 168 से ज्यादा स्वास्थ्य संस्थान अपग्रेड हुए हैं जिनमें 21 सिविल हॉस्पिटल, 34 सी0एच0सीज0, 96 पी0एच0सीज0 और 29 उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं। फिर यह कहना कि आप स्वास्थ्य संस्थान खोले जा रहे हैं और उनके लिए डॉक्टर्ज और अन्य स्टाफ का प्रावधान नहीं कर रहे हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। इन चार वर्षों में 550 डॉक्टर्ज की नियुक्तियां प्रदेश सरकार ने की हैं। इसके साथ हमारे 600 से ज्यादा स्टाफ नर्सिज और उसके अलाइड जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्तियां हुई हैं। अभी भी नियुक्तियों का प्रोसैस जारी है और 571 के लगभग और नियुक्तियां की जा रही हैं। 60 स्पैशलिस्ट्स डॉक्टर्ज प्रदेश सरकार ने इस दौरान लगाए हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि जहां हम स्वास्थ्य सेवायें बढ़ा रहे हैं वहीं डॉक्टर्ज को भी उनमें तैनात कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार का यह मानना है कि अभी जितने डॉक्टर्ज हमें चाहिए उतने उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी सरकार ने एक अच्छा और अहम फैसला डॉक्टर्ज के वॉक-इन-इंटरव्यु द्वारा लिया है ताकि जैसे ही कोई डॉक्टर आवेदन करता है उसको तुरन्त नियुक्ति दे दी जाए और डॉक्टर्ज के खाली पद भर जाएं। ऐसा केवल इसीलिए किया जा रहा है ताकि प्रदेश के लोगों को बेहतर-से-बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले। हमारा जो स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा है उसको राष्ट्रीय मानक के अनुसार अव्वल आंका गया है। हमारी शिशु मृत्यु दर प्रदेश में घटी है और राष्ट्रीय मापदण्ड में हम बेहतर साबित हुए हैं। हमारी सरकार ने कैंसर अस्पताल शिमला और मण्डी में खोला है और अब मदर एण्ड चाइल्ड स्पैशलाइज हॉस्पिटल जो कमला नेहरू शिमला में है उसके अलावा मण्डी, बिलासपुर, नुरपूर और सुन्दर नगर में भी खोलने की अधिसूचना जारी कर दी है। कुछ जगहों पर इन अस्पतालों के कार्य निर्माण स्तर पर हैं। हमें उम्मीद है कि सुन्दर नगर में भी मदर एण्ड चाइल्ड हॉस्पिटल का कार्य जल्दी

16/03/2017/1530/MS/AG/2

ही शुरू हो जाएगा। यह इस बात को दर्शाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदेश सरकार कितनी गम्भीर है। हमने नवम्बर, 2014 से 102 की मदर एण्ड चाइल्ड सेवा शुरू की है और उसके तहत 102 की 126 एम्बुलैंसिज प्रदेश में सेवाएं दे रही हैं और इसका परिणाम देखिए कि 90 हजार से ज्यादा लोग अब तक प्रदेश में इसका फायदा ले चुके हैं। हमारी सरकार ने एक कॉल के ऊपर अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है और आपको एम्बुलैंस की जरूरत है तो उसके लिए 108 की सेवा थी। पहले तकरीबन 166 हमारी एम्बुलैंसिज प्रदेश में सेवाएं दे रही थीं और अब 200 से ज्यादा एम्बुलैंसिज सेवारत्त हैं। मैं तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से अपील करूंगा कि अभी भी कुछेक पी0एच0सीज0 और सी0एच0सीज0 में लोगों की मांग रहती है जहां एम्बुलैंस पहुंचने में आधे घण्टे से ज्यादा समय लग जाता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि उन जगहों को भी इसमें शामिल करें ताकि हम ज्यादा अच्छी सेवाएं लोगों को इस माध्यम से दे सकें। शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद जो हमारे प्रदेश की मूलभूत जरूरत है, वह रोड्स हैं।

जारी श्री एस0 एस0 द्वारा----

16.03.2017/1535/SS-AS/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सोहन लाल) क्रमागतः

रोडस के ऊपर, हमारी सरकार ने 2000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण पिछले चार वर्षों में किया। हमने 200 से ज्यादा पुल प्रदेश में बनाए हैं। इससे 500 से ज्यादा जो हमारी सैंसस विलेजिज़ हैं उनको सड़कों से जोड़ा है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में भी जो गांव सड़कों से जुड़ने छूट गए हैं उनको हम इससे जोड़ें और इस वर्ष का जो हमारा लक्ष्य इस बजट के माध्यम से सरकार ने दर्शाया है उसमें सरकार ने कहा है कि हम 380 किलोमीटर मोटरेबल रोड प्रदेश में बनायेंगे। 30 नए पुलों का निर्माण प्रदेश सरकार कर रही है। 500 से ज्यादा किलोमीटर सड़कों को इस वर्ष पक्का करने का लक्ष्य

सरकार ने रखा है। मैं इसमें एक और बात कहना चाहूंगा कि यह तो मेन रोडस की बात है लेकिन जो लिंक रोडस हम किसी और माध्यम से बनाते हैं और उनका रख-रखाव प्रदेश में नहीं हो पाता था उसके लिए मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने एक नई स्कीम सड़क के निर्माण की बावत प्रदेश के लिए प्रस्तावित की है। 20 करोड़ रुपया इसमें रखा है जोकि मुख्य मंत्री रिपेयर योजना के नाम से बजट में प्रस्तावित है। मैं इसकी बधाई देता हूं क्योंकि जो लिंक रोड ब्लॉक के माध्यम से या अन्य किसी एजैंसी के माध्यम से बने हैं उनका रख-रखाव करने की बहुत ज्यादा ज़रूरत हमें महसूस होती थी, उसके लिए इन्होंने प्रावधान किया। इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। एक और अच्छी बात इस बजट में है। वह यह है कि 50 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार ने रोड सेफ्टी के लिए निर्धारित किया है। हम देखते हैं कि हमारी बहुत सारी दुर्घटनाएं सड़कों की वजह से हो जाती हैं। कई बार गाड़ी नीचे गहरी खाइयों में गिर जाती है। यदि हम इसको अपने प्लान में शामिल करें और सड़कों की सेफ्टी के लिए जो क्रैश बैरियर लगने ज़रूरी हैं वे लगाए जाएं, इसके लिए सरकार ने प्रावधान किया है। मैं समझता हूं कि यह भी एक बहुत अच्छा कदम सरकार की तरफ से है। हमारी सरकार ने मूलभूत प्रशासनिक ढांचे के लिए 14 नये सब-डिवीजन प्रदेश में खोले हैं। 16 तहसील बनाई हैं। 31 सब-तहसील बनाई हैं। अब तहसील, सब-तहसील, एस0डी0एम0 कार्यालय के माध्यम से लोगों को सीधी सुविधा सरकार से काम

16.03.2017/1535/SS-AS/2

करवाने की प्राप्त होती है। इसके बारे में भी हमारे उस पक्ष के लोग बहुत छींटाकशी कर रहे हैं कि किसलिये तहसीलें खोल दीं। आपके पास तहसीलदार, पटवारी और दूसरे लोग नहीं हैं। लेकिन जहां-जहां तहसीलें, उप-तहसीलें खुली हैं वहां आप जाकर देखिये कि उसका कितना लाभ लोगों को पहुंच रहा है। मैं इसमें अपने क्षेत्र का उदाहरण देना चाहूंगा। मेरा दूर-दराज और पहाड़ी क्षेत्र निहरी है। इसमें 1987 से सब-तहसील कार्यरत थी लेकिन वर्तमान सरकार ने इस सब-तहसील का दर्ज़ा बढ़ाकर तहसील किया। अब वहां 15 पंचायतों के लोगों को जो तहसील के माध्यम से कार्य करने होते थे, उसके लिए

सुन्दरनगर आने के लिए 100 से 150 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था, अब उनको वह सुविधा उनके गृह क्षेत्र निहरी में मिल रही है। इसका फायदा लोगों को पहुंचा है। इसी तरह मैं सरकार का धन्यवादी हूं कि मेरे यहां एक और सब-तहसील डैहर नामक जगह पर खोली गई। वहां भी सब-तहसील कार्य कर रही है और लोगों को जो 35 से लेकर 50 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता था, अब लोगों को इसके खुलने से लाभ पहुंच रहा है। लोगों को फायदा हो रहा है और

जारी श्रीमती के0एस0

16.03.2017/1540/केएस/एएस/1

मुख्य संसदीय सचिव(श्री सोहन लाल) जारी---

आप कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि फायदा हो रहा है तो आप भी अपने बजट भाषण में सरकार की इन उपलब्धियों का जिक्र करिए। सरकार को बधाई दीजिए। हमारी सरकार ने, तहसीलों की मैं जो बात कर रहा था, इसके साथ जो हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्ज़ आती थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हमें सौगात मिली थी, हमारे बहुत से पटवार सर्कलों में पटवारी की पोस्टें नहीं थी। हमारी सरकार ने इस दिशा में बहुत अहम कदम उठाया। पहले ही दो वर्षों में हमने 778 पटवारियों की नियुक्तियां की और इस वर्ष भी अभी तक, वर्ष 2016 तक 1120 पटवारियों की ट्रेनिंग चल रही है । इसके बाद उनकी नियुक्तियां हो जाएंगी। मैं दावे से कह सकता हूं कि इससे प्रदेश में कोई भी पटवार सर्कल खाली नहीं रहेगा। राजस्व मंत्री जी यहां पर बैठे हैं मैं इनको बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने कानूनगो सर्कल्ज़ की रेशनेलाइजेशन की 1 यह लोगों की सुविधा के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। जो 154 नए फील्ड कानूनगो प्रदेश में लगाए गए हैं इसका सीधा फायदा आम लोगों को हो रहा है। लोगों को असंख्य प्रशासनिक समस्याएं होती थी, तकसीम के कार्य होते थे, इनके बनने से लोगों को फायदा होगा। इसी तरह से हमारी सरकार ने परिवहन सुविधा को बढ़ाया है। 1300 से ज्यादा बसें प्रदेश की बसों का

जो फ्लीट है, उसमें शामिल की गई है। नई बसों के आने से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बसें न होने की वजह से या बसों की हालत खस्ता होने की वजह से बस रूट बन्द हो गए थे, वे रूट दोबारा शुरू हुए हैं। मैं परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पूर्व सरकार के समय में सुन्दर नगर निर्वाचन क्षेत्र में 6 रूट बन्द हो गए थे, वे सभी रूट जब हमें नई बसें मिली, मेरे सुन्दर नगर डिपो में 20 बसें हमें नई मिली और उनके मिलने से हमने छः के छः बन्द पड़े रूटों को बहाल किया, यह सरकार के अच्छे कार्यों में है। विद्यार्थियों को फ्री यातायात की सुविधा दी है इससे भी एक रेवोल्यूशनरी कार्य प्रदेश में हुआ है खासकर जो शिक्षा के लिए परिवहन की सुविधा दी गई है।

16.03.2017/1540/केएस/एएस/2

उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के मेरे साथियों ने बड़ी चर्चा की कि इलैक्शन के मध्यनज़र बजट दिया गया है और बेरोज़गारों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बेरोज़गारी भत्ता देने की बात की गई है और मात्र एक हजार रुपया कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखता। मैं समझता हूं कि एक बेरोज़गार लड़का जिसने अभी प्रोफैशनली अपने आप को स्टैंड करना है, उसने आगे की पढ़ाई करनी है या कहीं नौकरी ढूंढनी है तो उसको एक हजार रुपये का भी काफी फायदा होगा क्योंकि इसके माध्यम से उसको आने-जाने की सुविधा का फायदा होगा। न्यूज पेपर और अन्य मटिरियल के लिए वह कम से कम अपने घर वालों की तरफ नहीं देखेंगा न उनको तंग करेगा। यही नहीं इसके साथ हमारी सरकार सिर्फ बेरोज़गारी भत्ता ही नहीं दे रही है, हमारी सरकार ने युवाओं के लिए जो एक हजार नए बस परमिट देने की योजना रखी है। वह भी एक सराहनीय कदम है । इससे भी बेरोज़गार लोगों को लाभ पहुंचेगा। मैं समझता हूं कि यदि किसी एक बेरोज़गार व्यक्ति को बस परमिट मिलेगा तो

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

16.3.2017/1545/av/डीसी/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सोहन लाल) ------- जारी

तो कम-से-कम अपने 10 और लोगों को इसके माध्यम से रोजगार में सम्मिलित करेगा। सरकार ने इस दिशा में यह एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। इससे हमारे प्रदेश के नौजवानों को फायदा होगा। जो वोकेशनल ऐजुकेशन दी जा रही है उससे फायदा होगा। आप कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी ने यहां पर साढ़े चार घंटे का बहुत लम्बा भाषण पढ़ा। उस भाषण में कुछ नहीं है। नीरस है, उसमें कोई नई चीज नहीं है। यदि आपने इसका पूरी तरह संज्ञान लिया होता और पढ़ा होता तो इसमें देखते कि मुख्य मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से 14 नई स्कीमें प्रदेश के लोगों को समर्पित की हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है और इसमें विशेषकर किसानों के हित की स्कीमें रखी हैं। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और खेती-बाड़ी करते हैं। *मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना* जो पिछले वर्ष शुरू की गई थी उसमें जब यह लगा कि किसानों को सब्सिडी की राशि कम लग रही है और उसके लिए किसान आगे नहीं आए तो उसको बढ़ाकर 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत कर दिया। यह सरकार बधाई की पात्र है कि किसानों की मांग को मद्देनजर रखते हुए यह राशि बढ़ाई गई है। *मुख्य मंत्री किवी प्रोत्साहन योजना* शुरू की गई है। कृषकों और बागवानों के लिए विभिन्न उपकरणों की खरीद के लिए इस बजट में 12 करोड़ रुपपये की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। प्लास्टिक क्रेट्स के लिए भी सब्सिडी रखी गई है। हमारे किसानों ने जो पोली हाऊसिज बहुत पहले बनाये थे उनमें बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि उनकी प्लास्टिक शीट फट गई है। हमारे कई किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह उसको बदल सके। सरकार ने उस पोली शीट को बदलने का भी इसमें प्रावधान किया है और उसके लिए किसान को सब्सिडी मिलेगी। आज हमारा किसान आधुनिक तरीके से अपनी खेती-बाड़ी कर रहा है जिसके लिए वह ट्रैक्टर का इस्तेमाल भी

करता है। इसलिए ट्रैक्टर को टैक्स से पूरी तरह से ऐग्जैम्प्ट किया गया है जो कि हमारी सरकार का एक सराहनीय कदम है। आप लोगों को शायद यह बजट इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि जिन मुद्दों को आप यह

16.3.2017/1545/av/डीसी/2

समझते थे कि लोगों के बीच जाकर इलैक्शन के दौरान एजैंडा बनायेंगे तो वह बातें अब आपके हाथों से निकल गई हैं क्योंकि आप बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे थे। 14वें वित्तायोग के दौरान हमारे जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्यों के अधिकार का हनन हुआ था और उसके लिए बार-बार मांग आती थी। उनका कहना था कि हमें भी कुछ बजट दिलाया जाये और प्रदेश के कारगर विकास का हिस्सा बनाया जाए। इसलिए 42 करोड़ रुपये स्पैशली जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए रखा है और आप इस मुद्दे को आगे इलैक्शन के दौरान भुनवाना चाहते थे। हम जब लोगों से मिलते थे तो जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य कहते थे कि हमें भी इस विकास की गंगा में शामिल करो। बी0जे0पी0 वाले तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने दो हम एक-एक जिला परिषद के सदस्य को करोड़ों रुपये देंगे।

श्री वर्मा द्वारा जारी

16/03/2017/1550/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सोहन लाल)... जारी।

जो कि पूरा नहीं हुआ और जिसको हमने पूरा कर दिया। मैं समझता हूं कि हमारा जो बजट है, ये सभी तरह से विकासोन्मुखी है। इससे पूरे प्रदेश का विकास होगा। आप जो कहते हैं कि मात्र घोषणाएं हैं, कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ धीरज/ इंतजार रखने की बात होती है। जिस तरह माली पौधे को हररोज सिंचता है, लेकिन फल तभी आते हैं जब मौसम होता है। इसलिए धैर्य रखिए, हर काम पूरा होगा, हर घोषणा पूरी होगी और जो इस बजट

में कहा है, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। ये घोषणाएं वैसी घोषणाएं नहीं है जैसी पीछे 2 साल पहले की गई थी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वे अच्छे दिन आए नहीं। 15 लाख रूपया आएगा, वह नहीं आया। भ्रष्टाचार दूर करेंगे, वह नहीं हुआ। ..(घण्टी).. प्लीज़ वाइंडअप ।

16/03/2017/1550/टी0सी0वी0/ए0जी0/2

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य श्री गोविन्द राम जी आप बोलिए।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, 10 मार्च, 2017 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में 80 पेज़ का बजट भाषण पढ़ा और जिसमें से 68 पेज़ साढ़े चार घण्टे में पढ़े और 12 पेज़ सभी सदस्यों के निवेदन पर कि अब आखिरी पैरा पढ़ लें, वरना एक घण्टा और लग जाता या साढ़े पांच घण्टे लग जाते। एक बात तो माननीय मुख्य मंत्री जी माननी पड़ेगी, कोई भी व्यक्ति अगर इन 80 पेज़ों को पढ़े तो एक घण्टा 30 मिनट से अधिक समय नहीं लगता, लेकिन साढ़े चार घण्टे लग गये और एक घण्टा सभी के निवेदन पर बच गया और ये सभी को झेलना पड़ा। एक दिन टेलीविज़न पर इंटरव्यू आ रहा था, तो मुख्य मंत्री ने छाती फूला कर कहा कि अभी तो मैं जवान हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये इस उम्र में इतने जवान हैं तो जब जवान थे तो तब कैसे थे? ये खोज का विषय है। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के विदेश मंत्री थे, उन्होंने यू0एन0ओ0 में जा करके हिन्दी में अपना भाषण दिया था। जब भी हम सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, तो लिखा रहता है कि अधिक-से-अधिक हिन्दी का प्रयोग करें। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दो पंक्तियां लिखी थी, मैं प्रारम्भ से ही मुख्य मंत्री के बजट भाषण की निंदा करता हूं।

उन्होंने कहा था कि :

अपने घर में दासी, अपने घर में दासी,
बनने चली विश्व भाषा जो, अपने घर में दासी,
सिंघासन पर अंग्रेजी है, लखकर दुनियां हांसी,
लखकर दुनियां हांसी,
हिन्दी दां बनते चपरासी, अफसर सारे अंग्रेजीमय,
अवधि हो या मदरासी, कह कैदी कविराय,

विश्व की चिन्ता छोड़ो, पहले घर में अंग्रेजी के गढ़ को तोड़ो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट के आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब हमारे विपक्ष के नेता, पूर्व मुख्य मंत्री प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने अपना भाषण यहां पर दिया, तो आपने यह कहा कि ऋण ले करके घी-शकर पी करके हिमाचल प्रदेश की सेहत खराब की। आपको याद होगा कि इस देश के एक फिल्म स्टॉर हुए कादिर ख़ान। एक फिल्म में कादर ख़ान की बहुत पिटाई होती है, कपड़े भी फट जाते हैं और चेहरे पर भी चोट लगती है,

श्रीमती एन0एस0 ..... द्वारा जारी।

16/03/2017/1555/ एन0एस0/डी0सी0 /1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर----- जारी

जब वे फटी हालत में पहुंचते हैं तो दूसरा कहता है कि क्या हुआ? तब कादिर खान कहते हैं कि अरे, वे हमको ऐसे पटक-पटक के मारा जैसे धोबी धोबीघाट में कपड़े को पटक-पटक के मारता है, ठीक वैसा ही काम माननीय धूमल जी ने किया है। इसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी पैरा : 6 में कहते हैं कि भारत में विमुद्रीकरण 1946 में किया गया था और फिर 1954 में पुनः जारी हुआ। उसके बाद कहा कि फिर वापिस हुआ लेकिन इस बार यह भूल गए कि अब देश में यानि दिल्ली में भाजपा के नरेन्द्र मोदी सत्ता में बैठे हैं, जिन्होंने 8 नवम्बर को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इससे पहले हम सब कहते थे कि नरेन्द्र मोदी जी आपने काले धन के लिए क्या किया? 8 नवम्बर के बाद 9 तारीख से यह बोलना शुरू कर दिया कि अरे यह किया तो क्यों किया? ठाकुर कौल सिंह जी आपने कहा कि काला धन कब आया? केंद्र की सरकार ने पहली कैबिनेट में सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने पहले यू0पी0ए0 सरकार को कहा था कि एस0आई0टी0 का गठन करो। लेकिन 18 महीने से यू0पी0ए0 सरकार ने इसका गठन नहीं किया और इसके लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है,ऐसी खबरें आती थीं। हमारी केंद्र सरकार ने पहली कैबिनेट में दो जजों की अध्यक्षता में एस0आई0टी0 का गठन किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अभी-अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित विशेष जांच दल के डिप्टी चेयरमैन, जस्टिस अर्जित पसायत ने अभी हाल ही में शुक्रवार को कहा है कि अब तक

70,000 करोड़ रूपये की ब्लैकमनी सामने आ चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे जुड़ी छठी रिपोर्ट अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ रूपये में से 16,000 करोड़ रूपये ऐसे हैं जो ग्लोबल निक्स के बाद शुरू की गई जांच में पकड़े गए और आर्थिक और वित्तीय मामलों पर काम करने वाली कई सरकारी एजैंसियों का अधिकार इस मुलाकात के बाद तय होगें। जस्टिस पसायत ने कहा कि एस0आई0टी0 अप्रैल के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगी। जस्टिस पसायत ने केंद्र की सरकार तारीफ की है

16/03/2017/1555/ एन0एस0/डी0सी0 /2

और कहा है कि इन्होंने यह एक बहुत बढ़िया काम किया है। अभी George Washington University में पॉलिटीकल साईंस के और इंटरनैशनल मुद्दें हैं, उनके विशेषज्ञ एवं एसिस्टेंट प्रोफैसर , Prof. Adam Ziegfeld ने कहा कि आमतौर पर विधान सभा चुनाव अकेले दम पर बदलाव का संकेत नहीं देते हैं। लेकिन यू0पी0 और उत्तराखंड का चुनाव परिणाम ने दिखा दिया कि वर्ष 2014 के चुनाव अनायास नहीं थे और मोदी जी वर्ष 2019 के बाद भी भारत का नेतृत्व करते रहेंगे। अमेरिकन एंटरप्राईजिज इंस्टीच्यूट के अध्ययनकर्ता सदानंद रूमे ने कहा कि इस चुनाव ने मोदी जी को वर्ष 2019 में चुनाव के लिए स्पष्ट और पसंदीदा विजेता के रूप में खड़ा किया है। इस मान्य सदन में कहा गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आप यहां पर शिक्षा का हाल सुन लीजिए। अभी 31 दिसम्बर, 2016 को हायर ऐजुकेशन में

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी

16/03/2017/1600/RKS/AS/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर... जारी

एडिशनल डायरेक्टर बनाने के लिए डी.पी.सी. करवाई गई। डॉ0 अमर देव जी वहां पर अडिशनल डायरेक्टर थे और उन्हें अप्रूव भी किया गया था। लेकिन न जाने रातों-रात क्या हुआ? वहां पर एक ज्वाईंट डायरेक्टर है जो दो पोस्ट जुनियर है और उसका as a Joint Director दो साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ है। 1 जनवरी, 2017 को एक नोटिफिकेशन हुई जिसमें कहा The Governor, Himachal Pradesh, is please to order the posting/appointment of Shri Amar Dev, Additional Director, Higher Education, Himachal Pradesh, Shimla, as Advisor, Education, Himachal Pradesh, Shimla with immediate effect, in the public interest. 1 जनवरी को यह हुआ। 2 जनवरी, 2017 The Governor, Himachal Pradesh, is please to order that Shri Brij Lal Binta, Joint Director, Higher Education, Himachal Pradesh, Shimla, shall also hold additional charge of the post of Director, Higher Education, Himachal Pradesh, Shimla, with immediate effect, in the public interest, till further orders. यानी यह हुआ। आपने 15 जनवरी, 2017 को हायर एजुकेशन के बारे में जानकारी दी है। 'एडवाइजर एजुकेशन सैंक्शन स्ट्रेंथ-1 और पोस्ट फील्ड-1, डायरेक्टर हायर एजुकेशन-1 और वेकैंट अडिशनल डायरेकट, कॉलेज-एक।' आखिरकार इस शिक्षा का क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा :-

बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं,

है तू बहुत खुबसुरत, पर दिल लगाने के काबिल नहीं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को एक जानकारी देना चाहता हूं। गवर्नमैंट डिग्री कॉलेज, हरिपुर में कॉमर्स के 220 स्टूडैंट्स हैं। सभी क्लासिज़ के 220 स्टूडैंट्स के लिए वहां पर कॉमर्स का सिर्फ एक लैक्चरर है। दूसरा, वहां पर बी. ए., बी.कॉम., बी.एस.सी. के सभी छात्रों के लिए मैथेमैट्किस का केवल मात्र एक ही लैक्चरर है। गवर्नमैंट डिग्री कॉलेज,

हरिपुर में गर्ल्स हॉस्टल का फाउंडेशन वर्ष 2008 में प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने किया था। गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग बने हुए चार वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक वह बिल्डिंग प्रारम्भ नहीं हुई है। साइंस लैब के अंदर कोई अटैंडेंट नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रेदश के अंदर 'रूसा प्रणाली' को तुरन्त हटाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम इस प्रणाली को हटाएंगे। हिमाचल प्रदेश में सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ाई गई है जिसे वापिस लिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग का हाल भी किसी से छिपा नहीं है। मनाली जोकि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है लेकिन मनाली के सिविल हॉस्पिटल में न तो गाइनेकॉलोजिस्ट, न सर्जन और न ही ऑर्थोपैडिक्स है। वहां पर सिर्फ एक एम.डी. और एक फिजिशियन है।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

16.03.2017/1605/SLS-AG-1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर ....जारी

वहां पर यह हाल है कि 4 साल से...(व्यवधान)...क्या वहां पर गाइनेकोलोजिस्ट है, पिडियेट्रिशन है, सर्जन है? जब इतने महत्वपूर्ण सिविल हॉस्पिटल में यह पद नहीं हैं तो फिर आप क्या कह रहे हैं? वहां पर हॉस्पिटल के साथ लगती 7 बीघा भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम होनी थी। ठाकुर कौल सिंह जी, आपके 4 साल बीत गए; बताइए उसका क्या हुआ? अभी भी मनाली अस्पताल में रेडियोलोजिस्ट नहीं है। फिर आनन-फानन में आपने पतलीकूहल में एक पी.एच.सी. बना दी। पी.एच.सी. की ओपनिंग किसने की? जो वहां हमसे चुनाव हारे हैं। मैंने ठाकुर कौल सिंह जी से बात की तो इन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। वह पी.एच.सी.कहां चल रही है? एक DRDA का छोटा-सा भवन बन रहा था जिसका फाऊंडेशन हमने रखा था। अभी तक वह भवन बनकर तैयार भी नहीं हुआ। उसमें ट्वायलेट की व्यवस्था भी नहीं है। उसमें यह चल रही है। उसी तरह से कुल्लू अस्पताल है। मैं इस बजट चर्चा में आपसे निवेदन करता हूं कि सिविल अस्पताल मनाली के लिए वह ज़मीन ट्रांसफर होनी चाहिए। साथ ही मनाली में एक लेवल-2 का ट्रौमा सैंटर

स्थापित करने हेतु वहां के लिए योजना तैयार कीजिए ताकि उसकी केंद्र सरकार से मंजूरी मिले और वह काम हो जाए।

अभी पिछले कल ही PGI के संबंध में प्रश्न लगा था। आपने कहा कि सैक्टर 24-25 के हिमाचल सरायें भवन से ऐंबुलैंस के 5 चक्कर लगते हैं। मैं यह बात आपके ध्यान में लाता हूं। हिमाचल प्रदेश से हजारों मरीज़ जब PGI जाते हैं तो हिमाचल से जाने वाली 108 के अतिरिक्त कितनी ऐसी ऐंबुलैंसिज हमारे पास हैं जिनमें वैंटिलेटर लगा है? मैं आपको हाल ही की जानकारी देता हूं। कुल्लू जिला में वैंटिलेटर वाली एक ऐंबुलैंस केवल मात्र मिशन हॉस्पिटल में है। अभी पिछले दिनों 2-3 एक्सिडैंट हुए। वह वैंटिलेटर के साथ चण्डीगढ़ पहुंचाने का 22,000 रुपया लेते हैं। फिर हमारी व्यवस्था क्या है? जब भी कोई हिमाचल का व्यक्ति PGI में मरता है तो उसके आने-जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वहां से डैड बॉडी को लाने के लिए डैड बॉडी

16.03.2017/1605/SLS-AG-2

वैन नहीं है। कोई गाड़ी वहां से डैड बॉडी को लाने के लिए वहां तैयार नहीं होती। इनोवा वाले 20-25 हजार से कम नहीं मांगते। क्या वहां पर व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है? सैक्टर 24-25 में जो सरायें भवन हैं उनमें रैंप नहीं हैं, जनरेटर की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। यह सोचने के विषय हैं। आप यह भी बताएं कि 108 नंबर की कुल्लू जिला या प्रदेश में ऐसी कितनी ऐंबुलैंसिज हैं जो प्रदेश से बाहर मरीज़ को छोड़ने के लिए जाती हैं।

आप मैडिकल कॉलेज की बात सब जगह करते हैं। आखिरकार कुल्लू, लाहौल-स्पिति, पांगी, भरमौर और आधे मण्डी जिले के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या यहां के लिए सरकार मैडिकल कॉलेज बारे विचार नहीं कर सकती?

मुख्य मंत्री जी, मैं एक और बात आपके ध्यान में लाता हूं। आपने अभी बेरोज़गारी भत्ते की बात की। हम कहते हैं कि आपने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कहा था कि हम बेरोज़गारी भत्ता देंगे। साढ़े चार साल बीत गए। अब चुनाव सिर पर हैं। चुनाव के आते कई प्रकार का

प्रैशर पड़ा कि बेरोज़गारी भत्ता दो। जी.एस. बाली बोले, सुखविन्द्र सुख्खु बोले, आनन्द शर्मा जी आए। जब वह दिल्ली में केंद्र में मंत्री थे तब तो प्रदेश का औद्योगिक पैकेज भी छीन कर ले गए। 90:10 अनुपात को भी ले गए। अब आकर कहा कि यह तो हमारे चुनाव घोषणा-पत्र का वायदा है, यह पूरा करना चाहिए। आपने भी यह कहा कि चुनाव घोषणा-पत्र अनाड़ी लोगों ने बनाया था। लेकिन अब यह क्या ऐसी मज़बूरी हो गई जो यह आनन-फानन में करना पड़ा। मैं दो लाइनें आपके लिए कहता हूं। कभी-कभी हम क्या करते हैं कि जब सिर पर पेपर आता है, अग्जाम के दिनों में जल्दबाजी में हम कुछ निर्णय करते हैं। जल्दबाजी में हमें कुछ समझ नहीं आता।

जारी ..श्रीमती मन्जू द्वारा

16/03/2017/1610/MS/AS/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जारी--------

मुख्य मंत्री जी अर्ज किया है-

यह एग्जाम का रिश्ता भी अजीब होता है,
सब अपना-अपना नसीब होता,
रह जाता है जो निगाहों से दूर,
वही क्वैश्चन कम्पलसरी हो जाता है।

आज आपकी वही स्थिति हो गई है। उसके बादः-

एग्जाम के चार दिन पहले सिलैबस देखा तो याद आया, एग्जाम के पहले चुनाव घोषणा पत्र पर जब नज़र मारी तो लगा कि 1300 में से केवल 300 काम हो पाए, 1000 काम तो हुए ही नहीं। एग्जाम के चार दिन पहले सिलेबस देखा तो याद आया, कुछ तो हुआ है और कुछ

हो गया है। एग्जाम के दिन पेपर देखकर याद आया सबकुछ अलग है, सबकुछ नया है। इसलिए अब इन सारी बातों में,

अध्यक्षः माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। मनाली और कुल्लू से तो भेदभाव होता रहा है लेकिन अभी-अभी एक समाचार आया है कि अप्रैल के बाद टूरिस्ट सीजन में कुल्लू से आगे मनाली तक वोल्वो बसिज नहीं जाएंगी। जो पर्यटक किराया देकर कुल्लू पहुंचेगा क्या आगे वह टैक्सी करके जाएगा? रोहतांग जाने के लिए 800 पैट्रोल की और 400 डीजल की गाड़ियां जाएंगी लेकिन मेरा मुख्य मंत्री जी आपसे निवेदन है कि जो रोहतांग जाने के लिए गाड़ियां हैं, प्रो0 धूमल जी ने एक काम किया था और पांच साल के लिए यह कहा था कि पार्किंग और सुरक्षा की दृष्टि से रोहतांग के लिए जो 1200 गाड़ियां एन0जी0टी0 ने कही है क्यों हम एक काम ऐसा नहीं करते कि हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान टैक्सी ऑप्रेटर हैं रोहतांग के लिए वे ही पर्यटकों को लेकर जाएं ताकि उनका भी रोज़गार खुले। श्रीनगर, लद्दाख, गोवा और उत्तराखण्ड जैसे कई प्रदेशों के जो पर्यटन स्थल हैं, वहां जब किसी अन्य प्रदेश की गाड़ी

16/03/2017/1610/MS/AS/1

जाती है तो वह गाड़ी खड़ी रहती है और स्थानीय टैक्सी ऑप्रेटर पर्यटकों को घुमाता है। क्या इस बात पर आप भी विचार करेंगे? उसके साथ जो एन0जी0टी0 ने रिहैब्लिटेशन और रि-सैटलमैंट पॉलिसी बनाने को कहा था, अभी तक आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पॉलिसी को नहीं बनाया है। एक और तोहफा आपने हमको दिया है और वह यह है कि मनाली में जहां सबसे अधिक पर्यटन का काम होता है वहां डी0टी0डी0ओ0 ऑफिस के लिए स्पैशल भवन भी बना है और डी0टी0डी0ओ0 का ऑफिस वहां पर है। मनाली में 90 प्रतिशत होटल, गैस्ट हाउस और टूरिज्म एक्टिविटीज हैं और मनाली से इस ऑफिस को कुल्लू के एक-दो आपके नेताओं के कहने पर इसको कुल्लू ट्रांसफर कर दिया है। अब 90 परसेंट लोगों को कुल्लू दौड़ना पड़ता है जबकि कुल्लू में डी0टी0डी0ओ0 ऑफिस में बैठने के लिए भी जगह नहीं है। इसको भी वापिस किया जाना चाहिए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, no more. बात सुनिए। मैं अब आपको नहीं बोलने दूंगा। आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष जी, मैं इस बजट भाषण का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं क्योंकि इस बजट में किसी भी प्रकार की सोच या दिशा देने में मुख्य मंत्री जी असफल रहे हैं। विशेष तौर पर कुल्लू-मनाली से जबरदस्त तरीके से भेदभाव किया जा रहा है और आज ही एक समाचार छपा है। आपने कहा था कि एन0जी0टी0 के रोहतांग के मुद्दे पर अलग से एक स्पैशल एडवोकेट लगाएंगे लेकिन अभी तक वह भी नहीं लगा। आपको लगातार चार वर्ष कहते-कहते हो गए हैं। मुख्य मंत्री जी, वहां लोग बेरोज़गार हैं और सड़कों पर हैं। यह सब आपने किया है। अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहते हुए इस बजट का विरोध करता हूं धन्यवाद।

अध्यक्षः अब चर्चा में श्री अजय महाजन जी भाग लेंगे।

जारी श्री एस0एस0 द्वारा----

16.03.2017/1615/SS-AS/1

Shri Ajay Mahajan: Hon'ble Speaker, Sir, I rise to support the Budget presented by the Hon'ble Chief Minister on 10th March, 2017. It was his Twentieth Budget. I am proud to participate in the Budget deliberations, which shows a new light to the State's population and predominantly the rural. It looks to the new initiatives whether the jobs opportunity or State Economy. The Budget is pragmatic, inclusive and has a rural face. It is for the first time that the Hon'ble Chief Minister, Raja Virbhadra Singh has created history by delivering a highly motivated Budget speech lasting about four and a half hour. Hon'ble Prof. Prem Kumar Dhumal Ji, Leader of the Opposition and several other Hon'ble Members of BJP stated in their speeches, one after the other, that the Hon'ble Chief Minister gave the Budget Speech for four and half hour. They said it was historic in terms of time but it lack contents. I am surprised and astonished that such a senior leader, who has been the Chief Minister

twice and also remain a Member of Parliament several times, alongwith his very colleagues, fail to comprehend and understand the content of the Budget, which the common has understood and he has appreciated it highly. I would like to point out that the Budget is not a collection of numbers. It is acceptation of our values and aspirations. It is equally the quality of expenditure which is important and not just the source of availability of Rupees for development purposes, as has been pointed out by the Opposition. I congratulate the Hon'ble Chief Minister for giving such a wonderful Budget and forth consecutive tax free budget.

बहुत शेरो-शायरी चल रही थी। मैं भी इसमें एक शेर बोलना चाहता हूंः-

"परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है,
परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है,
जमीं पर बैठ के क्या आसमान देखता है।"

16.03.2017/1615/SS-AS/2

आप इसको समझा करो। शेरो-शायरी समझने वाले ही इसे समझ सकते हैं। Speaker, Sir, this Budget is an employment generation oriented budget. About 19000 functional posts, all most in all the departments, will be filled up. Some of other employment generation schemes in this Budget are as following: Being predominantly a Rural State as well as an Agricultural and Horticulture based State-this Budget has provided very well for these segments. The World Bank Aided Horticulture Development Project of 1134 cores will be made operational in the next financial year i.e.2017-2018. Mukhya Mantri Kiwi Protsahan Yojna launched with 4.00 cores for lower areas like Kangra, Una, Hamirpur, Bilaspur even the template areas of Sirmaur, Kiwi is a very important fruit and it is a new

fruit which is coming in the market. Kiwi is also of high value. It is rightly said कि मंकी मिनेस से यह दूर है। So I think it is a very good initiative for the famers of the lower areas and template areas. Rs. 12.00 crore is provided for orchardists , farmers, subsidy of power sprays and other power tillers and other equipment. New Nursery Promotion Schemes launched and this Scheme would also be an initiative for employment generation. 40% subsidies for establishing Soil Testing Labs. Covered area for construction of Poly Houses raised from 2000 to 4000 Square meters. This is very important because today the entire State is under the menace of monkeys as well as stray cattle. The erratic seasons the rain is coming in odd hours. For our rural based agriculturists and horticulturists if they deviate into Poly Houses, because there is another scheme with this where they are giving subsidy for off-season vegetables, once these both collaborated, I think this would go long way for eradicating unemployment and giving revenue to the youth of our State.

Continue in English by DC

16.03.2017/1620/केएस/डीसी/1

श्री अजय महाजन जारी -----

Because with these Poly Houses, you can control the temperature conditions; you can avoid the menace of monkeys and cattle; you can come into the market little earlier off season. You will get market price 30-40 % more than you come to the regular time .

New 'Krishik Bakri Palan Yojna' launched with the 60% subsidy will again l go a long way because most of our farmers additionally keep goats in their houses, that could be very helpful to them.

60% subsidy and new '5000 - Broiler Scheme' would again go very well with the farmers.

New scheme to provide 60% subsidy on breeding of Rams, procurement of wool increase by 10%. Milk procurement price enhanced by Rs. 1.00 per liter.

75% subsidy for setting up of milk processing and chilling plant by dairy cooperative societies. Once they are formed and come into operation this would procure milk from the farmers which would enhance the income tremendously.

100 trout units to be constructed , 800 crore new H.P. Forest Eco system Management and Livelihood Project and new Rs. 1300 crore H.P. Forest for Prosperity to be started New "Mukhya Mantri Rural Livelihood Scheme" started to provide livelihood to rural youth.

1,000 new bus permits will be given to unemployed youth. State of Art Industrial area in Pandoga and Kandrari will be made functional and once they are functional, lot of employment will be generated. Rs.10 crore provided for

16.03.2017/1620/केएस/डीसी/2

State Mission on food processing . New integration scheme for development of handloom and handicraft scheme started. Rs. 52 crore purposed to establish 6 city Livelihood centers and 4 Rural Livelihood centers. Graduate add-on programme will be started to improve the employment

potential of the youth. Rs. 100 crore kept for skill development allowance scheme which will attract the youth for skill training. Unemployment Allowance to be given to the youth having 10+2 and above qualification at the rate of Rs 1,000 per month and Rs 1,500 per month for disabled unemployed youth would be given with the budget of Rs 150 crore.

अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथियों को बहुत तकलीफ हो रही है और मैं देख रहा हूं कि जब से यह स्कीम अनाऊंस हुई है, इनको टैंशन और तकलीफ हो रही है। आपको न टैंशन होनी चाहिए और न तकलीफ होनी चाहिए। जिसने यह प्रोविज़न रखा है, यह उनकी टैंशन है। अगर आपको टैंशन होनी चाहिए तो उसकी होनी चाहिए जो चुनावों के दौरान आपने 15-15 लाख रुपया अनाऊंस किया था वह लोगों के अकाऊंट्स में कैसे पहुंचे? अगर आपको टैंशन होनी चाहिए तो इसकी होनी चाहिए कि जो करोड़ों नौकरियों का वायदा किया था, वह कैसे मिले। आपको इसलिए भी टैंशन हो रही है कि यह वायदा पूरा हो गया तो आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा। तो भाईयो, मेरे साथियो, इतनी टैंशन मत लो। जिसने यह काम किया है, उनको यह टैंशन दो। यह उनका काम है और वे इसे पूरा करेंगें। अगर टैंशन करनी है तो उसकी टैंशन करो जो आपकी दालों के रेट बढ़ गए हैं। चीनी के, गैस के, पैट्रोल के , हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं और आपको इसकी टैंशन करनी चाहिए कि इन चीजों के दाम कैसे कम होंगें। यह टैंशन मत करो कि युवाओं को कैसे रोज़गार मिलेगा। अगर मिलेगा तो क्या आप इसके अगेंस्ट हो? भत्ता देने के अगेंस्ट हो? आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। अगर कहते हो तो लिखकर दो की बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिलना चाहिए। अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो उसको करने दो। आप उसका फिक्र

16.03.2017/1620/केएस/डीसी/3

करो जो लोगों का आजकल बुरा हाल हो गया है। हर चीज़ आज मंहगी हो गई है। मुझे नहीं समझ आता कि इंटरनेशनल मार्किट में पैट्रोल के रेट नीचे आ रहे हैं और हिन्दुस्तान में क्यों बढ़ते जा रहे हैं? डीज़ल के रेट नीचे आ रहे हैं और हिन्दुस्तान में बढ़ रहे हैं। यह कैसे

हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? यह क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी चिन्ता करो। Many incentives have been given in the Health Sector and social welfare sectors. New scheme to provide free Insulin to Type -I diabetes patient up to 18 years of age. Special efforts to develop Cancer Treatment Facility in the State. Critical Care Package for cancer patients enhanced from Rs. 1 lakh 75 thousand to Rs. 2 lakh 25 thousand.
सोशल सिक्योरिटी की बात करुं, आपके समय में सोशल सिक्योरिटी पैंशन साढ़े चार सौ रुपये होती थी और सतरा हजार पांच सौ रु0 लिमिट थी ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

16.3.2017/1625/av/as/1

श्री अजय महाजन------- जारी

और लोग पटवारियों के चक्र लगा-लगाकर थक जाते थे मगर किसी को कोई पेंशन नहीं मिलती थी। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करता हूं, वहां पर सारी नई पेंशन कैंसिल कर दी गई मगर माननीय मुख्य मंत्री जी आए और इन्होंने उनके लिए प्रोविजन रखा तथा लोगों को पेंशन मिलनी शुरू हुई। 80 साल से ऊपर के लिए पहली बार इनकम क्राइटीरिया खत्म कर दिया गया। (---व्यवधान---) जब आप बोलते हैं तो हम बिल्कुल नहीं बोलते और यहां पर मजाक की बात नहीं चली हुई। हम बजट के ऊपर सीरियस स्पीच दे रहे हैं। मैं कोई चुनावी भाषण नहीं दे रहा हूं। (---व्यवधान---) आप (श्री हंस राज) प्लीज सुन लीजिए। 80 साल के लिए जो लिमिट खत्म की उनके साथ अकसर ऐसा होता था कि उनके बच्चे उन्हें पैसा नहीं देते थे। यह एक बहुत बड़ी इन्सानियत की बात हुई। जब से यह लिमिट खत्म हुई उसके बाद बहुत से बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिली। I am thankful to the Hon'ble Chief Minister for such a good gesture. उसके बाद 1200 रुपये से 1250 रुपये किए जो कि बहुत अच्छी बात है। 45 साल से नीचे की विधवा बहनों का 1200 रुपये कर दिया। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर

मुमकिन हो तो इस ब्रैकिट में सभी विधवाओं को लाया जाए। जब कोई विधवा 45 साल से ऊपर हो जाती है तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। आपने यह बहुत ही सराहनीय काम किया है जिसके बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा था। आप अगर इस बारे में प्रावधान कर सकें तो हम आपका शुक्रिया करेंगे। जहां तक मैंटली रिटार्डिड (---व्यवधान---) हंस राज जी, सुन लीजिए। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। मैं बजट के ऊपर बोल रहा हूं और कोई चुनावी भाषण नहीं दे रहा हूं। हमारे जो मैंटली रिटार्डिड बच्चे हैं उनके लिए भी इनकम का क्राइटीरिया समाप्त कर दिया जो कि आपकी तरफ से एक बहुत ही सराहनीय कदम है। (---व्यवधान---) आपने एम0एल0ए0 के लिए पहले 50 लाख रुपये की राशि की थी और अब बढ़ाकर 1.10 करोड़ रुपये की है। लेकिन जब इनकी सरकार थी तो they were very insensitive to this. अब जब आपने कर दिया और हमने इनसे कहा कि आपका धन्यवाद करें तो कोई दबी

16.3.2017/1625/av/as/2

जुबान में कर रहा था तथा कोई हंस रहा था। अब तो आप लोग (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा।) धन्यवाद कर दो। आपको 5 लाख रुपये डिस्क्रिशनरी ग्रांट के रूप में दी है। क्या आपके समय में इसमें एक भी पैसा मिलता था? आप मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद कीजिए। आपके नाबार्ड के तहत विभिन्न स्कीमों के लिए 70 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 80 करोड़ रुपये कर दिए और यह भी मुख्य मंत्री जी का एक प्रशंसनीय कदम है। आपने इसके लिए यह नहीं देखा की भाजपा का है या कांग्रेस का है, आपने सबको बराबर रखकर दिया। अं----(---व्यवधान---) आप लोग इस सदन की थोड़ी गरिमा रखें। यहां पर इतने वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं और कोई नहीं बोल रहा है।। request you अगर मैं गलत बात बोलता हूं तो आप मुझे टोक सकते हैं मगर जब मैं फैक्ट्स पर बोल रहा हूं तो उसको आपको सुनना चाहिए। बी0पी0एल0 में पहले एस0सी0 और दूसरी केटेगरी को लिया जाता था तथा जनरल केटेगरी वाले उससे बाहर रखे जाते थे। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में जनरल लोग हमसे पूछते थे कि क्या हम गरीब नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने एक नई स्कीम शुरू की है जिसके अंतर्गत जनरल केटेगरी के गरीब लोगों को भी घर मिलेंगे जो कि सराहनीय कदम है। जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्य

चुनकर आते हैं। मुझे नहीं पता केंद्र सरकार इनके लिए क्यों इनसैंसटिव थी। (---व्यवधान---) आपको (श्री वीरेन्द्र कंवर) जब पता ही नहीं है तो चुप बैठिए। 14वें वित्तायोग ने पंचायत के प्रधानों को तो पैसे दे दिए मगर जिला परिषद और बी0डी0सी0 के सदस्यों के पैसे काट दिए।

श्री वर्मा द्वारा जारी

16/03/2017/1630/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

श्री अजय महाजन ... जारी।

उन्होंने रिक्वैस्ट की, हमारे रूरल डेवैल्पमेंट मिनिस्टर और माननीय मुख्य मंत्री जी ने सेंटर को भी लिखा कि इनको पैसे मिलने चाहिए, लेकिन नहीं मिले। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, इन्होंने उनके लिए 43 करोड़ रूपये का बजट रखा है, जो ये नहीं कर सके, आपने वह करके दिखा दिया। सर, ये फैडरल सिस्टम है। सेंटर की सरकार अलग होती है, स्टेट की सरकार अलग होती है और सेंटर सरकार के पैसे अलग होते है और राज्य के पैसे अलग होते हैं। जैसे मेरे साथियों ने ठीक कहा, This is federal structure , taxes are collected from the State, जो सेंटर गवर्नमेंट हमें पैसा देती है, वह कोई एहसान नहीं करती है। That is in the Constitution . ये भी उसका एक पार्ट था, अगर नहीं दिया they should have given it कि उन्होंने कर दिया it was the need of the people. सर एक बहुत बड़ी डिस्कशन हुई 61 roads given by the Centre to the State. I want to put on record certain facts. Hon'ble Speaker, Sir, many Members of the Opposition have mentioned that the State Government has not prepared DPRs for the 61 'in principle ' new National Highways . Sir, Hon'ble Ex- Chief Minister has quoted Shakespeare " Much Ado about nothing" and also want to repeat the adage" Much Ado about nothing"! Criticism regarding non preparation of DPRs is far from the truth. The facts are that the Consultants are to be appointed by the Government of India for this. There is a detailed process which I want to put before this August House.

1. The Consultant will prepare the land accusation plan, surveying, estimate and bridge design along with other engineering requirements and details in the DPR.
2. The payment of the Consultant will be released by the Government of India only.
3. The State Government has to re-invite the tenders on account of changed norms or guidelines of Government of India dated 22.08.2016.

16/03/2017/1630/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

4. The State Government has been pro- active in taking steps to ensure expeditious appointments of the Consultant. Already on 17 roads technical and financial bids have been opened. For 42 cases, tender are invited for the 3rd time by the State PWD for the reason of single tender or other norms which again are made by the Central Government.

Sir, now let me talk about the status of DPR preparation capacity, I congratulate the Hon'ble Chief Minister for the preparation of DPR under PMGSY. 5000 crore has been sanctioned under PMGYS from the year 2000 onwards. Out of which Rs. 2241 cores, i.e. 46%, has been sanctioned during the year 2013-14 and 2016-17. During the tenure of this Government the State has received over Rs. 1800 crore for PMGYS roads, which includes the special incentive for the performance. This shows the efficiency of the Government. I wish to remind to all that the DPRs were prepared by the HPPWD.

Further, Sir, I wish to compliment the Hon'ble Chief Minister for the Phase-II of the World Bank (State Road Project) which has been approved. I am thankful that the Jawalaji- Dehra- Nagrota Surian- Jawali Damtal Road, has also been identified under that project for upgradation.

Sir, while work on Four Lane projects from Kiratpur - Manali, Parwanoo to Solan, are in progress and work of over Rs. 10,000 crores is in progress. However, there is an issue which I want to bring to the notice of the August House , regarding maintenance of the roads proposed for the four lane by the National Highway Authority of India namely, Pathankot - Palampur- Mandi, Shimla - Mataur and Baddi - Nalaghar road. While process of land acquisition, preparation of DPR and construction of roads would take 4 to 7 years horizon. It is essential that the funds for maintenance are provided to the State Public Works Department, till such time that work will not be commenced. Otherwise this entire network of roads will deteriorate as has been our experience on NH-22 (Kiratpur-Manali road) and NH-21 (Parwanoo -Shimla Road).

16/03/2017/1630/टी0सी0वी0/डी0सी0/3

Unfortunately, the funds for maintenance for these roads has been stopped. I would request the Hon'ble Chief Minister and our colleagues and senior leaders on the BJP side to take it up with the Central Government otherwise this will lead to a very disaterious state of affairs . After a couple of years till the new roads are started and old roads are not maintained.

Sir, all-round development of the State is best reflected in the rise of per-capita income which now stands at Rs. 1.47 lakh per person, compared to the national figure of Rs. 1.00 lakh per person. Similarly, the GDP growth of the State at 7.4% is also higher than the national figure of 6.8%. This is a symbol of the fact of sponsored schemes, investment and growth in Agriculture and Horticulture sector.

श्रीमती एन0एस0 ..... द्वारा जारी।

16/03/2017/1635/ एन0एस0/डी0सी0 /1

श्री अजय महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने चुनाव क्षेत्र नूरपुर की बात करना चाहता हूं। नूरपुर एक बहुत महत्वपूर्ण विधान सभा क्षेत्र है और यह बॉर्डर पर स्थित है।

अध्यक्षः आप प्लीज़ संक्षेप में कहिए।

श्री अजय महाजनः पहले जब भाजपा की सरकार थी तो उस समय नूरपुर से बहुत अनदेखी हुई है। मैं अपनी बात पहले स्कूलों से शुरू करना चाहूंगा क्योंकि इस मान्य सदन में स्कूल खोलने के ऊपर बहुत शोर-शराबा हुआ है। इन्होंने कहा कि बहुत स्कूल इस प्रदेश में खोल दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जब विपक्ष की सरकार थी तो नूरपुर में पांच साल में एक स्कूल ठेड़कुठेड़ में अपग्रेड हुआ था और वहां पर स्टॉफ भी नहीं था। जब हमारी सरकार सत्ता में आई तब वहां पर स्टॉफ भेजा गया। पिछले चार सालों में मेरे क्षेत्र में 35 स्कूल अपग्रेड हुए हैं और हर स्कूल में स्टॉफ मौजूद है। मैं मुख्य मंत्री महोदय जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे वहां पर जो छोटे-छोटे बच्चों को कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था लेकिन अब उनको अपने घरों के पास ही शिक्षा मिल रही है। यह बहुत बड़ी बात है। हमारे नूरपुर के कॉलेज के लिए 23 करोड़ रूपये की राशि सैंक्शन हुई है। उसका भी अभी माननीय मुख्य मंत्री जी शिलान्यास करके आए हैं। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के स्कूलों में कॉमर्स और साईंस की क्लासिज खुल गई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों में जब भाजपा की सरकार थी, एक बड़ी विचित्र और विडम्बना की बात है, मेरे पिता जी स्व0 श्री सत्त महाजन जी और माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने मिनी सचिवालय का नींव पत्थर रखा था, पांच साल गुजर गए लेकिन उसके ऊपर एक ईंट नहीं लगी। उसके बाद जब मैं विधायक बन करके आया तो उसकी एक तरफ स्टोन लगा हुआ है कि श्री सत्त महाजन और श्री वीरभद्र

सिंह जी और दूसरी तरफ अब स्टोन लगा हुआ है inauguration अजय महाजन और श्री वीरभद्र सिंह जी। वहां पर पिछले पांच सालों में

16/03/2017/1635/ एन0एस0/डी0सी0 /2

एक ईंट नहीं लगी । वहां के सारे काम बंद थे। सीवरेज का काम बंद था लेकिन हमारी सरकार के समय में अब उसका काम नूरपुर में चला हुआ है। भाजपा के समय में वहां पर सड़कों का बिल्कुल काम नहीं हुआ है। वहां पर मनरेगा के माध्यम से सड़कों का काम होता था। आज वहां पर लगभग 125 करोड़ रूपये की राशि से सड़कों का निर्माण कार्य चला हुआ है। वहां पर पांच पुल बन करके चालू हो गए हैं। सभी सड़कें लगभग बन करके तैयार हो गई हैं। जहां तक पानी की बात है तो लारे और नारे तो बहुत होते थे। भाजपा की सरकार ने वहां पर एक भी काम नहीं किया था। उन्होंने वहां पर एक होटल खोला था। यह होटल भी पांच साल बंद रहा था। अब दोबारा से उसकी शुरूआत हुई है। वहां पर कई टैंक बन गए लेकिन सोर्स का कोई प्रोवीजन नहीं रखा गया। अब लगभग 12 करोड़ की लागत से गम्भीरी स्कीम, बदाईं की स्कीम, खन्नी की स्कीम इत्यादि बनी हैं, इसकी मेरे पास बहुत लम्बी लिस्ट है, इन सबका काम युद्ध-स्तर पर चला हुआ है। नूरपुर शहर के लिए चार करोड़ की पार्किंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वार्ड नम्बरः 2 में भी पार्किंग का काम चल रहा है। बस स्टैंड का काम भी युद्ध स्तर पर चला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं अस्पतालों की बात करना चाहता हूं। नूरपुर में पहली बार एन0डी0आर0एफ0 तैनात हुई है। उसमें 2 से 40 की तैनाती होगी। बजीर राम सिंह जी के नाम पर स्टेडियम का काम शुरू हो रहा है। बी0एम0ओ0 का ऑफिस वहां पर शिफ्ट हो गया है। माइनिंग का ऑफिस नूरपुर और धर्मशाला में बन गया है। सर, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे लोअर एरियाज़ में किन्नू, आम और संतरे की ज्यादा पैदावार होती है।

श्री आर0के0एस0----जारी।

16/03/2017/1640/RKS/AS/1

श्री अजय महाजन... जारी

नूरपुर के पास सारे एरिया के लिए कोल्ड स्टोर बन जाए क्योंकि हमारे फार्मर्ज का एक्सप्लॉयट किया जाता है। यह पेरिसिबल प्रोडक्टस हैं यदि आप इसके लिए कुछ करेंगे तो I will be very grateful to you. Hon'ble Speaker, Sir, I am surprised that my friends in the opposition have not been able to see the stamp of human consideration for which Shri Virbhadra Singh is known for. His vast experience and sentiments are effected in every para and every line of the Budget. I want to remind you that many of us were not born when Shri Virbhadra was sitting alongwith the Late Pt. Jawahar Lal Nehru and other stalwarts of Indian politics. I may remind you that when he was a Member of Parliament, he took part in the historic debate on the merger areas of the Punjab into Himachal. If he not made this historic speech in the Parliament, we could not have these 68 Vidhan Sabha Constituencies in Himachal Pradesh. Sir, this is a growth oriented, employment oriented, pro-poor, development oriented Budget and has taken care of all segments of the society. This Budget is going to stimulate the Economy of the Himachal Pradesh. It is basket, full of benefits. It has increased the pensions of many segments of the society and taken care of farmers, poor people, traders, students, employees, retired employees, Ex-servicemen and above all the unemployed youth. I congratulate the Hon'ble Chief Minister for presenting a progressing and humane Budget benefiting all sections of the society. It is prelude to a brighter Pradesh in the coming years. With these words, I support the Budget. सर, अंत में मैं एक शेर राजा वीरभद्र जी की तरफ बोलना चाहता हूंः-

16/03/2017/1640/RKS/AS/2

"नजर-नजर में उतरना कमाल होता है,

नफ़स- नफ़स में बिखरना कमाल होता है,
बुलंदियों में पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है,

आपकी क्या मिशाल दें सबको, यह हकीकत है बेमिशाल हैं आप" ।

विपक्ष की तरफ भी मैं कुछ बोलना चाहता हूंः-

"छोटी-छोटी बातें करके कहां बड़े हो जाओगे, छोटी-छोटी बातें करके कहां बड़े हो जाओगे,
पतली गलियों से निकलो तो खुली सड़क पर आ जाओगे" ।

16/03/2017/1640/RKS/AS/3

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री विजय अग्निहोत्री जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विजय अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, 10 मार्च, 2017 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने साढ़े चार घंटे तक यहां पर बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं।

Chief Minister: Don't be with others. If you want respect, respect others.

अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि कल माननीय मुख्य मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे और सभी माननीय सदस्यों को बोलने का समय नहीं मिलेगा इसलिए आप अपनी बात संक्षेप में कहिए। (व्यवधान)... मैं सभी माननीय सदस्यों को बोल रहा हूं।

श्री विजय अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने कुछ भी नहीं कहा था परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी पहले ही बुरा मान गए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने साढ़े चार घंटे के लगभग

बजट अनुमान पढ़े और इस सदन में इन्होंने 20वीं बार बजट प्रस्तुत किया है। समय के हिसाब से तो यह एक रिकॉर्ड हो सकता है

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

16.03.2017/1645/SLS-AS-1

श्री विजय अग्निहोत्री ....जारी

लेकिन इसके माध्यम से अगर कहीं पहुंचने की बात हो तो वह बिल्कुल शून्य है। कई लोगों ने कहा कि इस बजट बुक में कुछ नहीं है; यह किसी काम की नहीं है। मुझे लगता है यह बहुत काम की है। अध्यक्ष महोदय, जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि आप विधान सभा में गए थे, आपने जंगली जानवरों को रोकने के लिए क्या किया; उसके लिए क्या योजना है? लोग कहते हैं कि हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, इनके बारे में आप क्या कर रहे हैं और विधान सभा से आप क्या लेकर आए हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि यह बजट बुक बहुत काम की है। हमें 10-20 यह और दे दें, फिर हम इसे सड़क वालों को भी दे देंगे और वानरों को भी बता देंगे कि आपके लिए इसमें बाड़ लगाने का प्रावधान कर दिया है, इस करके आप हमारे खेतों में मत आओ। बजट में आवारा पशुओं के लिए गौशाला खोलने का प्रावधान कर दिया है, इसलिए आप सड़कों में मत घूमो। यह किताब पढ़ो और हमारा नुकसान मत करो।

हमें भी इस सदन में 4 साल से ज्यादा का समय हो गया। यहां पर दिशाहीन तरीके से बजट अनुमान प्रस्तुत होते हैं। हमारी कोई दिशा नहीं है; प्राथमिकता नहीं है। प्रदेश को हम कहां ले जाना चाहते हैं, यह इसमें प्रदर्शित नहीं होता। मैंने जंगली जानवरों की बात की। पिछले साल इन्होंने कहा कि हम करंट वाली बाड़ लगा रहे हैं जिसके लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी देंगे। लेकिन एक भी किसान उसको लगाने के लिए आगे नहीं आया। हमने क्या यह बजट बुक ही लोगों को दिखानी है? इस बार यह सब्सिडी 80 प्रतिशत कर दी गई है। हमने गांवों में जाकर किसानों के साथ बैठकर उस समस्या के हल की क्या कोशिश की? आज तक कृषि विभाग उसके लिए क्या करता रहा? व्यक्ति को खेत तक पहुंचाने के लिए हमने कौन-सी ऐसी नीति बनाई जिसके कारण प्रदेश का किसान सोचे कि मैं खेती करूंगा और मुझे मेरी उपज का ठीक मूल्य मिलेगा और फसल बर्बाद होगी तो मुआवजा मिलेगा। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कृषि बीमा योजना आरंभ की, हम उसका भी लाभ नहीं उठा सके। हमने खेतों में बाड़ लगाने की घोषणा तो कर दी लेकिन हम उस चीज़ को

16.03.2017/1645/SLS-AS-2

धरातल तक पहुंचाने में कहां तक कामयाब रहे, उस विषय में हमने कभी चिंता नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में आज हर व्यक्ति खेती छोड़ने को मज़बूर हो रहा है। हमने उनको उचित सिंचाई की व्यवस्था देने की कोशिश नहीं की। 4 वर्ष पहले इसी बजट बुक में कहा गया था कि मुख्य मंत्री कृषि विकास योजना शुरू की गई है और हर चुनाव क्षेत्र से एक-एक पंचायत को हम एक-एक साल में विकसित करेंगे। मैं पिछले वर्ष अधिकारियों के पास वहां गया कि इस बार आपने हमसे पूछा ही नहीं कि आपकी कौन-सी पंचायत उसमें डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि योजना बंद हो गई है। अब आपने नई खेत संरक्षण योजना ला दी। उसके पश्चात आप कोई और योजना ले आएंगे। लेकिन उस योजना का हमें क्या लाभ हुआ, क्या हमने सारी पंचायतों को विकसित कर दिया? हम किसानों तक बीज तक पहुंचाने में नाकामयाब रहे हैं। आज जंगली जानवरों का क्या हुआ? आप बंदर लेकर जनसभाओं में जाते थे कि अगर इनसे प्रदेश को बचाना है तो कांग्रेस को वोट दो। लेकिन

उसके बाद क्या हुआ है? आज बंदरों की संख्या बढ़ी है और उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। आदरणीय वीरेन्द्र जी बता रहे थे कि बंदर कहां से पकड़े गए और कहां छोड़े गए। पता नहीं इसमें क्या हो रहा है? यह सारा कुछ गोल-माल हो रहा है। आज प्रदेश में खेती की ज़मीन को ठीक करने के लिए लैंटाना इरैडिकेशन हेतु जो बजट आता है वह बजट कहां लगता है, कहां से आ रहा है कहां जा रहा है, लैंटाना कहां उखाड़ा गया है इन बातों का कुछ पता नहीं है। आज प्रदेश को एक दिशाहीन सरकार का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पिछले 4 वर्षों से न तो इस प्रदेश का किसान सुखी है न युवा सुखी है, न महिलाएं सुखी हैं, न कर्मचारी सुखी है और न ही कोई विकास का काम ठीक डायरैक्शन में गया है।

जारी ..श्रीमती मन्जू द्वारा

16/03/2017/1650/RG/AS/1

श्री विजय अग्निहोत्री----जारी

और न ही यहां के पर्यटन को कुछ मिला है, चाहे किसी भी क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लें, उसमें कुछ नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कहां तक पहुंची हैं? हम बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते हैं। हमने यह मैडिकल कॉलेज शुरू कर दिया, वह कर दिया। लेकिन हमीरपुर मैडिकल कॉलेज के लिए ये आज तक जमीन भी नहीं देख सके। जब यहां प्रश्न होता है और कोई पूछता है कि हमीरपुर का मैडिकल कॉलेज क्यों नहीं शुरू हो पा रहा है, तो स्वास्थ्य मंत्री जी उठकर कहते हैं कि मैंने माननीय धूमल जी को कहा था कि आप अगर हमें वह-वह या वह चीज उपलब्ध करा दें, तो हम आपका मैडिकल कॉलेज शुरू कर देंगे। जब हमने ही सब कुछ उपलब्ध करवाना है, तो ये वहां किसलिए बैठे हैं? हमने इनका विरोध कहां किया है कि ये किस चीज को लेना चाह रहे हैं। आदरणीय धूमल जी ने तो कहा था कि स्कूल की बिल्डिंग ले लो और वहां आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र की जो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, आप उसको लें और शुरू तो करिए। लेकिन यह शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं। आज नदौन की सी.एच.सी. की वह हालत है कि आदरणीय धूमल जी ने वहां बजट का

प्रावधान करके सी.एच.सी. के भवन का शिलान्यास किया था, उसके ऊपर काम चला था और उस समय तक जो काम उस पर हुआ, वहीं तक वह सीमित है, लेकिन अब वह बंद पड़ा है। अब उसके लिए पैसा भी आ गया है, लेकिन वह पैसा वहां नहीं लगता और वह काम नहीं होता है क्योंकि इनकी इच्छाशक्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यहां वीरेन्द्र कंवर जी कह रहे थे कि एक-एक बैड पर तीन-तीन मरीज हैं। लेकिन सी.एच.सी. नदौन की हालत यह है कि मैं एक दिन गया, तो लोगों ने कहा कि एक बैड पर तीन की बात छोड़िए, हम तो बैड भी घर से लेकर आए हैं। वहां की व्यवस्था क्या है? नदौन के सी.एच.सी. में मरीज आता है, उसका वे इलाज नहीं कर पाते, उसको रैफर करना होता है, तो वहां से वे टांडा के लिए रैफर नहीं करते बल्कि हमीरपुर के लिए रैफर करते हैं और जब वह मरीज हमीरपुर में पहुंचाता है, तो हमीरपुर वाले उसको फिर टांडा रैफर करते हैं। हमने कहा कि मरीज को आप सीधे ही टांडा रैफर कर दिया करो। आप उनको यह अधिकार दें। क्योंकि वहां उनको ऐम्बूलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। पी.एच.सी., कांगू के भवन को बने हुए 3-4 साल हो गए। मैंने कई बार प्रश्न किया, तो उसको कब तक कम्पलीट करके जनता के सुपुर्द दिया जाएगा, लेकिन आज

16/03/2017/1650/RG/AS/2

तक आप यह नहीं कर सके। आज वहां डॉक्टर्ज की हालत दयनीय है। वहां चिकित्सक नहीं टिकते हैं। पूरे प्रदेशभर में आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि हमें विशेषज्ञ लोग नहीं मिलते हैं, हमें चिकित्सक नहीं मिल रहे हैं इसलिए हम वॉक-इन इन्टरव्यू कर रहे हैं। एम.सी.आई. ने पीछे एक छूट दी थी और पी.जी. छात्रों की संख्या बढ़ाई थी। उन्होंने कहा था कि हर प्रोफेसर तीन छात्र ले सकता है और ऐसोशियेट प्रोफेसर के अण्डर दो छात्र पी.जी. कर सकते हैं और असिसटैंट प्रोफेसर जिसको पांच साल हो गए हैं वह एक पी.जी. का छात्र रख सकता है। लेकिन हमने उस दिशा में कोई काम नहीं। क्या हमने इसको फौलो किया? क्या हमने उस छूट का लाभ उठाया? क्या हमने उतने छात्र पी.जी. के लिए रजिस्टर किए? हमने नहीं किए। डॉ. राजीव सैजल जी ने पूछा था कि यहां किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्यों नहीं हो पाता है? तो इन्होंने कहा कि हमारे पास इसके विशेषज्ञ नहीं हैं। आपके पास विशेषज्ञ कहां से आएंगे जब आप पैदा ही नहीं करेंगे? जब सुनहरे अवसरों का फायदा नहीं उठाएंगे, तो कहां से मिलेंगे? स्वास्थ्य की इतनी बुरी हालत है कि हम कहते हैं कि एन.आर.एच.एम. के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। आपका स्मार्ट कार्ड बन गया और

आपको पौने दो लाख रुपये इलाज के लिए मिलेगा। लेकिन जब गांव का व्यक्ति अस्पताल जाता है, तो उसको कोई लाभ नहीं मिल पाता। आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। आज कैन्सर का व्यक्ति पी.जी.आई. में जाकर धक्के खाता है, उसको बोलते हैं कि तेरा आई.आर.डी.पी. का स्मार्ट कार्ड यहां नहीं चलता है। तो हम आम आदमी या गरीब आदमी को सहायता देने के लिए सेवाएं देने के क्या कर रहे है? हमें यह सोचना चाहिए। हम पैसा देखते हैं और उस पैसे को बांटते हैं। इतना इसको दे दिया, इतना उसको दे दिया, इतना इस विभाग या उसको दे दिया। लेकिन हम उस विभाग में जाकर यह नहीं देखते कि वह पैसा कहां लग रहा है और कहां तक काम पहुंचा है। क्या कभी इसका फौलो अप लेते हैं? चाहे आप कोई भी योजना देख लीजिए।

अध्यक्ष महोदय, आज सड़कों की हालत देखिए। कहते हैं कि इतने करोड़ रुपये लोक निर्माण विभाग को दे दिए। मैं कह रहा हूं कि बजट बुक दिखा देंगे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जिनके ऊपर आज गाड़ी चलना दूभर हो गया है। ऐसी सड़कें हैं जहां निजी ऑपरेटर्ज ने बसें चलाना बंद कर दी हैं, कइयों ने बेच दीं और कहा कि हमसे हर रोज वर्कशॉप नहीं जाया जाता। आप कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा उन्नति या विकास कर लिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्लोड़ से झर्मानी-बहाड़-करसाई-अमरोह-स्रेड़ी सड़क और

एम.एस. द्वारा जारी

16/03/2017/1655/MS/AG/1

श्री विजय अग्निहोत्री जारी----

भट्ठा से सलौणी सड़क जो दियोट्सिद्ध को जाती है उस सड़क का हाल देख लो। गलोड़ से गाहलियां, बड़ौस-री-दांदडू के लिए जो सड़क है उसका हाल देख लो। आप गलोड़ से फाहल-प्लासी-टिप्पर वाली सड़क का हाल देख लो। कांगू से मालग-बैहरड़-सुकड़ियाह-धनेटा वाली सड़क का हाल देख लो। जहां बस बन्द हुई वह यह सड़क है। आप नदौन से गोना-वसारल-धनेटा होते हुए जो बड़सर के लिए सड़क जाती है उसका हाल खस्ता है। आज रंगस से कांगू-धनेटा होते हुए जो बंगाणा के लिए सड़क जाती है उसकी हालत खस्ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सड़कें हैं। आज वदारन-सराये-वाया क्वांट होते हुए पनसाई

से राम नगर-मंझैली और भूम्पल के लिए जो सड़क है उसको देख लो। ये ऐसी सड़कें हैं जिनका आज बहुत बुरा हाल है। फिर यहां बोलते हैं कि गडकरी जी ने नेशनल हाइवे डिक्लेयर किए और पैसा नहीं आया। आपने उसके ऊपर कुछ नहीं करना है। उनकी डी0पी0आर्ज0 बनाने के लिए आपकी इच्छा-शक्ति नहीं है। आप चाहते ही नहीं हैं कि विकास के काम का क्रेडिट किसी और को मिल जाए। इनका क्रेडिट आप ही ले लेना लेकिन उनकी डी0पी0आर0 तैयार कीजिए। उसके लिए अगर उन्होंने सैद्धांतिक रूप से पैसा भी माना है तो आप उसका टैण्डर करवाइए, आप काम करवाइए, आपको पैसा मिलेगा। लेकिन आप नहीं करना चाहते। आज हम कहीं पर भी विजनरी रूप से अपनी सड़कों की हालत देखें तो कहीं भी हमें विजन नहीं दिखाई देता कि हम अगले आने वाले 20 या 30 साल के लिए सड़क बना रहे हैं। आपके एज़ इतने खराब हैं कि आज अगर एक टू व्हीलर वाले को पास देना पड़ता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आज आपकी गाड़ियों की हालत खस्ता है। कुछ समय पहले हमारी समिति कुछ राज्यों के अध्ययन प्रवास पर गई थी। हम गोवा गए थे तो मैंने वहां कुछ दोस्तों से मिलने के लिए इनोवा गाड़ी हायर की। मैं वहां से सवेरे-सवेरे निकला। मैंने उस गाड़ी वाले को पूछा कि आपके ये टायर कितने चलते हैं। उसने कहा कि 80 हजार किलोमीटर से ज्यादा चलते हैं। हम कितना चला रहे हैं? हमारे तो 20000 या 22000 पर टायर बदलने पड़ रहे हैं। हम क्या विकास कर रहे हैं? हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। हमारे यहां तो ऐसा है कि सड़कों के लिए रिपेयर एण्ड मैंटीनैंस का पैसा आया तो बोले कि अभी तो बजट

16/03/2017/1655/MS/AG/2

पास हुआ है। मई या जून में पैसा आया और जुलाई में पैसा लगाने की कोशिश की और अगस्त में बारिश में सब बह गया। वन-टू-का-फोर और अपने-अपने घर को सारे चले गए। पैसा कहां लग रहा है? मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक भी सड़क ऐसी हालत में नहीं है जिसके ऊपर ये बोल सकें कि पिछले दो वर्षों में उनके ऊपर कभी भी बिचुमैन लगा हो या मैटलिंग हुई हो। यह भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है?

आज अगर हम सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को देखें तो शिमला की हालत भारद्वाज जी ने बता दी है कि कैसा पानी हमें पिलाया गया। हमारे वहां मीडियम इरीगेशन प्रोजैक्ट्स हैं। इस बार बजट बुक में उसका कुछ नहीं दिखा। उसका काम बड़ी धीमी गति से चला है। वहां एक कोला-मजियार-सेरा फेज वन- टू-थ्री एक बहुत बड़ी सिंचाई की स्कीम है। उसका वर्ष 2002 में काम शुरू हुआ था और उससे आज तक एक भी खेत को एक भी लीटर पानी नहीं पहुंचा है। हम क्या विकास की बात कर रहे हैं? आदरणीय धूमल जी की सरकार के समय में एक बड़सर से ऑग्यूमैंटेशन ऑफ वॉटर रिसोर्सिज फॉर नदौनता चुनाव क्षेत्र, जो उस समय नदौनता चुनाव क्षेत्र था, यह उसकी बात है। उसके लिए सलोणी में शिलान्यास किया गया। उसके लिए बजट का प्रावधान भी था लेकिन आज तक उसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। हम कहां पहुंचे हैं? मेरे वहां कई टैंक ऐसे हैं जो तीन-तीन साल से बने हुए हैं लेकिन उनमें पानी का टैस्ट नहीं किया जा रहा है और वे वैसे ही धूप से फटने लग गए हैं। वहां नदौन की जो सीवरेज स्कीम है उसके ऊपर 15 साल से काम चल रहा है। वह छोटा सा शहर है और उसकी सीवरेज स्कीम का काम नहीं हो पा रहा है। आज आप बोल रहे हैं कि मुख्य मंत्री जी ने चारों तरफ सर्वांगीण विकास करने की कोशिश की है। अभी डेढ़-दो साल पहले आदरणीय मुख्य मंत्री जी नदौन विधान सभा क्षेत्र में गए थे और उन्होंने मिनी सचिवालय का वहां शिलान्यास किया था। ये बताएं कि उसकी एक भी ईंट लगी है? इसके अलावा वहां पर टूरिस्ट इन्फोरमेशन सेंटर और पार्किंग के लिए एक शिलान्यास करके आए थे, उसकी क्या स्थिति है, क्या उसके बारे में भी बताएंगे?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, एक मिनट बैठ जाइए। सदन का समय बढ़ा लेते हैं। अभी 5.00 बजे का समय हो गया है और अभी काफी लोग बोलने वाले हैं। अगर सदन की सहमति हो,

जारी श्री एस0एस0 द्वारा----

16.03.2017/1700/SS-DC/1

माननीय अध्यक्ष क्रमागतः

तो दो घंटे और इस सदन का समय बढ़ाया जाता है? अब इस माननीय सदन का समय 7:00 बजे तक बढ़ाया जाता है।

श्री विजय अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने टूरिस्ट इंफोरमेशन सैंटर की बात कही। --(व्यवधान)-- हम कहीं अमृत और कहीं स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने कभी सोचा है कि हमारे जो प्रदेश के छोटे-छोटे शहर हैं उनके विकास की कोई योजना बननी चाहिए। हमारे यहां पार्किंग होनी चाहिए। टैक्सी स्टैंड होना चाहिए। हमारे वहां टूरिस्ट आएं, उसके लिए कोई विकास होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो आदरणीय धूमल जी ने धनेटा-बंगाणा सुरंग का शिलान्यास किया था और उसमें 10 करोड़ रुपये का प्रावधान भी था। वह पैसा पता नहीं कहां गया? उसके ऊपर ज़रा भी काम नहीं हुआ। अब आदरणीय नितिन गडकरी जी ने वहां नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया है, उसको उसमें इंक्लूड किया तो उन रोडस की डी0पी0आर0 नहीं बन पा रही है। इस करके विज़नरी सोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 400 हैड्स हैं उनमें थोड़ा-थोड़ा पैसा डाल दो और उसे निकाल लो। नमक, मिर्च, आलू, प्याज सारा घर ले आओ, रोटी बनाओ, खाओ और सो जाओ, वह बात नहीं है। क्या हमने कोई मास्टर प्लान हर क्षेत्र की तैयार की है? जैसे प्लानिंग की मीटिंग होती है और विधायकों को प्राथमिकता के लिए बुलाया जाता है, एक प्रॅफोर्मा छापकर दे दिया जाता है कि आप इसमें भरो क्या-क्या चाहिए। मान लो, हमें उसमें से कोई चीज़ नहीं चाहिए और कोई अन्य चीज़ चाहिए तो वह कहां से लेंगे? आप हर सैगमैंट की अलग से योजना बनाएं। वहां के विधायक और जन-प्रतिनिधियों को पूछ कर एक बृहद योजना बनाई जाए कि उस क्षेत्र की क्या आवश्यकता है। किसी को सड़क की ज़रूरत होगी, किसी को सिंचाई की आवश्यकता होगी और किसी को वाटर सप्लाई स्कीमों की आवश्यकता होगी, किसी को लिंक रोडस की आवश्यकता होगी। लेकिन हम चाहे वह लाहौल-स्पिति है या ऊना है एक ही पैरामीटर के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैं बार-बार

16.03.2017/1700/SS-DC/2

कहता हूं कि दो खड्डें हैं जहां पर अवैज्ञानिक तरीके से अवैध खनन हो रहा है और वे सूखती जा रही हैं। आज हमें अपनी स्कीमों के ऑगमैंटेशन के लिए बार-बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि वह रिचार्ज यूनिट है। वहां गड्ढे पड़ रहे हैं क्योंकि वहां से सप्पड़/पत्थर निकल दिए हैं। वहां पानी टिकता नहीं है। आज वे खड्डे सूखनी शुरू हो गई हैं। गर्मियों में उनमें पानी बिल्कुल नहीं बहता है जोकि पहले 12 महीने बहता था। जब मैं आज से 20-25 साल पहले स्कूल में पढ़ता था तो उन खड्डों में 12 महीने 24 घंटे चार-चार घराट चलते थे।

आज वहां एक भी घराट नहीं चलता है। वहां पानी ही नहीं है। पानी कहां जा रहा है? क्या हमने उनको दोबारा से रिचार्ज करने या संरक्षित करने की कोई योजना बनाई है? मैंने उसकी चैनेलाइजेशन और चैक डैम के लिए प्राथमिकता में डाला था। आपको बार-बार बोला भी। उसके लिए 25 लाख रुपये की डी0पी0आर0 बनाने के लिए एक सर्वे मंजूर हुआ। डेढ़-दो साल हो गए हैं लेकिन आज तक एक इंच भी काम आगे नहीं बढ़ा और न ही आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट को इस संबंध में पूना वाली संस्था के साथ बातचीत करने का टाइम लगा। ये बजट अनुमान पढ़कर या सारी बातें बोल कर कि हमने इतनी चीज़ें क्रियेट कर दीं, हमने इम्प्लॉयमैंट जनरेट कर दी तो उससे इम्प्लॉयमैंट जनरेट नहीं हुई। आपने अंतिम वर्ष में आकर युवाओं के साथ छल करने की कोशिश की है।

जारी श्रीमती के0एस

16.03.2017/1705/केएस/डीसी/1

श्री विजय अग्निहोत्री जारी---

आपने सोचा है कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को लोलीपॉप देने से बल्कि दिखाने से हम उसको मना लेंगें, ऐसा नहीं होता है। उसको भी बजट बुक ही देनी पड़ेगी बाकी कुछ नहीं मिलेगा। हमने पिछले चार साल इस चीज़ में गुज़ार दिए। बहाने करते रहे हम बोलते थे कि

ये बड़े अनभिज्ञ लोगों द्वारा किया गया वायदा है यह पता नहीं किसने बना दिया । आपने लास्ट में आ कर फिर बोला कि हमने बेरोज़गारी भत्ता देने की घोषणा कर दी और घोषणा कर दी तो कितने लोगों को देंगें? कितने बेरोज़गार हैं, उनकी गाइडलाइन कब बनेगी? आपने जब कोई व्यक्ति अन्तिम सांसें ले रहा होता है तो उसको गीता सुनाने की कोशिश की है जिसको सुनाई भी नहीं देता है लेकिन आप यह भूल गए कि गीता सुनना और सुनाना पराक्रमी लोगों का काम है। गीता का उपदेश युद्ध भूमि में हुआ था और देने वाला श्री कृष्ण था और सुनने वाला अर्जुन था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी सांसें बन्द हो रही थी जो आजकल प्रचलन है, वह आपने यहां करने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, युवाओं के साथ छल किया। किसानों के प्रति कोई गम्भीरता नहीं दिखाई । आपने पर्यटन के बारे में इस प्रदेश में क्या किया? पिछले चार वर्षों में आपकी पर्यटन के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आपके प्रशासन ने मनाली में प्रैस कॉफ्रेंस करके कहा कि टूरिस्ट यहां न आएं हम उनको नहीं सम्भाल सकते। आपसे एक राजधानी सम्भलती नहीं और कहते हैं कि हमने धर्मशाला का मान-सम्मान करने के लिए वहां राजधानी दे दी। तो क्या आप मण्डी, हमीरपुर, ऊना या अन्य जिलों का मान-सम्मान नहीं करते? यह मान सम्मान नहीं है। आप बताओ कि उसकी क्या आवश्यकता थी? यह भी बताओ कि आप वहां क्या-क्या करेंगें? आपने राजधानी दे दी, फट्टा बदल दिया। जैसे स्कूल अपग्रेड कर दिए लेकिन एक भी कुर्सी, डैस्क या एक भी कमरा नहीं दिया। बोर्ड लगा दिया। उससे क्या होता है? बोर्ड लगाने से क्या संस्थान चल पड़ता है? आपके पास जाओ और पी.एच.सी. मांगों आप सी.एच.सी. का फट्टा लगा दो चाहे सिविल हॉस्पिटल का फट्टा लगा दो, चाहे मैडिकल कॉलेज का फट्टा लगा दो इससे कुछ होने वाला नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में पता नहीं शायद

16.03.2017/1705/केएस/डीसी/1

बाली जी ने लिखवाया है कि हम एक हजार नये रूट बेरोज़गारों को देंगें। वह एक हजार रूट आपने क्या आइडैंटिफाइ किए हैं या उनको महकमा आइडैंटिफाइ करेगा या जो

व्यक्ति रूट लेगा, वह आइडैंटिफाइ करेगा? और वह काम से आप आइडैंटिफाइ करेंगें कि जो एच.आर.टी.सी. की बसें सफल नहीं हो पा रही है, वहां वह चलाएंगें? आप उनको रोज़गार देने की बजाय उलटा कर्जे में डालने की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर बनाए जाएंगें। वह ट्रांसपोर्ट नगर न पहले बने न अब। क्या हुआ उनके बारे में? मुख्य मंत्री जी बताएंगें जिस ट्रांसपोर्ट नगर में मल्टीपल फैसिलिटी होती है, वहां सारी गाड़िया भी खड़ी होती हैं, पैट्रोल पम्प वहां होता है, सब्जी मण्डी होती है, बाकी चीजें होती है उसका क्षेत्र को लाभ होता है। आज हम यहां से जाएं तो सड़क के किनारे हर जगह गाड़ियां खड़ी मिलती हैं। ट्रक खड़े मिलते हैं आप उनकी व्यवस्था करने में नाकाम रहे हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, अब वाइंड अप करने की कोशिश करें।

श्री विजय अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, सरकार वाइंड अप हो रही है। चलो, मैं तो कर ही देता हूं। अध्यक्ष जी, बहुत सी बातें हैं लेकिन बहुत ज्यादा बातें करके मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेगा। हम पिछले चार सालों से बोल रहे हैं। अब तो हम यह सोच रहे हैं अजय महाजन जी ने जाते-जाते बोला कि हमने कृषक बकरी पालक योजना में 60 प्रतिशत सब्सिडी दी है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

16.3.2017/1710/av/as/1

श्री विजय अग्निहोत्री ------- **जारी**

80 कर लो, बड़े काम आयेगी। यहां पर जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान पेश किए गए या आज तक जो किए गए, यह बिल्कुल दिशाहीन है। इसमें कोई विजनरी सोच नहीं है। इसमें किसी चीज को अचीव करने का टारगेट फिक्स नहीं है। इसमें कोई चीज कैसे

लागू होगी उसका प्रावधान नहीं है। हम किसी चीज को कैसे और कहां-कहां करेंगे उसके लिए कोई योजना नहीं है। यह केवल आंकड़ों का मायाजाल है और इस आंकड़ों के मायाजाल को हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते और न ही इसका समर्थन कर सकते हैं।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके पैरा 6 में एक चीज लिखी है कि नोटबंदी के दुष्परिणाम आने वाले काफी दिनों तक रहेंगे। कुछ चंडीगढ़ में दुष्परिणाम निकले, कुछ उत्तर प्रदेश में और कुछ महाराष्ट्र में निकले। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भी निकलेंगे क्योंकि मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों के अच्छे दिन लाने का वायदा नहीं किया था। जिनके अच्छे दिन आने थे वह आ गये हैं और आने वाले समय में इस प्रदेश में भी अच्छे दिन आयेंगे लेकिन अफसोस कि आपको उसमें भी घाटा ही होगा। इस करके मैं बहुत लम्बी बात न करते हुए इस बजट का विरोध करता हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

16.3.2017/1710/av/as/2

अध्यक्ष : धूमल जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं।

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी में पक्ष-विपक्ष अपना-अपना मत रखता है। लेकिन एक सिद्धान्त संसद और हर विधान सभा में चलता है कि जो माननीय सदस्य भाषण करता है उसके एकदम बाद जो बोलेगा उसको वह सुनता है। यहां हिट एण्ड रन वाली बात हो गई है। माननीय सदस्य अपनी कुछ भी बात कहते हैं और सदन से बाहर भाग जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बात को सुनिश्चित करें कि जो सदस्य बोले वह अपने बाद कम-से-कम एक वक्ता की बात को सुने। दूसरा, मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि यहां पर श्री अजय महाजन जी ने बड़ी शेरो-शायरी की है। काश, वे यहां पर बैठे होते तथा उन्होंने अपने पिता जी से भी डिसकशन की होती कि उनकी क्या हालत रही है। जब वे यहां पर थे तो उस दौर को तो आपने भी देखा है और आप सब जानते हैं। एन0एच0 की जो डी0पी0आर0 नहीं बन रही है उसके लिए एक दलील

दी जा रही है कि 22 अगस्त की नोटिफिकेशन में चेजिज आ गई, गाइड लाइन्स चेंज हो गई इस करके हमें रीटैंडर करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, इनके बजट डाक्युमैंट में ही लिखा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के 61 नेशनल हाईवेज, 3 फोर-लेन्स, ओवर ब्रिजिज की नोटिफिकेशन भारत सरकार ने 22 सितम्बर, 2016 को की है और गाइड लाइन्स 22 अगस्त, 2016 की है। जो चीज 2016 के 22 अगस्त को हुई उसके ठीक एक महीने के बाद नेशनल हाईवेज की नोटिफिकेशन होती है तो आफटरवर्ड्स उस नोटिफिकेशन को कैसे गिन रहै हैं। वह गाइड लाइन्स तो एक महीना पहले आ गई थी। अपनी असफलता को छिपाने के लिए यह आरगुमैंट माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण में भी दिया गया है और यही आरगुमैंट अजय महाजन जी ने भी दिया कि 22 अगस्त को गाइड लाइन्स आ गई। अगर 22 अगस्त को आई है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह एक महीना पहले आ गई। एक महीने के बाद नेशनल हाईवेज नोटिफाई हुए।

16.3.2017/1710/av/as/3

अगर माननीय सदस्य यहां पर हाजिर हों तो उनके सामने कंट्राडिक्ट किया जाए। वह पहली बार के सदस्य हैं और जब भी बोलते हैं पढ़कर बोलते हैं। पहली स्पीच तो कागज से पढ़ना अलाऊ होती है लेकिन पूरी स्पीच घर से लिखकर लाओ, यहां पर पढ़ दो और फिर वाहवाही करो। फिर सुनते भी नहीं, मैंने उनको पुकारा भी था कि अब विजय अग्निहोत्री जी बोल रहे हैं आप सुनकर जाइए। हम किसी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं बोलेंगे। लेकिन दस्तूर को निभाना सिखो, सदन की गरिमा तभी बनती है। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

श्री वर्मा द्वारा जारी

16/03/2017/1715/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, 10 मार्च, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश बजट अनुमान 2017-18 के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस कद़र साढ़े चार घण्टे इस बजट स्पीच को पढ़ा, इसकी मैं दाद देता हूं। मैं 20वें बजट की माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने अपने जीवन का 20वां बजट पेश किया। जिसका हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने बड़े बेतुके तरीके से विरोध भी किया। मैं कहना चाहता हूं कि एक बहुत ही संतुलित और सभी वर्गों का ध्यान रखने वाला यह बजट है। जिसके कुछ अंश जो गरीब लोगों से जुड़े हैं, उनका वर्णन मैं यहां करना चाहूंगा। जैसे इस बजट में जो हमारे दिहाड़ीदार थे, उनकी दिहाड़ी 150 रूपये से बढ़ाकर 210 रूपये की गई, जो एक बड़ा कदम है। जो 80 वर्ष से अधिक वृद्ध थे, उनको बिना शर्त/बिना आय प्रमाण-पत्र और 70 परसेंट विकलांगों को बिना आय प्रमाण-पत्र के उनकी पेंशन को बढ़ाकर 1200 रूपये किया और वद्धावस्था, विकलांगता, विधवा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 450 से 650 रूपये किया गया। इसी तरह से 'मुख्य मंत्री कन्यादान योजना' के अन्तर्गत जिन गरीब कन्याओं को विवाह हेतु सहायता राशि दी जाती थी, उसको भी बढ़ा करके 25000 से 40000 रूपये किया गया। जिन बंदरों की चर्चा हर बजट सैशन में बार-बार होती है, हम लोग अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में जाते हैं, लोग इस समस्या को हमारे (पक्ष/विपक्ष) सामने रखते हैं, लेकिन आज तक कोई कांक्रीट डिसिजन नहीं दे पाये। इन्होंने जो कांक्रीट डिसिजन दिया है कि खेतों के चारों ओर कांटेदार तारें न लगाने के ब़जाय करंट वाली तारें लगाने जिसमें पहले सबसिडी कम थी, जिस वजह से लोगों अप्लाई भी नहीं किया। मैं मानता हूं कि इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि इसका प्रचार-प्रसार प्रदेश में नहीं हुआ। प्रचार-प्रसार की इसमें कमी ज़रूर रही है। मैं चाहता हूं कि इसका प्रचार-प्रसार पंचायत लैवल पर हों, ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा सकें। इसके लिए सबसिडी 80 परसेंट करके, बन्दरों की समस्या जिससे हम सभी लोग किसान/बागवान परेशान हैं, उसका समाधान करने की माननीय राजा साहिब ने कोशिश की है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा खरीदी जाने वाली जो ज़मीन है, उसकी जो सेल/लीज़ डीड है, उसकी डयूटी को 50 परसेंट माफ किया है। ये भी एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि जब उद्योग लगेंगे, तभी हमारे यहां आय के साधन जुटेंगें, हमारे लोगों की इंनकम बढ़ेगी और वे समृद्ध होंगे। सामान्य बसों में महिलाओं को किराये में जो 35

16/03/2017/1715/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

परसेंट की छूट इस बजट में दी गई। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम हैं। प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में जो नये संस्थान खुले, चाहे एजुकेशन या अन्य क्षेत्र हो। एजुकेशन की भर्त्सना यहां काफी दिनों से हो रही है कि इतने कॉलेज खुले।

श्रीमती एन0एस0 ..... द्वारा जारी।

16/03/2017/1720/ एन0एस0/ए0एस0 /1

श्री राम कुमार ----जारी

मैं विपक्ष से कहना चाहूंगा कि जब पहले यह कॉलेज नहीं खुले थे तबसे आकलन करें कि कॉलेज खुलने से पहले हिमाचल प्रदेश के कितने बच्चों को कॉलेज की ऐजुकेशन प्राप्त हो रही थी और नये कॉलेज खुलने के बाद कितने बच्चों को हायर ऐजुकेशन में एडमिशन मिली है। मैं समझता हूं कि यह आंकड़ा लगभग डेढ़ गुणा होगा। यह इस सरकार का एक बड़ा कदम है। गांव के बच्चों को जहां पर बस की सुविधा नहीं थी, लड़कियों को 50-60 किलोमीटर दूर कॉलेज में नहीं जा सकती थीं, उन क्षेत्रों में कालेज खुलने से उनके लिए शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने जरूरत के हिसाब से नये कॉलेजिज की घोषणा की और उनको शुरू किया। इन्होंने इन कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए राशि भी मुहैया करवाई है। मेरे क्षेत्र में बरोटीवाला कॉलेज खुला और उसके शिलान्यास के समय इन्होंने पांच करोड़ रूपये की राशि का चैक पी0डब्लयू0डी0 विभाग को उसी समय दिया। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज लगभग 300 स्टूडैंटस डिग्री कॉलेज बरोटीवाला में ऐजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त नालागढ़

कॉलेज की यह स्थिति थी कि वहां पर लगभग 1500 स्टूडैंट्स थे और वहां पर तीन-तीन सैशन बच्चों के लगते थे तथा बच्चों को कॉमर्स में एडमिशन नहीं मिलती थी। बच्चों को कालका, चण्डीगढ़, अम्बाला या अन्य राज्यों में एडमिशन के लिए धक्के खाने पड़ते थे। उनको वहां पर भी एडमिशन नहीं मिलती थी। थक हार कर वे स्टूडैंट्स ऐजुकेशन प्राप्त करने से वंचित रह जाते थे। इसका सारा श्रेय मुख्य मंत्री महोदय को जाता है कि इन्होंने ऐसा कदम उठाया जिससे उन बच्चों को हायर ऐजुकेशन प्राप्त करने का अवसर मिला। अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्कूलों की बात करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 25 स्कूल अपग्रेड किए हैं और नये खुले हैं। वर्ष 2007 से 2012 तक का जो समय था, उसमें केवल सुआ क्षेत्र में एक प्राईमरी स्कूल खुला था और इस स्कूल में एक भी पद सृजित नहीं हुआ था।

16/03/2017/1720/ एन0एस0/ए0एस0 /2

इसकी वजह से इसे डेप्यूटेशन पर चलाया गया था। मैंने उस क्षेत्र का भ्रमण किया और वहां की पंचायत का दौरा किया तो वहां के लोगों ने बात उठाई कि एक स्कूल माननीय पूर्व विधायिका जी ने खोला था लेकिन इसमें एक भी पद का सृजन नहीं हुआ है। तब मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया और तब वहां पर पदों का भी सृजन हुआ। मेरे क्षेत्र के सभी स्कूलों में टीचर्ज़ भी मौजूद हैं। जिन स्कूलों में कामर्स और साईंस नहीं थी। वहां पर भी इन्होंने ये विषय दिए हैं। बद्दी से साई 20 किलोमीटर की दूरी पर है वहां के बच्चों को कामर्स या साईंस पढ़ने के लिए बद्दी जाना पड़ता था। साईंस और कॉमर्स की फैकल्टी माननीय मुख्य मंत्री जी ने दी है जिससे वहां के बच्चों को लाभ हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अब तहसीलों की बात करना चाहूंगा। 16 नये उपमंडल, 16 तहसीलें और 31 उप-तहसीलें इस सरकार ने अपने समय में खोली हैं। इनकी बहुत मांग थी। मेरे क्षेत्र के लोग तहसील का कार्य करवाने कसौली जाते हैं, उनका थाने का कार्य भी कसौली में होता है क्योंकि यह क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसके लिए उन्हें एक दिन वहां पर ठहरने पड़ता था, 500 रूपये का कमरा लेना

पड़ता था लेकिन बद्दी तहसील खुलने से पट्टा तक का क्षेत्र इसमें आ गया है। इससे वहां के लोगों को लाभ हुआ है। यह भी एक विकास का कार्य है। लोगों को रोजमर्रा के कार्यों जैसे प्रमाण पत्र बनवाना, अपनी रजिस्ट्री करवानी है, इंतकाल करवाना है तो ये सब कार्य तहसील से होते हैं। यह तहसील बनने से आम लोगों को लाभ हुआ है। सरकार ने राजनीतिक तौर पर ये संस्थान नहीं खोले हैं। विपक्ष को इसकी सराहना करनी चाहिए।

इसमें 21 नये सिविल अस्पताल, 34 सी0एच0सीज0 और 29 उप-स्वास्थ्य केंद्र इस सरकार के कार्यकाल में खुले हैं। मैं अगर अपने क्षेत्र की बात करूं तो दून क्षेत्र में इससे पहले कोई सी0एच0सीज0 नहीं थे। अब दो सी0एच0सीज0- एक बद्दी में और दूसरा चण्डी में खुला है। मेरा क्षेत्र दो भागों में बंटा हुआ है- एक पहाड़ी और दूसरा मैदानी क्षेत्र। इससे लोगों को लाभ हुआ है। एक पी0एच0सी0 हरिपुर है वहां पर लगभग

श्री आर0के0एस0 ----जारी

16/03/2017/1725/RKS/AS/1

श्री राम कुमार... जारी

10,000 हजार लोग मेले में हर सप्ताह माथा टेकने आते हैं। वहां पर कोई भी डॉक्टर नहीं था। जब कभी आपातकालीन स्थिति आ जाती थी तो लोगों को 10 किलामीटर दूर बद्दी-बरोटीवाला जाना पड़ता था। यह जरूर है कि डॉक्टर्ज की कमी है परन्तु वहां पर पी.एच.सीज. और सी.एच.सीज. में डॉक्टर्ज की तैनाती भी हो गई है। भर्ती प्रक्रिया चली हुई है। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि यदि आप डाक्टर्ज लाते हैं तो हम उनको तुरंत भर्ती करेंगे। दो-चार दिन पहले कुछ डाक्टर्ज की भर्तियां भी हुई हैं। जहां-जहां डाक्टर्ज नहीं थे उन क्षेत्रों में कुछ डाक्टर्ज की अप्वाईंटमैंट हुई है। इसी तरीके से 40 पशु चिकित्सालय, 2 पशु क्लीनिक, 47 पशु औषधालय और पांच पंचायत पशु औषधालय इस सरकार ने खोले हैं। यह डायरेक्ट हमारे जमींदारों/पशुपालकों से जुड़ी चीजें हैं। इससे

उनको लाभ होगा। मैंने भी अपने क्षेत्र के लिए 4 पशु अस्पतालों की मांग की है। शायद वे अभी पाइपलाइन में हैं। इन चीजों का आम-जन को लाभ हो रहा है। पशुपालकों को अपने बीमार पशुओं को दूर-दराज पशु औषधालय ले जाने में दिक्कत होती थी। इसलिए इन संस्थानों का खुलना जरूरी था। इसके लिए हम सभी लोगों को माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। प्रदेश के भिन्न-भिन्न हिस्सों में रोजगार मेलों का कार्यक्रम शुरू किया गया है। मैंने भी बद्दी, नालागढ़ में यह कार्यक्रम करवाए । अन्य जगहों में भी यह कार्यक्रम हुए। लगभग 27 हजार युवाओं को इन रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार मिला। यह एक सराहनीय कदम इस सरकार का रहा है। इससे पहले भी हमारे यहां उद्योग थे परन्तु ऐसे कार्यक्रम प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं हुए थे। यह एक नया कदम है जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिला है। दून क्षेत्र में कोई रोजगार कार्यालय नहीं था। अभी बद्दी में एक रोजगार कार्यालय खुला है। इससे पहले हमारे युवा साथियों को अपना नाम दर्ज करवाना के लिए कसौली या नालागढ़ जाना पड़ता था। जब बच्चों का नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज नहीं होता था तो उनका इंटरव्यू में नम्बर आना असम्भव था। आज प्रदेश सरकार जो भर्तियां कर रही है उनमें इन बेरोजगारों के रोजगार कार्यालय से इंटरव्यू कार्ड निकलते हैं और उन्हें भर्ती में

16/03/2017/1725/RKS/AS/2

शामिल होने का मौका मिलता है। यह भी सरकार का एक अच्छा कदम है। प्रदेश में वैलफेयर कार्यालय खोले गए हैं। यह आम-जन और गरीब-जन से जुड़ा हुआ काम है। हमारी विड्डो पैंशन, बुढापा पैंशन और अपंग पैंशन इन्हीं कार्यालयों से मिलती है। इन कार्यालयों के खुलने से लोगों की फटीक/दौड़ कम हुई है। क्योंकि इसके लिए उन्हें कई चक्कर लगाने पड़ते थे। यदि नजदीक में वेलफेयर कार्यालय होगा तो इससे आमजन को बहुत बड़ी सुविधा होगी। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। हर चुनाव क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने 50 करोड़ रुपये 'विधायक क्षेत्रीय विकास निधि' को बढ़ाकर 70 करोड़ रुपये किया है। हमें जो पैसा नाबार्ड

की स्कीमों से मिलता है उसे 80 करोड़ रुपये किया गया है। यह एक बड़ा कदम है। यहां पर बात आती है कि डी.पी.आर्ज. नहीं बन रही है। उसके लिए सभी की स्थिति यही है। जब विधायक कंसर्न डिपार्टमैंट से बात नहीं करेगा तो उसकी डी.पी.आर्ज बनने में दिक्कत तो है परन्तु इसके लिए विधायक को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं अपनी बात कहूं तो मेरे लगभग 67-68 करोड़ रुपये अवेल हो चुके हैं। इस बार 10 करोड़ रुपये बढ़ने से जो मेरी बाकी स्कीमें पाइपलाइन में थी, वे भी पूरी हो जाएगी। इसका लाभ सभी को हुआ है।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

16.03.2017/1730/SLS-DC-1

श्री राम कुमार ....जारी

यह कार्य केवल हिमाचल में ही हो रहा है। यहां पर विधायक निधि को 50 लाख से एक करोड़ रुपये किया गया था और अब एक करोड़ से 1.10 करोड़ रुपये किया गया है। हमारे पड़ोसी राज्यों में यह रीति नहीं है। वहां पर सत्तापक्ष के लोग ही विकास कार्यों का आबंटन लेते हैं और उन्हीं के विकास कार्यों को योजनाओं में शामिल किया जाता है। मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इसमें पक्ष-विपक्ष के सभी सदस्यों के लिए बराबर पैसे का आबंटन होता है और बराबर धनराशि दी जाती है। इससे विकास योजनाओं का लाभ सभी को बराबर मिलता है। इसके लिए विपक्ष को भी धन्यवाद करना चाहिए।

इससे पहले जो धूमल साहब की सरकार रही, उस समय चाहे विधायक क्षेत्रीय विकास निधि का पैसा हो या नाबार्ड से प्लानिंग का पैसा हो, यह कभी इतना नहीं बढ़ा है। जब पिछली बार माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पैसे की बढ़ोतरी की गई, उस समय हमने चलते-चलते सीढ़ियों पर बात की कि इसको 50 करोड़ से 70 करोड़ रुपये करना है। उन्होंने बाल्दी साहब को बुलाकर तुरंत आदेश दिए कि इस राशि को 70 करोड़ किया जाए ताकि हमारे विधायकों को इसका लाभ हो। इसके लिए पक्ष-विपक्ष दोनों को उनका

धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने सभी सदस्यों के लिए यह सराहनीय कदम उठाया है। मैं इसके लिए पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा।

प्रदेश में बागवानी को सुदृढ़ करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन बजट अनुमानों में 424 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अभी माननीय अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि इसका फौलोअप नहीं होता है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि फौलोअप तो हम लोगों को करना है। मुख्य मंत्री जी सारी चीजें फौलोअप नहीं करेंगे। बजट दे दिया है। संबंधित क्षेत्र को कितनी एलोकेशन हुई है, उसके राखे हम स्वयं हैं। ...(व्यवधान)... आपकी बात सही है पर उसमें हमारी भी जिम्मेबारी बनती है। जैसे डॉ0 वाई. एस. परमार किसान स्वरोज़गार योजना के अंतर्गत क्षेत्र को 2000 वर्गमीटर से बढ़ाकर 4000 वर्गमीटर किया गया है और 15 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के किसानों के लिए, जिनकी पॉलीहाऊस की सीट्स प्राकृतिक आपदा के कारण फट जाती थी, उनको कोई पैसा नहीं मिलता था। इसके लिए जो नई स्कीम माननीय मुख्य मंत्री जी ने दी - मुख्य मंत्री ग्रीनहाऊस रैनोवेशन स्कीम, इससे हमारे बहुत से किसानों को लाभ होगा।

16.03.2017/1730/SLS-DC-2

खासकर मैदानी क्षेत्रों में जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो वहां पर पॉलीहाऊस फट जाते हैं। उन्होंने जो फसल उसमें उगाई होती है, वह खराब हो जाती है। कृषि के लिए 484 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। यह भी बड़ा बजट है जिससे हमारे किसानों को लाभ होगा।

14वें वित्तायोग की यहां चर्चा हुई कि थ्री टीयर सिस्टम में जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वह तंग थे और यह सिस्टम एक तरह से फेल हो रहा था। 14वें वित्तायोग में पंचायत समिति और जिला परिषद् के बजट को कट लगा था। मैं देखता था कि हमारे जिला परिषद् और पंचायत समितियों के लोग अपने आपको ठगा हुआ महसूस करते थे। वह हमसे बार-बार बात करते थे कि हम अपने क्षेत्रों में कैसे जाएं और कैसे लोगों को जवाब दें। लोग हमसे काम मांगते हैं कि हमने आपको वोट दिया है, इसलिए कोई-न-कोई स्कीम आप भी अनाऊंस करके जाइए। वह लोग कई बार माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले और हमने भी उनसे बात की। माननीय पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा जी से भी हमने बात की। इन्होंने उस बात को तरजीह दी कि उनका भी क्षेत्र में मान-सम्मान होना चाहिए; उनको भी

हक है कि वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपना योगदान दे सकें। इसलिए इस हेतु जो इस बार 42 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, इस सराहनीय कदम के लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा।

यह पहली बार हुआ कि जो हमारे पंचायत रोड्ज थे, उनकी देखभाल नहीं होती थी। कई बार माननीय सदस्यों ने भी यह बात उठाई। पिछली बार भी मेरा प्रश्न था कि जो खंड विकास कार्यालय या पंचायतों द्वारा जो रोड्ज बनाए जाते हैं, उनकीरिपेयर का प्रावधान कहीं नहीं होता। इसके लिए हम लोगों को संबंधित उपायुक्त के पास जाकर गुहार लगानी पड़ती थी कि हमारे यह पंचायत रोड्ज बंद हो गए हैं, इनकी बहाली के लिए हमें रिपेयर हेतु पैसे दें।

जारी ..श्रीमती मन्जू द्वारा

16/03/2017/1735/RG/DC/1
श्री राम कुमार----जारी

लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि सीधे तौर पर ब्लॉक्स को पैसा देने के लिए बीस करोड़ रुपये का प्रावधान माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में किया है । जो एक सराहनीय कदम है इसके लिए भी हमें माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। इससे सीधे तौर पर गांव के लोगों को लाभ होगा और गांवों की सड़कों की रिपेयर होगी।

अध्यक्ष महोदय, जो हमारे बी.पी.एल. परिवार थे जिनके आवास के लिए मुख्य मंत्री आवास योजना शुरू की गई है और इसमें तीस करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान प्रस्तावित है। यह भी एक बड़ा कदम इस बजट में लिया गया है। राजीव गांधी आवास योजना के तहत जो आवास बनते थे, पहले मैं अध्यक्ष था, तो केवल 27,000/-रुपये की राशि घर बनाने के लिए दी जाती थी। उसके पश्चात एक मीट दिल्ली में हुई, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी ने इसकी अध्यक्षता की और भारत सरकार के पंचायती राज मंत्री भी उसमें शामिल हुए। हमने इस मांग को वहां उठाया क्योंकि पूरे भारतवर्ष के जिला परिषदों के चेयरमैन वहां आए थे, तो उस समय इसको बढ़ाकर 45,000/- किया गया और उसके बाद इसको बढ़ाकर 75,000/-रुपये किया गया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश

की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कई बार मकान के रॉ-मैटीरियल को खच्चरों पर ट्रांसपोर्ट करके ले जाना पड़ता है और अब इसके लिए 1,30,000/-रुपये की राशि बढ़ाकर की गई है। यह गरीब लोगों के लिए एक सराहनीय कदम प्रदेश सरकार का रहा है और इसमें 115 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवादी हूं।

अध्यक्ष महोदय, बद्दी, बरोटीवाला जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको सीधे तौर पर हिमाचल से कनैक्ट करने के लिए पहले कोई अच्छा रोड नहीं था, हमें पिन्जौर-कालका से होकर आना पड़ता था। हमने इसके लिए कई बार मांग की। हमारे यहां जो बद्दी-बरोटीवाला में उद्योगपतियों की ऐसोसियेशन है उन्होंने भी इसके लिए मांग की, तो इसके लिए भी बजट में तीन करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान जो हमारा बरोटीवाला-मन्धाला-गुनाई-परवाणु रोड़ को चौड़ा करने के लिए बजट में किया गया है। जो एक सराहनीय कदम है और इससे हमारे पूरे बी.बी.एन. क्षेत्र को लाभ होगा। इससे 1800 उद्योगपतियों को शिमला आने के लिए लाभ होगा।

Speaker: Try to wind up, please.

16/03/2017/1735/RG/DC/2

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, बी.बी.एन.डी.ए. का गठन वर्ष 2002 में हुआ था। पहली बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए पिछली बार 36 करोड़ रुपये बजट में दिए और इस बार फिर 36 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान इसमें किया गया है। कुछ पैसा वहां की जो फीस टी.सी.पी. से अर्जित होती है उसको मिलाकर और पिछला जो पैसा बचा है और कुछ उद्योग विभाग से मिलाकर, मैं समझता हूं कि 60-70 करोड़ रुपये अतिरिक्त फायदा नालागड़ और दून क्षेत्र को इस सरकार ने दिया है। यह भी बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। इससे हमारे क्षेत्र का कायाकल्प हुआ है। बहुत अच्छी सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स और बहुत अच्छे कार्य जो शायद बीस सालों में नहीं होने थे वे इन दो-तीन सालों में माननीय मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां कई बार विधान सभा के आगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल हुई, उन्होंने मांग रखी । उनका जो मानदेय है वह 450/-रुपये से बढ़ाकर 1000/-रुपये

किया गया और सहायकों का 300/-रुपये से बढ़ाकर 600/-रुपये किया गया है। यह भी एक आमजन से जुड़ी बात थी और यह दायित्व केन्द्र का था। क्योंकि इसमें शायद कुछ शेयर केन्द्र से आता था।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में आय के साधनों के सृजन के लिए मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा। मैंने अपने बजट फॉर्म में भी इसको भरकर दिया है। पूरे विश्व में हमारा हिमाचल प्रदेश सबसे सुन्दर प्रदेश है, पर्यटन को विकसित करने की बहुत सारी संभावनाएं यहां हैं। विशेषकर हमारे बड़े शहरों जैसे शिमला और मनाली में अगर हम कैसीनो का चलन शुरू करें, तो अच्छा रहेगा। इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरी चर्चा हुई थी। इन्होंने कहा कि हमारे हिमाचल के ऊपर इसके दुष्प्रभाव होंगे। मेरा सुझाव रहेगा कि जैसे नेपाल आदि जो पड़ौसी देश हैं उनमें नेपालियों को कैसीनों में जाने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन अन्य देशों से आने वाले व्यक्तियों को उसमें जाने की अनुमति होती है। अतः मेरा सुझाव है कि नॉन-हिमाचली को उसमें अलॉऊ किया जाए, तो मैं समझता हूं कि कैसीनो से हिमाचल प्रदेश की आय में काफी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त हमारे यहां परवाणु से लेकर सोलन तक की जो नदी है वहां पर लोग आकर शराब पीकर चले जाते हैं। अगर उस क्षेत्र को हम लोग लीज भूमि के तौर पर लोगों को दे दें और वे उसके साथ-साथ हट्ज आदि बना लें।

एम.एस. द्वारा जारी

16/03/2017/1740/MS/AG/1

श्री राम कुमार जारी-----

उसके साथ-साथ जैसे गोवा वगैरह में हट्स बनाई गई हैं, हमें भी वैसे ही करना चाहिए क्योंकि उससे आय के बहुत ज्यादा साधन जुड़ेंगे। मैं समझता हूं कि हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसलिए हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कारगर कदम उठाए। जैसे रोपवेज हैं तो कालका या परवाणु से कसौली के लिए सीधा लगाया जा सकता है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री राम कुमारः अध्यक्ष जी, आप बार-बार मुझे समाप्त करने के लिए कह रहे हैं। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद।

16/03/2017/1740/MS/AG/2

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो उन्होंने बीच में कहा कि एम0पी0लैड की स्कीम तो धूमल साहब के समय थी ही नहीं। मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। मैं केवल इनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जब आप विधायक नहीं थे और आपके पिता जी विधायक थे तब वर्ष 1999 में हिमाचल प्रदेश में पहली बार एम0एल0ए0 लोकल एरिया डवलपमैंट स्कीम मैंने यहां पर लागू की थी।

श्री राम कुमारः मैंने कहा कि ये स्कीम पड़ोसी राज्यों में नहीं है। -(व्यवधान)- मैंने राशि को बढ़ाने के लिए कहा।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः आपने मेरा नाम लेकर कहा कि जब धूमल जी मुख्य मंत्री थे तब नहीं था। मैंने 20 लाख रुपये से शुरू की और 30 लाख रुपये तक तो हम ले गए थे। घर में जाकर आपके पिता जी तो बताते ही होंगे कि हमारी सरकार में कैसा व्यवहार होता था और उनकी में कैसा होता था।

अध्यक्षः अब चर्चा में श्री कृष्ण लाल ठाकुर जी भाग लेंगे।

16/03/2017/1740/MS/AG/3

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः अध्यक्ष जी, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने 10 मार्च को बजट प्रस्तुत किया है, उस पर चर्चा के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, जैसे बजट के बारे में शुरू में ही नेता प्रतिपक्ष आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने विस्तार से आंकड़े देकर बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से हिमाचल के लिए खुलकर मदद दी जा रही है उसके बावजूद भी जो प्रदेश सरकार का सारा काम है वह लोन लेकर किया जा रहा है। जो आर0बी0आई0 की गाइडलाइन्ज हैं उसके अनुसार

लोन की भी एक सीमा है। उसके मुताबिक अगर हम ऐसा करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोन भी हमें नहीं मिलेगा। यह बड़े दुःख की बात है। इसके अलावा अभी जैसे और बातें हुई। जैसे भारद्वाज जी ने बताया कि चाहे यशवन्त सिंह परमार जी हों या महात्मा गांधी जी हों, उनकी याद कांग्रेस वालों को सिर्फ वोट के लिए ही आती है वैसे उनको भूल जाते हैं। इसी तरह से हमारे डॉ0 भीमराव अम्बेदकर, सरदार पटेल जी थे और अन्य जितने भी हमारे नेता थे उनको सिर्फ कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए यूज किया है चाहे वह दलित वर्ग था या मुस्लिम वर्ग था। परन्तु मुझे लगता है कि धीरे-धीरे अब लोग पूरे देश और प्रदेश में सबकुछ समझ चुके हैं कि वोट बैंक की राजनीति क्या है। आने वाले समय में सही जो उम्मीदवार होगा उसी के पक्ष में लोग वोटिंग करेंगे। लोग सरकार के गवर्नेंस और लॉ-एण्ड-ऑर्डर तथा डवलपमैंट को देखकर ही वोट देंगे। बजट में जैसे सभी ने पढ़ा और बताया कि बजट में किसी भी वर्ग विशेष के लिए चाहे बागवान, युवा वर्ग, कर्मचारी, किसान या मजदूर हों, किसी का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि इस बजट में विजन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें चाहे मजदूरों की बात ले लें। हमारे भाई राम कुमार जी ने भी बताया कि मजदूरों की दिहाड़ी 150/-रुपये से 210/-रुपये कर दी है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब धूमल जी की सरकार थी तो एकदम 75/-रुपये से 100/-रुपये दिहाड़ी को कर दिया था और पांच साल में 150/-रुपये कर दिया था। जोकि सौ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी थी। उस ढंग से तो यह दिहाड़ी अभी बहुत कम बढ़ी है और लगभग एक तिहाई बढ़ी है जबकि मजदूरों को प्रैक्टिकली दिहाड़ी 300 या 350 मिलती है और वैसे भी अगर 150 का डबल कर दें तो 300 रुपये होनी चाहिए थी। इसलिए जो मजदूरों की वाहवाही वाली बात है यह केवल आंकड़ों की बात है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अभी

16/03/2017/1740/MS/AG/4

जैसे नाबार्ड में बताया कि लिमिट पर-कन्स्टीच्यूएंसी 80 करोड़ रुपये कर दी है तो 80 करोड़ रुपये तो धूमल जी के समय भी थी और

जारी श्री एस0एस0 द्वारा----

16.03.2017/1745/SS-AG/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर क्रमागतः

अब यह 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए था क्योंकि कॉस्ट एस्कालेशन है। जो कॉस्ट इंडैक्स पांच साल पहले था, वह उससे 70-80 परसैंट ज्यादा हो गया है। इसलिए अगर यह 80 करोड़ किया है तो बहुत कम है।

इसी तरह से विधायक क्षेत्रीय विकास निधि की बात है। धूमल जी ने डिटेल में बता ही दिया है कि वह उनके समय स्टार्ट हुई थी और बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई थी। उस 50 लाख रुपये की वैल्यू वर्तमान समय में एक करोड़ के बराबर हो गई है। इसलिए अच्छी बात है कि विधायक निधि 1 करोड़ 10 लाख रुपये कर दी है। मैं चाहता हूं कि यह कम-से-कम डेढ़ करोड़ होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि विधायक जो होता है वह जानता है कि क्षेत्र का विकास कहां होना है, कहां पर छोटे-छोटे कामों की ज़रूरत है। थोड़े पैसे से ज्यादा इम्पैक्ट कहां हम दे सकते हैं। इसके बारे में सबसे ज्यादा विधायक ही जानता है। इसलिए विधायक निधि डेढ़ करोड़ तक होनी चाहिए। तब तो हम कह सकेंगे कि बजट में कुछ अच्छा काम हुआ है। एक जनरल व्यू लें, जब सरकार बजट पेश करती है और उसके बाद उसकी इम्प्लीमैंटेशन होती है, बाद में क्या-क्या एचीवमैंटस होती हैं, मुझे लगता है कि उन एचीवमैंटस पर कभी फोकस नहीं होता। पूर्ववक्ताओं ने सही कहा कि एक साल कोई स्कीम डाल दी जाती है, उसकी कोई वैल्यूऐशन नहीं होती कि वह कम्प्लीट हुई, कितनी हुई या शुरू भी नहीं हुई तो अगले साल उस स्कीम को डिलीट करके दूसरी स्कीम शुरू कर दी जाती है। बजट बुक की बड़ी स्पीच बनाने के लिए सिर्फ आंकड़ों के चक्कर में रहते हैं। मुझे लगता है कि शायद पांच-दस साल पहले लोग गुमराह हो जाते होंगे परन्तु अब समय आ गया है कि लोग प्रैक्टीकल हो गए हैं। लोग रिजल्ट चाहते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है। तो इन चीज़ों से, बड़ी-बड़ी बुक बनाकर, बड़ा भाषण देकर कोई लाभ नहीं होने वाला है। अगर हम इसमें तीन चीज़ें लें। हम डिवैल्पमैंट की बात ले लें। डिवैल्पमैंट में सबसे पहले सरकार को प्रोजैक्ट बनाना होता है, प्रोजैक्ट बनाकर जब एप्रूव हो जाता है तो

उसकी एग्जिक्यूशन होती है। जब प्रोजैक्ट बनकर कम्प्लीट हो जाता है तो उसकी मैंटीनेंस होती है। अगर इन तीनों फ्रंटस पर मैं देखूं, चाहे डी0पी0आर0 बनाने की बात हो तो उसे

16.03.2017/1745/SS-AG/2

बनाने में बहुत सुस्ती है। अगर कोई डी0पी0आर0 एप्रूव हो जाती है और कोई एम0एल0ए0 ज्यादा एक्सियन को कहकर डी0पी0आर0 बना लेता है, हमने भी बनवाई है इसमें कोई शक नहीं है परन्तु जब उसकी एग्जिक्यूशन स्टार्ट होती है तो उसमें बिल्कुल ढील होती है। कहते हैं कि स्टाफ नहीं है, यह तो बड़ा मुश्किल है। हमने 62 ट्यूबवैल एम0एल0ए0 प्रायोरिटी में नाबार्ड के माध्यम से एप्रूव करवाए हैं। उसमें अभी 30 डील हो पाए हैं। बाकी के लिए कहते हैं कि स्टाफ नहीं है। मुझे लगता है कि हर जगह ऐसा ही हाल होगा।

अब अगर हम आई0पी0एच0 की बात लें तो उसमें मैंने एम0एल0ए0 प्रायोरिटी में तीन मीडियम इरिगेशन प्रोजैक्ट्स डाले थे। उसमें स्टेट गवर्नमैंट ने सिर्फ डी0पी0आर0 बनानी थी और डी0पी0आर0 बनाकर फंडिंग के लिए गवर्नमैंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सिज़ को स्पोंसर करना थी। एक प्रोजैक्ट था हमारा construction of big dams on Lohand-Mahadev-Kundlu-Chickni Khad और फिर बड़े डैम लगाकर वैली और हिल के एरिया को इरिगेट करना था। एक तो यह मीडियम इरिगेशन प्रोजैक्ट था। एक ऐसा ही प्रोजैक्ट गम्भर खड्ड पर दोनों साइड राइट और लैफ्ट बैंक पर डैम बनाकर दोनों साइडों की जमीन को इरिगेट करना था। वह भी मीडियम इरिगेशन प्रोजैक्ट था। तीसरा, एक चैनेलाइजेशन ऑफ बरसाती खड्ड था। नालागढ़ कांस्टीचुऐंसी में बरसाती खड्ड को चैनेलाइज करके और wherever feasible small dams बनाने था। वह प्रोजैक्ट भी गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को स्पोंसर करना था। अगर ये तीनों प्रोजैक्टस हमारे बनते हैं तो नालागढ़ कांस्टीचुऐंसी में चाहे हिल एरिया हो या प्लेन हो, उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला था परन्तु अभी तक सिर्फ चैनेलाइजेशन की जो मॉडल/फिजीबल स्टडी स्टार्ट की है। मुझे लगता है कि अभी उसका एस्टीमेट भी नहीं बना है जो मॉडल स्टडी के लिए टैंडर कॉल करना है। जो पूना में रिसर्च इंस्टिच्यूट है वहां के लिए अभी तक एस्टीमेंट नहीं बना पाए हैं। डी0पी0आरज़0 की यह पॉजिशन है। चाहे नेशनल हाईवेज़ की बात ले लो। पी0डब्ल्यू0डी0 की भी वही बात है। हमारे दो नेशनल हाईवेज़ हैं। उसकी भी डी0पी0आर0

का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। ये मेज़र प्रोजैक्टस हैं जिसकी फंडिंग गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने करनी है क्योंकि स्टेट गवर्नमैंट के पास पैसा नहीं है, यह मैं मानता हूं। इसलिए हमारी यही प्रायोरिटी होती है कि हम सैंटर से कितना फंडस ला सकें। परन्तु उसके लिए सही और टाइमली डी0पी0आर0 बनानी होती है लेकिन उसमें जिस ढंग से काम होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है।

16.03.2017/1745/SS-AG/3

अब आई0पी0एच0 मिनिस्टर चली गई हैं। इन्होंने कहा कि फिल्टर बैड के लिए 20 करोड़ रुपया दे दिया है। इतना हम और सी0सी0ए0 क्रियेट करेंगे और इतनी बस्तियों को पानी देंगे। मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं होने वाला है। इन्होंने फिल्टर बैड की बात की कि इस बार भी बहुत फिल्टर बैड बना दिये लेकिन वे फील्ड में कहीं भी नहीं हैं। इसके साथ-साथ जहां बात की है कि इस बार हमने और अच्छा काम कर दिया है कि जितने भी रूरल एरियाज़ में टैंकस हैं उनमें लॉकिंग सिस्टम कर दिया है। मेरा तो यह कहना है कि यह बात भी बिल्कुल वैसे हो जायेगी जैसे हमने स्टेट को ओ0डी0एफ0 डिक्लेयर किया है।

जारी श्रीमती के0एस

16.03.2017/1750/केएस/एएस/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर जारी----

सिर्फ कागजों में किया है। ऐसे ही लॉकिंग की बात होगी। रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में ऐसे 30- 40 परसेंट टैंक होंगे जिनमें स्लेब ही नहीं है तो लॉकिंग कहां से करेंगें? मुझे लगता है कि ये सारी बातें ऐसी है जैसे यह बजट बल्की है परन्तु इससे कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ इसमें यह बताया गया है कि स्कीमें शुरू की गई है। आई.पी.एच. आप सी.सी.ए. की बात कर रहे हैं । 2.67 लाख हैक्टेयर जो सी.सी.ए. विकसित हुआ है

उसकी भी युटिलाईजेशन 1.10 लाख है। 50 प्रतिशत से कम है तो मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि न तो इनके पास स्टाफ है, न जो हमारी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वह बिल्कुल कम है। किसानों को बताएं कैसे क्रॉप आरिएंटेशन होनी है। कौन-कौन सी फसलें बीजनी हैं तो वह भी मिसिंग है। हम एग्रिकल्चर डिपार्टमैंट को कलैबरेट करके दोनों डिपार्टमैंट इकट्ठा इसको करें तभी तो सी.सी.ए. की युटिलाईजेशन बढ़ेगी। वैसे भी विभाग का जो वर्तमान में स्ट्रक्चर है,मैं बार-बार उसके बारे में बात करता हूं और मेरी बात में काफी दम है। हम पोलिटिकल गेम के लिए इतने सारे इंस्टीट्यूशन्ज़ जो खोलते जा रहे हैं वे ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होंगे। आई.पी.एच. डिपार्टमैंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारी ह्यूमैन हैल्थ प्लस ह्यूमैन इकोनॉमी दोनों से जुड़ा हुआ विभाग है। जो हमारे पड़ौसी राज्य हैं, चाहे पंजाब या हरियाणा हैं या दूसरे छोटे स्टेट्स हैं, उत्तराखंड है, सभी जगह आई.पी.एच.के तीन विंग्ज़ में है । हम न तो इरिगेशन में किसानों के साथ न्याय कर पा रहे हैं, न रूरल पॉपुलेशन में जो वाटर सप्लाई है, उसमें कर पा रहे हैं और न ही अरबन एरियाज हैं, उनमें कर पा रहे हैं । अरबन एरियाज़ में, शिमला में अभी जो पीलिया हुआ वह इसी वजह से हुआ क्योंकि हम किसी के साथ भी जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी ट्राईफरकेशन होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि इसके लिए स्टेट की इकोनॉमी को भी देखना होता है परन्तु दूसरे जो अनफ्रूटफुल हम दफ्तर खोल रहे हैं, दूसरी चीजें हैं उसकी बजाय इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अरबन वाटर सप्लाई स्कीम अलग बन जाए , रूरल वाटर सप्लाई स्कीम अलग बन जाए और इरिगेशन का अलग डिपार्टमैंट बन जाए । इसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं

16.03.2017/1750/केएस/एएस/2

आएगा क्योंकि कुछ डिविजन्ज़ को इंटर्नलाइज़ करके उसको हम मैनेज़ कर सकते हैं परन्तु इसकी तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा पी.डब्ल्यू.डी. में भी ऐसा ही है। वहां चाहे क्वालिटी की बात है, क्वालिटी मिसिंग है। रीकार्पेटिंग करते हैं तो उसका हम बार-बार मुद्दा उठाते हैं कि उसकी थिकनैस बढ़ाओ । डिपार्टमैंट की टैक्निकल स्पैशेलाईज़ेशन कमेटी उसको करें क्योंकि 20 एम.एम. डालते हैं तो उसमें भी करैक्शन

लेयर हम नहीं डालते हैं तो कही 20 एम.एम. की जगह 10 एम.एम. रह जाती है कहीं युनिफोर्मिटी के लिए 20 एम.एम. की जगह 25 एम.एम. हो जाती है । तो न ठीक क्वालिटी आ पाती है न उसकी लाईफ होती है और जिसकी लाईफ पांच साल बताई जाती है वह चार-पांच महीने में ही टूट जाती है।

अध्यक्ष महोदय, जो रूरल रोड़ज़ हैं, पंचायती रोड़ हैं, उसके लिए ब्लॉक को फंडिंग दें । इस बार तो वह कर दिया है, अच्छी बात है। हम पिछले चार सालों से यह मुद्दा उठा रहे थे परन्तु उसमें भी मेरा यह कहना है कि एक तो 20 करोड़ रु0 कम है और ब्लॉकवाईज़ जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए वह ब्लॉक की जनसंख्या और उसकी पंचायतों को देखकर होनी चाहिए जैसे नालागढ़ ब्लॉक हिमाचल में जो चार-पांच सबसे बड़े ब्लॉक हैं, उनमें आता है तो ब्लॉक वाईज़ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पंचायतों और पॉपुलेशन के हिसाब से हों। पिछले चार-पांच सालों से पंचायतों में बहुत ज्यादा रोड़ बन गए हैं तो उनकी मेंटिनैंस भी हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। एन.एच. 21 जिसको आप 105 नं0 कहते हैं, नालागढ़ से स्वारघाट तक का जो रीच है उसके लिए हम केन्द्र सरकार से पूरा पैसा लाए हैं। गडकरी जी से हम बार-बार मिले। पैसा पूरा आ गया परन्तु बड़े दुख की बात है, हमने उसके बारे में यहां भी बड़े धरने प्रदर्शन किए, केसिज़ भी कोर्ट में चले हुए हैं परन्तु स्टैट गवर्नमैंट का जो पी.डब्ल्यू.डी. का नेशनल हाईवे विंग है, उससे ढंग से काम नहीं करवा पा रहा है जितना काम हुआ है उसकी क्वालिटी भी डाऊटफुल है। इसके अलावा जो काम है,जो टैंडर दूसरे ठेकेदार को दिया है उसकी भी स्पीड पहले तो ठीक थी लेकिन अब लगता है शायद उसको कोई इंस्ट्रक्शन्ज़ न चली गई हों, उसको गो स्लो वाला कोई सिग्नल नहीं चला गया हो । बड़े दुख की बात है अगर ऐसा हो रहा है । लोग देख रहे हैं कि फील्ड में कैसे काम हो रहे हैं। जब ऊपर से ढीला काम होता है तो फील्ड लैवल के ऑफिसर को भी डर नहीं होता। एक एनार्की टाईप का माहौल बना हुआ है उसके लिए मेरा सिर्फ यही कहना है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

16.3.2017/1755/av/as/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर------- जारी

कि हम बार-बार मुद्दा उठा रहे हैं और केंद्र सरकार ने पूरा पैसा दिया है। नेशनल हाईवे-21, नालागढ़-स्वारघाट का टैंडर अवार्डिड है उसके लिए सरकार स्पैशल इनस्ट्रक्शन्ज दे। यहां पर अधिकारी लोग तो बैठे हैं और यह स्पीच भी सम्बंधित विभागों को जाती है। मगर मुझे लगता है कि इसको कोई पढ़ता नहीं होगा क्योंकि सैन्स्टिविटी का लैवल बिल्कुल जीरो हो चुका है। (---व्यवधान---) बोलने को तो बोल दूं मगर आप लोगों ने करना कुछ नहीं, लेकिन आपको इसका जवाब जनता देगी। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और काम के प्रति सिनसीयर है। हम अपना काम करवा लेंगे, हमारे में इतना दम तो है। इसमें घबराने की जरुरत नहीं है। जितनी भी रोड्ज हैं चाहे रूरल की बात करें या नेशनल हाईवेज की बात करें उन सबका बुरा हाल है। कोई नई डी0पी0आर0 बनाने की बात हो या मैन्टेन करने की बात हो। अब अगर हम इन्स्टिच्यूशन्ज की बात करें जैसे यहां कई लोगों ने कहा। मेरे भाई, राम कुमार जी ने भी कहा कि हमारी सरकार ने इतने इन्स्टिच्यूशन्ज खोल दिए। इतने स्कूल अपग्रेड कर दिए। उसके लिए मेरा यह कहना है कि आपकी सरकार ने जो स्कूल खोले / अपग्रेड किए हैं या दूसरी इन्स्टिच्यूशन्ज खोली हैं वह नॉर्म्ज को फोलो करते थे जो मैरिट पर थे। उनको या तो खोला ही नहीं या फिर लेट खोला है। मैं आपको नालागढ़ का उदाहरण देता हूं। मैं पहले राम-बुशैहर की बात करूंगा। राम-बुशैहर में तीन चीजें बहुत जरूरी थी। उनकी पिछली सरकार के समय में अनाऊंसमैंट भी हो चुकी थी और नोटिफिकेशन भी होने वाली थी। तीन नहीं, चार है। उसमें एक आर0टी0ओ0 ऑफिस भी था। आर0टी0ओ0 आफिस की नोटिफिकेशन भी हो गई थी। बाकी राम-बुशैहर में तीन चीजें हैं उसमें एक तो 108 नम्बर ऐम्बुलैंस है जो कि एक छोटी सी बात थी और पिछली सरकार के समय में हो चुकी है। दूसरा कार्य आपका पी0एच0सी0 को सी0एच0सी0 बनाना था। यह सी0एच0सी0 भनाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह तीन निर्वाचन क्षेत्रों को जोड़ती है। तीसरी बात डिग्री कालेज की थी। ये तीनों मुद्दे मैं पहले साल से लेकर चाहे वह माननीय मुख्य मंत्री के साथ प्लानिंग की

16.3.2017/1755/av/as/2

मीटिंग हो, एक नेशनल हाईवे और बाकी यह तीनों चीजें जो मैंने अभी बताई। मैंने यह बात यहां प्रश्न के माध्यम से तथा दूसरे हर प्लेटफार्म के माध्यम से उठाई है। यहां स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। सी0एच0सी0 की लगभग 6-8 महीने पहले नोटिफिकेशन हुई है। उसकी अनाऊंसमैंट तो एक साल पहले हुई थी मगर नोटिफिकेशन लगभग 6 महीने पहले की गई थी और वहां पर अभी तक एक भी डॉक्टर नहीं आया है। (---व्यवधान---) सी0एच0सी0 बनने के बाद आपने(माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कहा गया।) वहां कोई डॉक्टर नहीं दिया। (---व्यवधान---) कब भेजेंगे? 6 महीने से ऊपर का समय हो गया है। अब तो हम ही करेंगे, आप जायेंगे और हम करेंगे। (---व्यवधान---) आप कुछ नहीं करेंगे। सी0एच0सी0 पहले ही ढाई साल लेट खुली है। उसकी नोटिफिकेशन को 6 महीने का समय हो गया है मगर आपने अभी तक कोई डॉक्टर नहीं दिया है। उस सी0एच0सी0 का श्रेय उधर यहां से भेजे हुए आपके सो-कॉल्ड नेता ले रहे हैं जबकि उसमें उनका कोई रोल नहीं है। यह हमने खुलवाई है और यह हमारा राइट था मगर यह राइट ढाई साल बाद मिला है जिसके लिए हमें खेद है। हम इसके लिए आपका धन्यवाद नहीं करेंगे। राम बुशैहर में 108 नम्बर ऐम्बुलेंस दो साल लेट चलाई गई और अब वह चली हुई है। मैं डिग्री कालेज के लिए चार साल से मुद्दा उठा रहा था। उसकी अनाऊंसमैंट और नोटिफिकेशन भी कर दी। मेरा आपसे आग्रह है कि जब यह कालेज फंक्शनल हो तो वहां पर सम्बंधित विषयों के लैक्चरर भेज दे। ऐसा न हो कि एक प्रिंसिपल आ गये और बच्चों को पढ़ाने वाला वहां कोई न हो। ये सारे कार्य हमारे ऐफट्र्स से हुए है और इसका श्रेय राम बुशैहर की 20 पंचायतों को जाता है जिन्होंने इनके लिए बार-बार स्ट्रगल किया है। मैंने भी उनका जन प्रतिनिधि होने के नाते हमेशा ये मुद्दे उठाये हैं। इसलिए इसका श्रेय वहां आपके सो-कॉल्ड नेता न ले और मैं अभी उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता। (---व्यवधान---) आपने शिमला से भेजे हैं और कई भेजे हैं। मैं यहां उनका नाम नहीं लेना चाहता और ऐसा कुछ नहीं है वे 5-6 महीने बाद पता नहीं कहां जायेंगे। आप यहां पर बेरोजगार युवाओं की बात करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो टैक्सी का परमिट लेते हैं। (---व्यवधान---) टैक्सी युवा ही चलाते हैं, बूढ़े लोग तो बहुत कम टैक्सी चलाते हैं या चलाते ही नहीं हैं।

श्री वर्मा द्वारा जारी

16/03/2017/1800/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर.... जारी।

4+1 का परमिट तो दे भी देते हैं लेकिन जो 6+1 का 2 साल से कोई परमिट नहीं दे रहे हैं। इसमें कोई टेक्निकल प्रोब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर कोई प्रोब्लम है भी तो युथ के इंट्रस्ट में 6+1 का परमिट भी जारी करें, क्योंकि इसके लिए बहुत लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। बजट में जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है यह एक बहुत बड़ा मज़ाक है। पिछले 4 सालों में यह भत्ता नहीं दिया गया और देना अब भी नहीं है, क्योंकि गाइडलाइन्ज़ आने में 2-3 महीने लग जाएंगे। इसके बाद इलेक्शन आ जाएंगे। इसलिए ये लॉस्ट साल में इसको कर रहे हैं। प्रदेश के युवा इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि ये आपने क्यों अलाऊंस किया है? ये आपने इलेक्टशन में वोट गेन करने के लिए अलाऊंस किया है। अगर आपको युवाओं से अटैचमेंट होती तो आप 4 साल पहले इसको देना शुरू करते। आप इसको अब कर रहे हैं, जब आप जाने वाले हैं, इसका आपको कोई फा़यदा होने वाला नहीं है। इस तरह से आप बेरोज़गारी भत्ता देने में पूरी तरह से फ्लॉप हो गये हैं। किसानों के लिए "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना" की बात थी, लेकिन बड़े दुःख की बात है कि उसके लिए एग्रीकल्चर/आई0पी0एच0 डिपार्टमेंट होते हुए भी अभी तक उसकी डी0पी0आरज नहीं बनाई गई। इन्होंने जो कंसल्टेंट हायर किया था उसने ये डी0पी0आरज एक साल लेट बनाई और अब 2016-17 में भी इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक सही डी0पी0आर गर्वनमेंट इण्डिया को परपोज़ नहीं होगी, तब तक उससे फंडिंग नहीं होगी। ये आप सब जानते हैं। इसकी सही ढ़ग से डी0पी0आरज बन जाये ताकि 2017-18 के लिए हिमाचल प्रदेश को "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना" से पैसा मिले और किसानों को उसका फ़ायदा हो और पैसा तो पूरे-का-पूरा केन्द्र सरकार ने देना है। केन्द्र ने 90:10 में और भी बहुत सारी ग्रांट्स दी है। -(व्यवधान)- चली गई वह this is not as per norms आपको उसके नार्मज़ पता नहीं है। जहां तक लॉ एण्ड आर्डर की बात है, पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी ऑफिसर्ज़ हैं वे ये देखते हैं कि कहां पर क्या गलत काम करना है। प्रदेश के अंदर पुलिस का बुरा हाल है। बी0बी0एन0 में तो और भी बुरा हाल है। बी0बी0एन0 बहुत सेंस्टिव एरिया है, क्योंकि यहां पर बाहर के प्रवासी लोग भी रहते हैं। वहां पर बहुत बुरा

हाल है, चाहे चेंन स्नेचिंग हो या माइनर के साथ रेप की बात हो। दूसरे, माइनिंग माफिया बड़ा भारी है, स्लैक्टिव माइनिंग हो रही है।

16/03/2017/1800/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

कुछ गरीब लोगों के ट्रेक्टर्ज का बड़ा चालान होता है, जबकि जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनका धन्धा दिन और रात चलता रहता है। इससे आम लोगों में भारी रोष हैं। जहां तक इंडस्ट्री की बात है, भाई राम कुमार जी ने कहा कि बी0बी0एन0 में बड़ा विस्तार हो रहा है। बी0बी0एन0 में जो पैसा है, वह हमारा पैसा है। वह कोई ख़राद का पैसा नहीं है। ये पैसा गवर्नमेंट इंडिया का पैसा है और लोगों का पैसा है। इसलिए बी0बी0एन0 में जो हो रहा है, वह बहुत कम हो रहा है। जो हो रहा है वह भी प्लांड -वे से नहीं हो रहा है। नालागढ़ में एक पार्किंग बनाई है, लेकिन जब उदघाटन करने के लिए माननीय मंत्री जी गये तो माननीय जजिज़ (Judges) ने उसका उदघाटन करने से रोक दिया, क्योंकि यह टी0सी0पी0 नॉर्मज़ के मुताबिक नहीं बनी है और हमारा जो व्यू है, वह भी खराब हो रहा है। इतना पैसा खर्च करने के पश्चात् उद्घाटन तक नहीं कर पाये। ऐसे ही कुछ रेन शल्टर बने हैं। उसमें बी0बी0एन0 पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन उसके लॉग-लास्टिंग कोई रिजल्ट नहीं होंगे। जब डबल लेन बनाई जा रही है तो कल उसको तोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार प्रकार की डेवैल्पमेंट हमारे क्षेत्र में हो रही है। पैसा नालागढ़ को पहले से थोड़ा ज्यादा मिला है, परन्तु अगर पॉपुलेशन और पंचायतों के हिसाब से देखें तो नालागढ़ दून से लगभग डेढ़ गुणा है। मेरी तो हमेशा यही डिमाण्ड रही है कि हमारा बजट डेढ़ गुणा होना चाहिए

श्रीमती एन0एस0 ..... द्वारा जारी।

16/03/2017/1805/एन0एस0/डी0सी0/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर -----जारी

जबकि यह लगभग एट-पार पहुंचा है। बी0बी0एन0 में भेदभाव भी है और इसके साथ-साथ भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ गया है। भ्रष्टाचार पर चैक की बहुत जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने मास्टर प्लान अप्रूव किया है, उसके लिए पिछली बार यह पैकेज माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। उस समय माननीय धूमल जी प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। उस समय धूमल जी ने मांगा था और उन्होंने तीन राज्यों के साथ हिमाचल प्रदेश को भी यह पैकेज दिया था। दुर्भाग्यवश प्रदेश में ऐसी सरकार आ गई जिसने मास्टर प्लान बनाया ही नहीं। इन्होंने यह भी नहीं देखा कि यहां पर किस ढंग से डिवैलपमैंट हो, कहां पर इंडस्ट्री होनी चाहिए और कहां पर ग्रीन एरिया होना चाहिए और रेजीडेंशियल एरिया कहां पर होना चाहिए? बिना सोचे समझे उसकी हैप्हैजर्ड डिवेलपमैंट कर दी गई है। इसलिए वहां पर जिस ढंग से डिवेलपमैंट होनी चाहिए उस ढंग से नहीं हुई है। आपने अब जा करके मास्टर प्लान अप्रूव किया, अब उसका क्या फायदा है?

अध्यक्षः माननीय सदस्य प्लीज वाईंडअप कीजिए। You have spoken full time.

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः सभी सरकारों का इस प्रकार का हिसाब-किताब है। प्रदेश में इस टाईप का माहौल बना हुआ है। मुझे लगता है कि सरकार के पास 6-7 महीने का समय बचा हुआ है इसलिए सरकार को लोगों की सेवा ठीक ढंग से करनी चाहिए। सरकार लोगों की सेवा दिमाग से ज्यादा और दिल से कम करती है। अगर आपको लोगों के दिल जीतने हैं तो दिल से सेवा करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आप अगली बार आएं और विपक्ष में हों लेकिन आपकी स्ट्रेन्थ अच्छी हो। आप सब तो नहीं आएंगे लेकिन कम-से-कम 15-20 लोग आ जाएं। आपके विकास के कामों को देख करके लगता है कि आप सिंगल डिजिट में ही रह जायेंगे, जिस प्रकार से लोकसभा और उत्तराखंड में हुआ। हम चाहते हैं कि आप अच्छी स्ट्रैन्थ में आएं। कांग्रेस में भी कुछ लोग अच्छे हैं और हम चाहते

16/03/2017/1805/एन0एस0/डी0सी0/2

हैं कि वे जीत जाएं। मुझे लगता है कि ऐसा हो नहीं पायेगा जिस तरीके से आप (सत्ता पक्ष) काम कर रहे हैं। यह बजट हर वर्ष आता है और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। इस बार हमें जैसी उम्मीद थी, वैसा ही बजट इस मान्य सदन में आया है। मुझे पता है कि जाने वाले लोग कुछ नहीं करते हैं, अब तो केवल मात्र घोषणायें ही होनी हैं।

Speaker: Hon'ble Member no more speaking please.

श्री कृष्ण लाल ठाकुर : मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि आप में से 15-16 लोग जीत करके आएं और इधर (विपक्ष) बैठें और हमारी सरकार हो तथा हम राज्य को विकास की तरफ ले जाएं। इस सदन में बार-बार क्षेत्रवाद का मुद्दा उठा है।

Speaker: Not to be recorded.

श्री कृष्ण लाल ठाकुर : हमारी पार्टी (भाजपा) क्षेत्रवाद और जातिवाद में विश्वास नहीं करती है। अध्यक्ष महोदय, यह बजट दिशाहीन बजट है। यह बजट आंकड़ों का मायाजाल है। इसमें हमें न पिछली बार कुछ मिला था और न ही इस बार कुछ मिला है। इस बजट से लोगों को भी कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

16/03/2017/1805/एन0एस0/डी0सी0/3

श्री बम्बर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, 10 मार्च को माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए इस मान्य सदन में खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से ही माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी विधायकों के लिए अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए 1 करोड़ 10 लाख रूपये की निधि बढ़ाई है। मैं आपके माध्यम से इसके लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इस बजट का सबसे ज्यादा श्रेय माननीय वीरभद्र जी को जाता है।

इनके ही समय में यह निधि बढ़ने का कार्य चला है और अभी 2-3 वर्षों के अंदर यह राशि 1 करोड़ 10 लाख तक पहुंची है। हमारे पास डिस्क्रेशनरी फंड नहीं होता था। हम कभी किसी कार्यक्रम में जाते थे या किसी गरीब की मदद करनी होती थी तो उसके लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं होता था। इसके लिए भी हम मुख्य मंत्री जी के आभारी हैं कि

श्री आर0के0एस0----जारी

16/03/2017/1810/RKS/Ag/1

श्री बम्बर ठाकुर...जारी

उन्होंने 5 लाख रुपये सभी विधायकों को दिए जिससे सोसाइटी के अंदर हमारे इंस्टीट्यूशन्ज की रिस्पैक्ट भी बढ़ी है। जिस क्षेत्र में हम जाते हैं वहां पर हम कुछ-न-कुछ के देने लायक होते हैं। इसके लिए मैं सभी पक्ष व विपक्ष के विधायकों से चाहूंगा कि वे माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करें। विपक्ष के एकाध सदस्य को छोड़कर किसी ने भी माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद नहीं किया। वे केवल मात्र क्रिटिसिज्म ही करते हैं। यदि यह निधी ठीक नहीं है तो आपको लिखकर दे देना चाहिए कि हमे यह निधि नहीं चाहिए। आप अपने समय में विधायक निधि नहीं दे सके। डिस्क्रेशनरी फंड आप नहीं दे सके। प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा कार्य हो रहे हैं। सड़कों, रास्तों, सिंचाई स्कीमों और रूरल रोड्स को मैंटेन करने के लिए सरकार पैसा दे रही है। यह केवल-और- केवल राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। हमारे पास डिस्क्रेशनरी फंड नहीं होता था। वह भी राजा साहब ने दिल खोलकर दिया। उसके लिए आपको इनका धन्यवाद करना चाहिए। जब कोई चीज आपको मिल जाती है तो आप कहते हैं कि यह तो मिलना ही था। इसमें राजा साहब का कोई योगदान नहीं है। इस प्रकार की मानसिकता आप लोगों की हो तो भगवान ही आपका भला करने वाला है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इस टैन्योर के अंदर जो राजा साहब ने विकास के कार्यों को गति प्रदान की है, इसकी तुलना नहीं की जा

सकती है। आप कहते हैं कि केवल मात्र घोषणाएं हो रही है। हम आपको अपने जिला के आंकड़े दिखाएंगे। हमारे जो निचले क्षेत्र के किसान हैं, जो लोग भेड़-बकरियां पालते हैं, पहले बकरियों पर कोई सब्सिडी नहीं देता था। माननीय वीरभद्र सिंह जी ने किसानों का ध्यान रखते हुए बकरियों पर 60 प्रतिशत उपदान दिया है। लेकिन आप इसका विरोध कर रहे हैं। आपको इसका धन्यवाद करना चाहिए। आप कैसे किसान हितैषी हुए? इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में नाहन, हमीरपुर और चम्बा में मैडिकल कॉलेज दिए गये हैं। आपकी सरकार रही, आप सता में रहे परन्तु आप हमीरपुर को मैडिकल कॉलेज नहीं दे सके। आप लॉअर हिमाचल की बात कर रहे हैं। आप समान विकास की बात कर रहे हैं। आप चम्बा को मैडिकल कॉलेज नहीं दे सके। आपको

16/03/2017/1810/RKS/Ag/2

इन कॉलेजों के लिए ठाकुर कौल सिंह और राजा साहब का धन्यवाद करना चाहिए। यदि आपको चम्बा और हमीरपुर के अंदर मैडिकल कॉलेज नहीं चाहिए तो आप इसका विरोध कीजिए। यहां पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे तो आपने नाहन में मैडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोला? आप बिलासपुर में ट्रॉमा सैंटर की अधूरी बिल्डिंग का उद्घाटन करके चले गए और उसमें थियेटर भी नहीं बनाया गया था। एक सिम्पल बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया, न स्टाफ दिया और न ही थियेटेर। राजा साहब ने इसके लिए 43 लाख रुपये दिए और अब वहां ट्रामा सैंटर की बिल्डिंग के साथ थियेटर भी तैयार हो गया है। क्या अब हम ठाकुर कौल सिंह जी और राजा साहब का धन्यवाद न करें? क्या हम आपका धन्यवाद करें?

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

श्री बम्बर ठाकुर ....जारी

आप केंद्रीय मंत्री जी को पूछो। मैं अभी उनके बारे में बात करूंगा। ज़रा ठहरिए। मैं अभी अपनी बात रख रहा हूं। आप कह रहे हैं कि यह बजट खोखला है,सरकार के पास पैसे ही नहीं हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि आपने वहां पर अधूरी बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया। वहां पर अभी बिल्डिंग बनकर तैयार हुई और उसका पैसा हमारी सरकार ने दिया। वहां पर पानी का टैंक नहीं था। ठाकुर साहब और वीरभद्र सिंह जी ने हमें उसके लिए 15.00 लाख रुपये दिए। फिर वहां एक लाख लीटर पानी का ओवर हैड टैंक बना। पांच साल तक वहां से आपके स्वास्थ्य मंत्री रहे, वह नहीं दे सके। पांच साल तक स्वास्थ्य मंत्री रहे लेकिन वहां टैंक नहीं दे सके। वहां पानी नहीं था। वहां पर बदबू रहती थी। यह बात किसी ने नहीं उठाई। सीवरेज लाईन जगह-जगह पर टूटी थी। हम ठाकुर साहब और वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद न करें तो किसका करें? इन्होंने 10.00 लाख रुपया दिया जिससे वहां पर सीवरेज की सारी लाईन चेंज हो गई। फिर कोई गली-सड़ी लाश गोविंद सागर में मिल जाती थी या कहीं जंगल में मिल जाती थी तो उसे मॉर्चुरी में रख देते थे। इससे सारे अस्पताल का वातावरण खराब होता था। लेकिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने डैड हाऊस के लिए एक रुपया तक नहीं दे सके। आज वीरभद्र सिंह जी और ठाकुर कौल सिंह जी ने 43.00 लाख रुपया दिया। हम इनका धन्यवाद न करें तो किसका करें। वहां आधुनिक मॉर्चुरी बन रही है जिसके लिए 43.00 लाख रुपया दिया गया है। इसके लिए हम माननीय राजा साहब के धन्यवादी हैं। अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से ठाकुर साहब का धन्यवाद करते हैं। यह तो एक विभाग की बात थी। अब आप सुनते जाएं। आप स्वास्थ्य मंत्री की बात कर रहे हैं जो केंद्र में बैठे हैं कि उनका धन्यवाद करो। किसलिए करें? नेर चौक के अंदर मैडिकल कॉलेज बना जिसके लिए आपने कोई पैसा नहीं दिया और न अपने अधीन लिया। बाकी राज्यों में ले लिए लेकिन हिमाचल में नहीं लिया। फिर आप मुख्य मंत्री बनना

चाहते हैं। हिमाचल का मुख्य मंत्री बनना चाहते हैं लेकिन नेर चौक के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं दे सके। आज हम वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद न करें, उनको मुबारिकवाद न दें;

16.03.2017/1815/SLS-AG-2

ठाकुर साहब को मुबारिकवाद न दें तो किसको दें? इन्होंने अब उसे अपने अधीन लिया और प्रदेश सरकार उसमें पैसा लगा रही है। 732 युवाओं को अब वहां पर रोज़गार दिया जाएगा जिनमें स्टॉफ नर्सिज, पैरा-मैडिकल स्टॉफ और डॉक्टर्ज़ भी लगेंगे। इसके लिए किसका धन्यवाद करें? केंद्रीय मंत्री का करें? मुख्य मंत्री बनना चाहते हैं कि यहां मुख्य मंत्री बना दो। प्रदेश के अंदर हमने कोई काम नहीं करना है लेकिन हमें बना दो। क्या ऐसे होता है? माननीय मुख्य मंत्री राजा साहब ने बिलासपुर में सिंथैटिक ट्रैक के लिए अपने पहले के कार्यकाल में 5.00 करोड़ रुपया दिया था। आप उसको हमीरपुर ले गए। न एक विधायक ने बोला, न दूसरे ने बोला और न वन मंत्री ने बोला कि यह पैसा क्यों लेकर गए। आज हम फिर से वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करते हैं अब फिर कि 5.50 करोड़ रुपया बिलासपुर के सिंथैटिक ट्रैक के लिए उनके द्वारा मंजूर हुआ है और उसका काम चल पड़ा है। लेकिन आपके जो वन मंत्री थे, जो आज देश के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके सामने यह पैसा गया। सिंथैटिक ट्रैक का पैसा हमीरपुर को गया। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। ...(व्यवधान)... मैं उनका विरोध नहीं बल्कि बात-की-बात कर रहा हूं। आप पैसे की बात कर रहे हैं कि उन्होंने पैसा दिया। लेकिन उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। जो पैसा दिया था वह हमीरपुर लेकर के चले गए। ...(व्यवधान)...यहां पर एक माननीय सदस्य ने उनका नाम लिया था कि उन्होंने बिलासपुर के लिए AIIMS दिया, मैं तब चर्चा कर रहा हूं।...(व्यवधान)... कहा कि केंद्रीय मंत्री ने AIIMS दिया। मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं कि कहां दिया।...(व्यवधान)... AIIMS हमारी मनमोहन सरकार और UPA ने दिया।...(व्यवधान)... आज हमने ज़मीन भी उसके नाम पर कर दी लेकिन एक फूटी कौड़ी बिलासपुर को AIIMS के लिए नहीं मिली है।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : आप एक मिनट बैठिए। रवि जी आप क्या कहना चाहते हैं। बंबर जी आप एक मिनट बैठिए।...(व्यवधान)...

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि कई बार इस माननीय सदन में ऐसी बात उठती है कि नियमों के विपरीत बात न हो। जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे इस सदन के सदस्य नहीं हैं तो उनके बारे में टिप्पणी करना माननीय सदस्य को शोभा नहीं देता।

जारी ..श्री गर्ग जी द्वारा

16/03/2017/1820/RG/AS/1

----(**व्यवधान**)----

श्री रविन्द्र सिंह .... जारी....

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो बात उनके बारे में यहां की गई है उसको कार्यवाही से निकाला जाए। इसके अतिरिक्त मेरा सभी से अनुरोध है कि जो कोई व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, यदि उसके बारे में कोई अच्छी बात करनी है, तो कह सकते हैं, लेकिन कुछ गलत बोलना ठीक नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने ऐसी कोई टिप्पणी उनके बारे में नहीं की है, इन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं दिया।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप कमाल करते हैं उनके ऊपर इन्होंने पांच मिनट का भाषण दे दिया। इन्होंने नड्डा जी का नाम लिया।

अध्यक्ष : इन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं दिया।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप चाहे, तो कार्यवाही में देख लीजिए। --(व्यवधान)---अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि इसको कार्यवाही से निकाला जाए।

अध्यक्ष : मैं देख लूंगा, यदि कुछ ऐसा होगा तो उसको कार्यवाही से निकाल दूंगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले इनको भाषण तो पूरा करने दीजिए, बाद में देख लीजिए। ---(व्यवधान)---

अध्यक्ष : अगर कोई ऑब्जैक्शनेबल बात होगी, तो मैं उसको कार्यवाही से निकाल दूंगा। मैं रिकॉर्ड देखूंगा। माननीय सदस्य आप बोलिए।

16/03/2017/1820/RG/AS/2

श्री बम्बर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा कि 1328 नए सरकारी विद्यालय प्रदेश में खोले गए हैं। कुछ अपग्रेड किए हैं। ये लोग कहते थे कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए। जब स्कूल खुल गए, तो कहते हैं कि उनमें अध्यापक नहीं हैं। लेकिन आज मुख्य मंत्री जी ने अध्यापक भी लगा दिए। आज हमारे हमारे बिलासपुर में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहां अध्यापक न हो। कहीं एक-दो जगहों पर कोई कमी होगी, लेकिन अभी इन्टरव्यू चल रहे हैं और पूरे प्रदेश में हर रोज इन्टरव्यू हो रहे हैं। इस बात की इनको परेशानी हो रही है कि हम दुबारा यहां सरकार बनाएंगे। तो मैं इनसे कहूंगा कि ये दुबारा भी जीतने वाले नहीं हैं। चिन्ता न करें, वीरभद्र सिंह जी की सुनामी फिर से यहां चलने वाली है और यहां फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम उनको फिर से मुख्य मंत्री बनाएंगे। पंजाब में इन्होंने देख लिया कि इनकी मात्र दो सीटें आईं। धर्माणी जी ने ठीक कहा था, लेकिन ये इनकी बात को भी तोड़-मरोड़ रहे हैं। ---(व्यवधान)----यू.पी. हमारे नजदीक का प्रदेश नहीं है। वहां बाप-बेटे की लड़ाई हुई और ये कहते हैं कि मोदी लहर थी। तो वहां मोदी लहर कोई नहीं थी। अगर मोदी लहर होती, तो पंजाब में केवल मात्र इनके दो ही आदमी जीतकर न आते। इसका जवाब पंजाब की जनता ने तो दे दिया। अब हिमाचल प्रदेश की जनता देने वाली है। अमृतसर से लोक सभा की सीट पर इनके वित्त मंत्री दो लाख से ज्यादा वोटों से हारे थे। अभी भी ये वहां हुए उप चुनावों में हारे हैं। इसलिए ये क्या बात करते हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर किसी ऐसे सदस्य का नाम कोट नहीं करना चाहता जो यहां नहीं हैं। लेकिन यहां पहले इनकी तरफ से कोट किया गया था। इन्होंने कहा कि हमारे केन्द्रीय नेतृत्व ने यह दिया, वह दिया। अब मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं और इनको उत्तर दे रहा हूं कि उन्होंने यहां फूट कोड़ी नहीं दी। ऐम्स के लिए एक फूटी कोड़ी नहीं दी। बजट में कुछ नहीं रखा। इसके विरूद्ध जो वीरभद्र सिंह जी ने दिया, मैं तो उसको गिना रहा हूं। हमारे मंत्री और सरकार प्रदेश की जनता को दे रही है, मैं तो वह गिना रहा हूं। लेकिन इनको ये बातें अच्छी नहीं लगतीं और ये बातें रिकॉर्ड में नहीं आनी चाहिए। इसलिए ये

हल्ला कर देते हैं। आप लोग वरिष्ठ हैं, पहले बात को सुनिए। यदि इनको कोई बात बुरी लगती है, तो उसके बाद उठकर बोलिए कि यह गलत बात है, लेकिन मैं आंकड़ों के ऊपर बात कर रहा हूं और उससे बाहर नहीं जा रहा हूं।

16/03/2017/1820/RG/AS/3

अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे नौजवान बच्चे हैं, सबको फ्री ट्रेवलिंग की सुविधा किसने दी? हमारी सरकार, मुख्य मंत्री जी और हमारे परिवहन मंत्री जी ने यह सुविधा दी। हम उनको धन्यवाद न करें, तो क्या आपका धन्यवाद करें? ये कहते हैं कि इस बजट में कुछ नहीं है। क्या हमारे बच्चे बसों में फ्री ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं? क्या बच्चों को दो-दो वर्दियां नहीं दी जा रही हैं? इसमें भी इनको दर्द हो रहा है। यदि इनको यह सब अच्छा नहीं लगता, तो ये सड़कों पर जाएं और विरोध करें और कहिए कि बच्चों को बसों में मुफ्त यात्रा नहीं मिलनी चाहिए। यदि आपके अंदर हिम्मत है, तो इसको बाहर जाकर कहिए और कहिए कि महिलाओं को भी कम किराये पर बसों में मत ले जाइए। यहां बातें करते हैं। आप अपने भाषणों को लेकर वहां जाइए। हमने पेन्शन बढ़ाई, लेकिन इसका भी इनको दर्द हो रहा है, हमने इसको 450/-रुपये से लेकर 650/-रुपये पर पहुंचाया, तो भी इनको बुरा लग रहा है। इनकी तनख्वाह बढ़ाई। यदि इसका भी इन्हें दर्द है, तो ये लिखकर दें। इन्हें जो-जो चीजें अच्छी नहीं लगतीं, ये लिखकर दे दें।

एम.एस. द्वारा जारी

16/03/2017/1825/MS/AG/1

श्री बम्बर ठाकुर जारी----

आप लिखकर दे दीजिए कि हमें तनख्वाह भी नहीं चाहिए और बुजुर्गों की पैंशन भी नहीं चाहिए। आप लिखकर दे दीजिए कि बच्चों को बसों में फ्री यात्रा की सुविधा और मुफ्त में

वर्दी की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा 1000 नौजवानों को जो वीरभद्र सिंह जी ने नये बस रूट परमिट देने की घोषणा की है और अब देने जा रहे हैं, वह नहीं मिलने चाहिए, ऐसा भी आप लिखकर दीजिए। क्योंकि इनको मालूम है कि 1000 नौजवानों के साथ 3000 परिवार और जुड़ने वाले हैं। बस का ड्राइवर और कन्डक्टर भी इसलिए इनको चिन्ता सता रही है कि हम इस सीट के ऊपर अब कैसे आएंगे। परन्तु आप लोग इधर आने वाले नहीं हैं। आप लिखकर दे दीजिए कि हमें ये चीजें नहीं चाहिए। -(व्यवधान)- यदि हमने रूट लिए तो हमने चलाए भी और सरकार ने अब यह योजना बनाई है, कौंडल साहब, हम पहले से बच्चों को अपनी बसों में मुफ्त यात्रा करवाते थे जिसकी वजह से हम यहां पहुंचे हैं। आप बताइए, आपने कौन सा सामाजिक काम अपने राजनीतिक जीवन के अंदर किया है? हम आपको इसके सैंकड़ों उदाहरण दे सकते हैं। हम आपको उदाहरण दे सकते हैं कि हमने क्या-क्या किया है। आवास योजना की राशि को 48,500/-रुपये से हमारे मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने और हमारी सरकार ने 1 लाख 30 हजार रुपये पर पहुंचाया है। आप लोग उन गरीबों का विरोध कर रहे हैं जिस गरीब को मकान नहीं मिलता था? इसके लिए थोड़ी विपक्ष के लोगों को थोड़ी शर्म करनी चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अभी वहां से एक वक्ता कह रहे थे कि गांव की सड़कों का क्या होगा? गांव की सड़कें ठीक नहीं है। अब मुख्य मंत्री जी ने 20 करोड़ रुपया दे दिया तो उसकी भी आपको दर्द हो रही है। अब जब पैसा दे दिया है तो वे सड़कें भी ठीक हो जाएंगी। फिर आप गांव में जाकर क्या बोलेंगे? अब 20 करोड़ रुपया दे दिया है, आप इसका विरोध कीजिए। आप लिखकर दे दीजिए, आप सड़कों पर जाइए और आप वहां जुलूस निकालिए कि यह पैसा नहीं मिलना चाहिए। तब हम आपका दम मानते हैं।

16/03/2017/1825/MS/AG/2

इसी तरह से मुख्य मंत्री जी ने 1000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देने की बात कही है। आप लोग रुक जाइए हम महीने-दो महीने के अंदर इसे देना शुरू कर देंगे आप क्यों चिन्ता कर रहे हैं? हम 1000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देने जा रहे हैं और आपको उसकी चिन्ता सता रही है कि अब सारे नौजवानों ने वीरभद्र सिंह जी का गुणगान करना शुरू कर दिया है? अगर आपको उसका भी विरोध करना है तो आप सड़कों पर आइए और विरोध कीजिए।

हर क्षेत्र में 19000 नई नौकरियां नौजवानों के लिए निकाल दी हैं। आप बताइए आपके समय में कितने लोगों को नौकरियां दी गईं? आपने तो अपने समय में उन पर घोड़े

दौड़ाए,कर्मचारियों को पीटा बल्कि बागवानों और कर्मचारियों के ऊपर गोलियां चलाईं। ये आपकी सरकारें रही हैं। वीरभद्र सिंह जी का हम धन्यवाद न करें तो किसका धन्यवाद करें? "कौशल विकास भत्ता" दिया जा रहा है और 100 करोड़ रुपये का बजट इसके लिए रखा गया है। मुख्य मंत्री जी ने नौजवानों के लिए "खेल विकास योजना" शुरू की है जिसमें 10 लाख रुपया प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में बच्चों के खेल के विकास के लिए दिया जाएगा। यदि आपको यह नहीं चाहिए तो आप मुख्य मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए, हम अपने चुनाव क्षेत्रों में उस पैसे को लगा देंगे। लेकिन आप केवल-मात्र विरोध ही करते हैं। आप लोग बोलने से पहले सोचिए कि हम क्या बोल रहे हैं। मेरे बिलासपुर को वीरभद्र सिंह जी ने महिला थाना दिया। कौंडल जी, आपको तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बिलासपुर की बात है। आप तो नहीं ला पाए। आप भाजपा सरकार के समय एक बार मंत्री रहे और एक बार डिप्टी स्पीकर रहे और आप कह रहे हैं कि बिलासपुर में क्या हो रहा है? हम बिलासपुर में वीरभद्र सिंह जी से महिला थाना लेकर गए इसलिए आप भी उनका धन्यवाद करो। कौंडल साहब, आप यहां पंगा मत लो। फिर ये कहते हैं कि इस बजट में कुछ नहीं है? मैं व्यक्तिगत तौर पर न आपको कुछ बोलता हूं और न रणधीर शर्मा जी को बोलता हूं लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर मुझे बोलेंगे तो आप सुनेंगे भी। मेरी चादर बिल्कुल साफ है। जिसने जो बोलना है बोलिए और उसको प्रूव करके बताइए। हम लड़ाई लड़ना जानते हैं। मैं राजनीतिक परिवार से नहीं आया हूं बल्कि एक साधारण परिवार से आया हूं। मैं अपने दम पर और वीरभद्र सिंह जी वजह से

16/03/2017/1825/MS/AG/3

लड़ाई लड़कर यहां आया हूं और अगली बार फिर से यहां आऊंगा लेकिन बिना मतलब से पंगा मत लीजिए।

वॉटर गार्डों का माननीय मुख्य मंत्री जी ने मानदेय बढ़ाया, इसके लिए हम मुख्य मंत्री जी के धन्यवादी हैं। पंचायत चौकीदारों, सिलाई अध्यापिकाओं और मिड-डे-मील वर्कर्ज के पैसे भी बढ़ाए हैं। हमें केन्द्र सरकार से पैसा आना चाहिए था,

जारी श्री एस0एस0 द्वारा----

16.03.2017/1830/SS-DC/1

श्री बम्बर ठाकुर क्रमागतः

आप बोलते हैं कि मोदी साहब ने यह कर दिया। मोदी साहब ने वह कर दिया। मिड डे मील वर्कर्ज़ को आप कुछ नहीं दे पाए। वह पैसा भी वीरभद्र सिंह जी को देने को बोल रहे हैं। प्रदेश के अंदर राजा साहब काम कर रहे हैं इसलिए आप दे दीजिए। केन्द्र से हिमाचल में आते नहीं हैं और ऐम्ज़ का शिलान्यास नहीं कर पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की वीरभद्र सिंह जी की लोकप्रिय सरकार ने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए तमाम फॉरमैलिटीज़ पूरी कर ली हैं। मैं यहां से चाहूंगा कि केन्द्र सरकार से कहें, नड्डा जी से कहें कि आप इसे कर दो। प्रदेश सरकार ने जमीन भी दे दी, पैसा भी दे दिया, अब आपने इसे क्यों रोका है? आप मोदी जी को बुलाईये, नड्डा जी को बुलाईये लेकिन आपने हमारे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास क्यों रोका है? इस बात का जवाब आपके पास कोई है? आप इस बात का जवाब दीजिये। पब्लिक जानना चाहती है, बिलासपुर की जनता इसका जवाब चाहती है कि आपने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास क्यों रोका है? बिलासपुर के बच्चों को बाहर के जिलों के अंदर इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने के लिए क्यों जाना पड़ रहा है? उसकी केवलमात्र वजह आप हैं। राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस काम को आप कर रहे हो।

Speaker: Kindly wind up now.

श्री बम्बर ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वाइंड अप करने जा रहा हूं। --(व्यवधान)-- मेरा टारगेट कोई नहीं है। कौंडल साहब, आप बीच में मत बोलो। जब आप बोलते हैं तो हम नहीं बोलते। लेकिन मेरा टारगेट सही है। मैं अपने टारगेट पर चल रहा हूं। मैं एक बात कर रहा हूं कि मेरा टारगेट सीधा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर वीरभद्र सिंह जी की लोकप्रिय सरकार तमाम विकास के काम कर रही है। जिनको लेकर ऑपोजिशन के लोग टिप्पणियां

कर रहे थे। मैं फिगर एंड फैक्ट्स पर बोल रहा हूं। बिलासपुर के अंदर जितने +2 स्कूल खुले। उसमें आपको भी मिला। आप भी राजा साहब के पास गए कि मेरे को दो स्कूल दे दो। राजा साहब ने आपका

16.03.2017/1830/SS-DC/2

भी ख्याल रखा। आपको एस0डी0एम0 का दफ्तर झण्डुता में दिया। आप उसका धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। रणधीर जी को स्वारघाट में एस0डी0एम0 का दफ्तर दिया। सोलदा में आई0टी0आई0 दी। आप इसके लिए धन्यवाद तो कर दो। आपने कुछ सीखा ही नहीं है। धन्यवाद करिये। आपको डिग्री कॉलेज दिया। एस0डी0एम0 का दफ्तर दिया। बड़गांव से झण्डुता को पुल दिया। गेहड़वी के अंदर आई0टी0आई0 दी। ऐसे ही नैनादेवी के अंदर काम हुआ। समान विकास वीरभद्र सिंह जी कर रहे हैं। कहीं पर भी भेदभाव नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको भेदभाव के बारे में बता रहा हूं जोकि आपने मेरे चुनाव क्षेत्र से किया। मेरे चुनाव क्षेत्र के जो पैसे मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी की तत्कालीन सरकार में मंजूर हुए थे, वे पैसे यहां से वापिस हुए थे। हमीरपुर को लेकर गए थे। आज राजा साहब ने वे दोबारा दिए। अब उसका धन्यवाद नहीं करें तो किसका करें। शिशु वार्ड हमारा बिलासपुर के अस्पताल में नहीं था। 1960 में बिलासपुर का अस्पताल बना। आप शिशु वार्ड तक नहीं बना पाए। 32 लाख रुपया शिशु वार्ड के लिए मिला। वहां पर हमारे पास जनरेटर नहीं थे और 37 लाख रुपये के तीन जनरेटर बिलासपुर के अस्पताल के अंदर मिले। रघुनाथपुरा के स्कूल को 23 लाख रुपया भवन के लिए मिला। बंदला के स्कूल को 21 लाख रुपया मिला। पंजगाई के स्कूल को 25 लाख रुपया मिला। बरमाणा के स्कूल को 25 लाख रुपया मिला। धाटरो के स्कूल को 42 लाख रुपया मिला। बल्हघाट का स्कूल वीरभद्र सिंह जी ने प्लस टू किया। धाटरो का स्कूल वीरभद्र सिंह जी ने प्लस टू किया। दसगांव का स्कूल जो आपके एक्स एम0पी0 के गांव का स्कूल है वह वीरभद्र सिंह जी ने प्लस टू किया। उनके गांव की सड़क को एक करोड़ 52 लाख रुपये से पक्का करके एक साल के अंदर-अंदर वीरभद्र सिंह जी ने दिया। हवान के स्कूल को 15 लाख रुपया दिया। गोलमठानी के स्कूल को 11 लाख

रुपया दिया। तलवाड़ा के स्कूल को भवन के लिए 84 लाख रुपया दिया। भवन बनकर तैयार हो गए हैं और आप बोलते हैं कि कुछ नहीं मिला। यह मैं बिलासपुर के स्कूलों की बात कर रहा हूं।

Speaker: Wind up please.

16.03.2017/1830/SS-DC/3

श्री बम्बर ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं एक सैकिंड में समाप्त कर रहा हूं। ये पैसे हमारे माननीय वीरभद्र सिंह जी की कृपा से मिले हैं। हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए 1818 करोड़ रुपये फोरलेन के लिए वीरभद्र सिंह जी दिल्ली सरकार से लेकर आए। आप उसका भी धन्यवाद नहीं कर पा रहे हैं। 1818 करोड़ रुपया का फोरलेन वीरभद्र सिंह जी लेकर आए। आपने तो केवल मात्र बड़े-बड़े होडिंग्ज़ लगा दिये, वह भी मुख्य मंत्री बनना चाहता है। सुनिये, एक बोर्ड रानीकोटला से बटोलदेवी लगा दिया कि एन0एच0 बनेगा। रानीकोटला कोई कलकत्ता शहर है या बटोलदेवी कौन-सा बड़ा शहर है?

जारी श्रीमती के0एस0

16.03.2017/1835/केएस/डीसी/1

श्री बम्बर ठाकुर जारी----

ऐसे-ऐसे होर्डिंग्ज़ लगा दिए लोगों को मूर्ख बनाने की नीयत से। उसके 12 साल के एम.पी. के कार्यकाल के अन्दर बिलासुपर में एक हैंड पम्प लगा वह भी अपने आंगन में लगाया और बनना चाहता है मुख्य मंत्री? पूरे देश ने देखा रिश्वत खाते हुए, ऐसे लोग आपकी पार्टी के अन्दर हैं। फालतू की बातें करते हैं। बच्चों के ऊपर राजनीति करते हैं। आपने बिलासपुर के अंदर रैली की, आपने मेरा नाम चार्जशीट में लिखा कि बम्बर ठाकुर की फोर लेन में दख़लंदाज़ी है। आप लोग विकास के मुद्दे से लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। फोर लेन के

अंदर हमने क्या खाया और आपके लोगों ने क्या खाया, उसके लिए आदरणीय वीरभद्र सिंह जी ने एक कमेटी बनाई है । ब्लास्टिंग का बहाना ले कर आपके लोगों ने वहां पर करोड़ों रु0 के ठेके लिए हैं। मैंने इसी माननीय सदन में कहा है कि इस हाऊस के अन्दर तस्वीरें आ जानी चाहिए कि किस-किस के पास कितना-कितना काम है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया अब समाप्त करें।

श्री बम्बर ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने, सुधीर शर्मा जी ने, मुकेश अग्निहोत्री जी ने कौशल विकास भत्ता, बिलासपुर के लिए एन.ई.एल.एम., नैनादेवी के लिए एन.ई.एल.एम., घुमारवीं के लिए एन.ई.एल.एम., प्रोजैक्ट ये जो मिशन हमारे लिए वहां पर हमारे मंत्री, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है, उसके लिए मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह बजट बिल्कुल खुशहाली ले कर पूरे प्रदेश के अंदर आ रहा है जिसका दर्द इनको जरूर है लेकिन हम इस बजट भाषण का, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने साढ़े चार घण्टे बजट भाषण पढ़ा, समर्थन करते हैं। आपको एक और ज्ञान होना चाहिए।

16.03.2017/1835/केएस/डीसी/2

अध्यक्षः माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री बम्बर ठाकुरः अध्यक्ष जी, जब मुख्य मंत्री जी यहां पर बजट भाषण पढ़ रहे थे तो ऊपर से इन्द्र देवता बर्फ बरसा रहे थे। बर्फबारी हो रही थी। जब तक भाषण हुआ, तब तक बर्फ पड़ती रही और जैसे ही भाषण खत्म हुआ, बर्फबारी भी बन्द हो गई। इस बजट भाषण का समर्थन करते हुए आपने मुझे बोलने का समय दिया, अध्यक्ष महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

16.03.2017/1835/केएस/डीसी/3

श्री नरेन्द्र ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा जितने भी वक्ता सत्ता पक्ष से बोले रहे हैं या बोलने वाले हैं,

ये सभी एक ही बात से शुरूआत कर रहे हैं कि माननीय वीरभद्र सिंह जी ने बजट भाषण पढ़ने में साढ़े चार घण्टे लगाए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। जो 40 मिनट में बजट भाषण पढ़ा जाना था उसको साढ़े चार घण्टे में पढ़ा तो यह तो आपकी सरकार और मुख्य मंत्री जी की कार्यकुशलता का परिणाम देता है। जिस बजट को 40 मिनट में पढ़ा जाना चाहिए था, उसको साढ़े चार घण्टे में पढ़ा और आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो जब बजट पढ़ने में ही आपने साढ़े चार घण्टे लगा दिए तो उसको इम्पलीमैंट करने के लिए पता नहीं आप कितने साल लगाएंगें, आपकी कार्यकुशलता का पता तो यहीं से लग जाता है। हां, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो यहां पर हुआ कि इस ढंग से बजट पढ़ा गया जैसे रामलीला में नाटक दिखाते हैं। पीछे से एक डिक्टेट करता है और कलाकार उसको आगे जा कर बोलता है। सुधीर शर्मा जी पीछे से बोल रहे थे और मुख्य मंत्री जी उसको आगे पढ़ रहे थे। तभी एक-एक संटैंस को पढ़ने में पांच-पांच मिनट लगे और जो 40 मिनट में बजट पढ़ना था, उसको साढ़े चार घण्टे लगे। आप कह रहे हैं कि यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है? इस टाईप का वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको ही मुबारक हो। आपने साढ़े चार घण्टे में बजट पढ़ा तो निकला क्या? हमने भी बजट पढ़ा इसमें नया कुछ नहीं था और जैसे कहते हैं न कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी...

16.3.2017/1840/av/as/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर------- जारी

इस बजट में डायरैक्शन और विजन जैसा कुछ नहीं है। मैं तो यह कहता हूं कि यह बजट पता नहीं किस अनाड़ी से तैयार करवाया है। इस बजट का अगर सारांश निकाले और भविष्य में भी अगर इसी प्रकार के बजट आते रहे तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश का दिवालिया निकलने वाला है। इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर आपके पास

कोई पॉलिसी या विज़न नहीं है तो आप उसके लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी को तो फोलो करो। वह ढाई साल के अर्से में हमारे देश को कहां से कहां ले गये। आदरणीय जगजीवन पाल जी, मैं आपसे सवाल करता हूं। (--व्यवधान---) आप मेरी बात सुन लो। कहां से कहां ले गये। आप अपने भाषण में डीमोनेटाइजेशन की बात कर रहे थे। (--व्यवधान---) अब सुन लो। आप अपने भाषण में डीमोनेटाइजेशन की बात कर रहे थे। मुझे बड़ा दुःख है क्योंकि आप यह कह रहे थे कि डीमोनेटाइजेशन के दौरान डेढ़-दो सौ व्यक्तियों को लाइन में खड़े होकर हार्ट अटैक हो गया। (--व्यवधान---) अब आप सुनिए। मेरी बात सुनिए। जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा इत्यादि का रिजल्ट आया उसके बाद आप जैसे लोगों को कितने हार्ट अटैक हुए? आप मुझे उसके बारे में भी बताना।(--व्यवधान---) आप मेरी बात सुन लीजिए। हार्ट अटैक तो यहां पर भी हो सकता है। हार्ट अटैक तो हवाई जहाज में भी हो सकता है। हार्ट अटैक तो बैड रूम में भी हो सकता है। माना लाइनों में खड़े होकर लोगों को हार्ट अटैक हुआ और लोग दुःखी थे तो उन्होंने कितने ए0टी0एम0 तोड़ दिए, उन्होंने कितनी बसें फूंक दी? आप इस बात को अभी भी नहीं पचा पा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ(--व्यवधान---) पंजाब में हमारा क्या है वहां तो हम केवल 20 सीटों पर इलैक्शन लड़ रहे थे। वहां पर हमारा अकाली दल के साथ गठजोड़ था। इन सारे परिणामों को देखकर आप अपने आपको कहां पर संतुष्ट कर रहे हैं? आप उत्तराखंड में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए। आपका सफाया हो चुका है मगर फिर भी आप बात मानने को तैयार नहीं है। (--व्यवधान---) मेरी बात सुन लो। यह बजट बिल्कुल विजनलैस और डायरैक्शनलैस है। मैं आपको

16.3.2017/1840/av/as/2

थोड़े से आंकड़े पढ़कर बताता हूं। कृपया आपने मेरी बात सुन लेना। जब आपने यहां पर बजट पेश किया तो इसको 1876 करोड़ रुपये के घाटे से ओपन किया। इस वर्ष की जो टोटल रिसीट्स हैं यानि रैवन्यू और कैपिटल को मिलाकर जो टोटल अकाऊंट बनता है वह इस वर्ष 35782 करोड़ रुपये की है। इस बार का जो बजट का खर्च है वह 37782

करोड़ रुपये है। अगले साल यह बजट 8580 करोड़ रुपये के घाटे से ओपन होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि टोटल बजट में से जो आपने इस बार पेश किया उसका 27 प्रतिशत पे में चला जायेगा। 14 प्रतिशत पेंशन में जायेगा और 20 प्रतिशत लोन को वापिस करने में चला जायेगा। आपके पास विकास के लिए केवल 40 प्रतिशत पैसा बचेगा। 20 प्रतिशत भ्रष्टाचार में जायेगा फिर आपके पास केवल 20 प्रतिशत पैसा बचेगा जिससे आप 80 लाख लोगों का विकास करेंगे। यहां पर बड़े चीख-चीखकर कहा जा रहा है कि हम इस प्रदेश का बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं। यहां पर जो बजट पेश किया गया मैं आपको उसके आंकड़े बता रहा हूं। इसमें आपकी अपनी प्रदेश की आय केवल 27-28 प्रतिशत है और बाकी सारी यानि 50 प्रतिशत से ज्यादा केंद्र सरकार एड देती है। बजट बनाने वालों ने यह नहीं सोचा कि अगर केंद्र में कभी वार हो जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है और केंद्र एड देने में असमर्थ हो जाता है तो आपकी स्टेट का क्या हाल हो जायेगा। आपकी स्टेट का दिवालिया निकल जायेगा। (--व्यवधान---) मैं इसीलिए कह रहा हूं और संघीय ढांचा बाऊंड नहीं है। इस बार विकास के ऊपर आपने पिछले कई सालों के मुकाबले राशि कम कर दी है।

श्री वर्मा द्वारा जारी

16/03/2017/1845/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर..... जारी।

आपने पैसा कहां डाइवर्ट किया है? जैसे ऊंट के मुंह में जीरा डालते हैं, आप सोशल वैलफेयर की बात कर रहे हैं, कईयों को 50,200,150 रूपये बढ़ा दिए और अब चीख-चीख कर कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सरकार का बेसिक पर्पज़ है कि विकास के कार्य में मैक्सिमम पैसा खर्च हों। आप विकास के ऊपर पैसा कम खर्च कर रहे हैं और छोटे-छोटे इंसेंटिव देने के लिए, वोट लेने के लिए वहां आप पैसे को डाइवर्ट कर रहे हैं। अभी बेरोजगारों की बात कर रहे थे कि 1000 रूपया हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। ये

कितने करोड़ का खर्चा है, ये पैसा कहां से आएगा? सोर्स आपके पास है नहीं, सोर्स पैदा करने के लिए बज़ट में कोई प्रावधान नहीं हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप बेरोजगारों को भत्ता दे नहीं पायेंगे। अगर आप देंगे भी तो विकास का पैसा जो 20 परसेंट है, आप उसको कट करके वहां डाइवर्ट करेंगे? ऐसे खोखले वायदे करने से आपको यहां कुछ नहीं मिलेगा। आप बिना इनकम जनरेट किए सामाजिक कल्याण की बात कर रहे हैं, ये तो आपकी हालत है। एग्रीकल्चर के बारे में बड़ी चर्चा हुई। वर्ष 1950-51 में प्रदेश की जो अपनी आय थी, उसका 55 परसेंट हिस्सा एग्रीकल्चर से आता था। वर्ष 1967-68 में यह 26 परसेंट रह गया और अब 9.04 है। आपको 9.04 परसेंट एग्रीकल्चर से आता है और कुल 55.67 हैक्टेयर भूमि में से 9.55 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि हैं। 80 परसेंट लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं और 80 प्रतिशत खेती वर्षा पर निर्भर करती है। आपके पास किसानों को इरिगेशन या अन्य इंसेंटिव देने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं हैं। जो 80 परसेंट अन-इरिगेटिड एरिया है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाया जाये, इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। हम यहां पर चर्चा तो करते हैं कि किसानों को बंदरों, जंगली जानवरों आदि से नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। आप कांटे वाली तारों की बात करते हैं, हमारे एम0एल0ए0 फण्ड में ये प्रावधान था कि हम अपने एम0एल0ए0 फण्ड से कांटे वाली तार लगाने के लिए पैसा दे सकते थे, लेकिन इस सरकार ने इस बार की गाइडलाइन्ज़ में उसको भी हमारे से छीन लिया है। पहले आप इसके लिए सबसिडी 60:40 की रेशो से दे रहे थे और अब 80:20 की रेशों से दे रहे हैं, लेकिन इनको कोई नहीं लगा रहा है। इसके

16/03/2017/1845/टी0सी0वी0/ए0जी0/2

लिए जेब से कोई नहीं खर्चेगा। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि हम जो राशि एम0एल0ए0 फण्ड से देते थे, उसको दोबारा गाइडलाइन्ज़ में एड किया जाये, ताकि हम किसानों का भला कर सकें। यहां माननीय सदन में एजुकेशन के ऊपर बड़े जोर-जोर से बातें की जा रही थी। आपने बड़े जोर-शोर से कहा कि बड़े भारी स्कूल खोल दिए हैं। बड़े भारी प्राइमरी स्कूल खोल दिए हैं, इनमें अध्यापक अप्वाईंट किये गये। मान लिया ये अध्यापक आपने अप्वाईंट किये। क्या वज़ह है कि इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के

बावजूद आपके स्कूलों से विद्यार्थियों का पलायन प्राइवेट स्कूलों में हो रहा है। एक भी वक्ता ने इसके बारे में नहीं बोला और न कोई जवाब दिया। आज 50 परसेंट छात्र सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल बहुत थोड़े हैं। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? आप अरबों-करोड़ो रूपये की सुविधाएं दे रही हैं, अरबों-करोड़ों रूपये का आप वेतन दे रहे हैं, लेकिन इसके बारे में आप चुप है। कोई भी एजुकेशन देने में आप बिल्कुल असमर्थ है। आप कहते हैं कि हमारी स्टेट 90 परसेंट शिक्षित हो गई है, जो अपने दस्तख्त कर लेता है, उसको आप शिक्षित मान लेते हैं।

श्रीमती एन0एस0 ..... द्वारा जारी।

16/03/2017/1850/एन0एस0/ए0एस0/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर -----जारी

आपका यही क्राईटीरिया है कि जो अपने हस्ताक्षर कर ले, वह पढ़ा-लिखा हो गया,चाहे वह स्कूल गया हो या नहीं। आपकी सरकार क्वालिटी ऑफ ऐजुकेशन देने में टोटली फेल रही है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया है। कालेजिज के पास alternative नहीं हैं। प्राईवेट कॉलेजिज बहुत कम हैं, अदवाईज आपके सारे-के-सारे कॉलेज खाली रह जाते। एक ग्रैजूएट पास छात्र सिम्पल ऐप्लीकेशन नहीं लिख सकता है। ऐसी शिक्षा आप प्राईमरी से ले करके ग्रैजूएशन तक दे रहे हैं। आप किसको गुमराह कर रहे हैं और आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं। आपने चार सालों में क्या किया है? शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या सुधार किए हैं? आपने अपने कार्यकाल के दौरान फट्टे जरूर लगाये हैं। अध्यक्ष महोदय, इस मान्य सदन में एक बात बड़े जोर-शोर से कही जाती है कि हमारी भ्रष्टाचार के बारे में जीरो टॉलरेंस है। अध्यक्ष महोदय, इस बात को बार-बार वे लोग कहते हैं, जो खुद ही इसमें इनवॉल्व हैं। मैंने पीछे एच0आर0टी0सी0 का मुद्दा उठाया था कि इस विभाग के पांच ऑफिसर्ज़ के खिलाफ अब एफ0आई0आर0 रजिस्टर्ड हुई है। यह केस क्या

था? मैं आपको बताता हूं। यह केस वर्ष 2004 का था और इसमें पूरी कोशिश की गई कि एफ0आई0आर0 रजिस्टर्ड न हो। पुलिस ने यह केस रजिस्टर्ड ही नहीं किया। एक व्यक्ति प्राईवेट कम्पलैंट फाईल करके कोर्ट में गया और 13 सालों के बाद कोर्ट की डायरैक्शन के ऊपर एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है। यह बड़ी हैरानी की बात है। आखिरकार उन पांच अफसरों के ऊपर एफ0आई0आर0 दर्ज हो गई और केस शुरू हो गया। इस केस में उनको सजा भी हो जाएगी क्योंकि यह केस बड़ा फुलप्रूफ है। लेकिन जिन्होंने उनसे यह काम करवाया, वे यहां पर बहुत हंसते हैं। नगरोटा से 77 और रोहडू से 37 कंडक्टर लगे तथा जो चार बच्चे टॉपर थे, उनके 98 व 99 नम्बर थे तथा 305 टॉपर बच्चों से एक बच्चा इसमें सलेक्ट हुआ और 304 को इग्नोर किया गया। इसमे इतनी बड़ी धांधली हुई है। इसमें पैंसिल से लिख करके नम्बर बढ़ाये गये हैं। इसमें इतना

16/03/2017/1850/एन0एस0/ए0एस0/2

बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 13 साल तक पुलिस स्टेशन में एफ0आई0आर0 करने से रोका गया है। यह केस वर्ष 2004 का है। उसके बाद भी जितनी कंडक्टर भर्तियां हुई हैं, सबमें हेरा-फेरी हुई है। फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारी भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस है। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि मैंने जो मामला यहां पर उठाया है, इसका वे मुझे जवाब दें। इस मान्य सदन में मैंने जब टेंडर ऑफिसर्ज की लिस्ट मांगी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वे करप्ट नहीं हैं, अभी तक उनके ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है और उनके ऊपर इन्कवायरी चली हुई है। आपने तो भ्रष्टाचार की डेफिनिशन ही बदल दी है। अगर किसी ने कोई अफेन्स किया हो तो पहले उसकी एफ0आई0आर0 होती है। एफ0आई0आर0 के बाद ही इन्वेस्टगेशन होती है और उसके बाद केस कोर्ट में जाता है तथा फिर चार्जशीट लगती है। एफ0आई0आर0 उसी के ऊपर दर्ज होती है जिसने अफेन्स किया हो। यह कहते हैं कि एफ0आई0आर0 दर्ज होना, इन्वेस्टगेशन होना और चार्जशीट लगना यह कोई अफेन्स नहीं है। कोर्ट में केस कैसे छूटते

हैं? यह हम सब जानते ही हैं। इनोसेंट को सजा हो जाती है और क्रिमनल वरी हो जाता है। जजों को खरीदा जा सकता है। गवाहों के एविडैंस अपने हक में दिला दिए जाते हैं। फिर कहते हैं कि कोर्ट का वर्डिक्ट तो मेरे हक में आया है इसलिए मैं इनोसेंट हो गया। लेकिन वास्तव में हमने देखा है कि सरेआम मर्डर और रेप होते हैं लेकिन गवाह मुकर जाते हैं। जिसने मर्डर किया है, वह इनोसेंट हो गया या

श्री आर0के0एस0-----जारी।

16/03/2017/1855/RKS/As/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर...जारी

जिसने रेप किया वह इनोसैंट हो गया, नहीं। कानून की नजरों में वह इनोसैंट हो गया क्योंकि जज, गवाह खरीदे गए हैं। ऐसा ही आप लोग भी कर रहे हैं। जो बच्चे टॉपर थे उनको किस गुनाह की सज़ा दी गई? उनको सलैक्शन से क्यों रोका गया? 19-21 तो चलता है लेकिन 99 प्रतिशत वाले को इग्नोर कर आप 50 प्रतिशत वाले को नौकरी दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा अन्याय कोई नहीं करता जो आपकी सरकार और मंत्रियों ने किया। आपने हमीरपुर के साथ भेदभाव किया है। गलत चाहे मैंने किया । am liable for it. गलत चाहे आपने किया you are liable for it. गलत, गलत है, चाहे वह आप लोगों ने किया हो या हमने किया हो। You have to accept it. चिंतपुरनी में कार पार्किंग कॉम्पलैक्स आपने लीज़ पर दिया है। मैंने इस पर नियम-62 के अंतर्गत चर्चा मांगी है। जिस पाटी को यह कॉम्पलैक्स लीज़ पर दिया है उससे ट्रांसपोर्ट को करोड़ों रुपये का घाटा हुआ है। मैं यह देख रहा हूं कि आपकी सरकार में ओपन भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां से उठकर चले गए हैं। यहां पर यह कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत संस्थान खुल गए हैं और डाक्टर्ज भी आ गए हैं। यह एक रुटिन वर्क है। यह एक प्रोसैस है, चाहे किसी की भी सरकार हो। क्या आपने युनिसेफ की रिपोर्ट पढ़ी है? मैंने इसका पहले भी जिक्र किया था परन्तु माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसका जवाब नहीं दिया है। हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन 70-80 लाख के करीब हैं और 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे शायद 2-3 लाख ही होंगे। लेकिन 56 हजार

बच्चे कुपोषण से शिकार हैं। क्या आप महिलाओं और बच्चों को यह स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं? 33 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे कुपोषण से शिकार हैं। वे बच्चे इस प्रदेश को कहां ले जाएंगे। इसके लिए सरकार की कमजोरी कहां है? यहां पर मैडिकल कॉलेजों का जिक्र किया गया। हमीरपुर का मैडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की देने है। परन्तु इस मैडिकल कॉलेज के लिए अभी तक जमीन तक चयन नहीं हुई है। हमने बार-बार कहा कि आयुर्वेदिक की बिल्डिंग या स्कूल की बिल्डिंग में इसकी क्लासिज़ शुरू कर दो। वह मैडिकल कॉलेज हमीरपुर में आया परन्तु गया कहां इसका कोई नामो-निशान नहीं है। जो आदरणीय नड्डा जी बिलासपुर में एम्ज लाएं हैं उसके लिए आप मना कर दो कि यह हमें नहीं चाहिए।

अध्यक्ष,श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

16.03.2017/1900/SLS-AG-1

अध्यक्ष : इस माननीय सदन का जो समय बढ़ाया गया था वह समाप्त हो चुका है जबकि अभी बोलने वाले कुछ सदस्य शेष हैं। मैं समझता हूं कि अगर थोड़ा कम बोलेंगे तो आप जल्दी जा सकते हैं।

अब इस माननीय सदन की बैठक का समय 7.45 अपराह्न तक बढ़ाया जाता है।

श्री नरेन्द्र ठाकुर : बम्बर जी, आप मना कर दीजिए कि हमें AIIMS नहीं चाहिए। AIIMS खुलेगा। माननीय मोदी जी उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... हम ही बजट दे रहे हैं और हम ही उसको खोलेंगे भी। आपके पास कुछ नहीं है। ...(व्यवधान)... आप मेरी बात सुनिए। आप लोगों को और कितना गुमराह करोगे? हर बार बजट पेश करते हैं कि हमारा बजट टैक्स फ्री है। बड़ी वाही-वाही लूटी जाती है। सोर्स ऑफ इनकम जीरो है। आप इंसैंटिव दे रहे हैं जबकि टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। जिस ढंग से आपने इस बार घोषणाएं की हैं, उससे फिसकल डैफिसिट इस साल 4% तक चला जाएगा और उससे निबटने के लिए आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी स्टेट की फाइनैंशियल पोजिशन ठीक हो, हमारा कर्ज़

कम हो तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। आप इंडस्ट्री को अपलिफ्ट कीजिए। आपके कार्यकाल में उद्योग भी घटे हैं जो हिमाचल का एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। उसके बारे में आपको कोई चिंता नहीं है। हाईडल प्रोजैक्ट भी कम हुए हैं। यह भी सोर्स ऑफ इनकम है। इनको आप बढ़ाइए। बजट इन चीजों के लिए डाइवर्ट कीजिए न कि भत्ते और इंसैटिव देने के लिए। क्यों आप स्टेट को बैंकरप्सी की ओर ले जा रहे हैं? आप कुछ बेसिक सौलिड अप्रोच रखिए। सरकारें आती-जाती रहती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आज विधायक हैं, कल नहीं रहेंगे। आज आप मंत्री हैं लेकिन कल नहीं रहेंगे। परंतु राज्य का कुछ भला करके जाओ न कि लोगों को गुमराह करके जाओ।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : मैं सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि बीच में न बोलें। चर्चा को आपस में न करें क्योंकि इससे समय बर्बाद होता है।

16.03.2017/1900/SLS-AG-2

श्री नरेन्द्र ठाकुर : आप टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए। लेकिन जहां से भी आपकी इनकम जनरेट हो सकती है वहां यह बजट साइलैंट है और आप भी साइलैंट हैं। आप चर्चा कर रहे हैं कि दिहाड़ी 200 से 210 और 250 से 300 रुपये हो गई। यह कोई हैल्थफुल बजट नहीं है। यह स्वयं को और प्रदेशवासियों को धोखा देने की बात है। इसलिए इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल डायरैक्शनलैस और विज़नलैस है। इसमें कोई सोच नहीं है कि हम प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं। इस बजट से हम अपने प्रदेश को बैंकरप्सी की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए इसमें सुपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। मैं इस बजट का डटकर विरोध करता हूं।

16.03.2017/1900/SLS-AG-3

अध्यक्ष : अब श्री मनोहर धीमान जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री मनोहर धीमानः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 10 मार्च को जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2017-18 का बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसपर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस उम्र में भी उन्होंने साढ़े चार घंटे खड़े होकर बजट भाषण पढ़ा। इसके लिए तो माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने भी उनका धन्यवाद किया था और बधाई दी थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट को सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

जारी ..गर्ग जी

16/03/2017/1905/RG/DC/1

श्री मनोहर धीमान----जारी

सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने विधायक निधि दस लाख रुपये बढ़ाई है। इससे सभी माननीय सदस्यों को फायदा हुआ है और इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना जरूरी है। इसी कड़ी में माननीय मुख्य मंत्री जी का मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि विधायक निधि खर्च करने का कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया है। जैसे स्कूलों, खेलों का सामान, अस्पतालों में कम्बल, बिस्तर, महिला मण्डलों जैसी संस्थाओं के लिए फर्नीचर इत्यादि खरीदने का प्रावधान इसमें रखा गया है। इसका भी फायदा हम जैसे लोगों को हुआ है। क्योंकि जब भी हम स्कूल जाते थे या कोई संस्था हमें बुलाती है, तो वहां हमें अपनी जेब से पैसे देने पड़ते थे। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए फल और सब्जी रखने के लिए प्लास्टिक क्रेट्स पर जो 50% उपदान का प्रावधान रखा गया है इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। इसका सीधा फायदा किसानों को हो रहा है। चंबा, हमीरपुर, सोलन, ऊना, मण्डी, बिलासपुर,

सिरमौर और कांगड़ा के किसानों के लिए मुख्य मंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना चलाई है और इस पर भी 50% उपदान जो रखा गया है इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। विशेषकर हमारे इन क्षेत्रों के किसानों को बहुत लाभ होगा क्योंकि जंगली-जानवर और बंदरों के कारण लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि बंदर इस कीवी फल को नहीं खाता।

अध्यक्ष महोदय, हर विधान सभा क्षेत्र में दस लाख रुपये की लागत से खेल का मैदान बनाने की जो योजना इस बार रखी है इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। इसके साथ मैं एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग के नाम से 108 कनाल भूमि वहां है। मैंने पिछले विधान सभा सत्र में भी यह बोला था कि सरकार इसको अपने कब्जे में ले ले, नहीं तो लोग इसको कब्जा लेंगे। इसी तरह पंचायत के चौकीदार, आंगनवाड़ी और सिलाई अध्यापकों का जो मानदेय बढ़ाया है इसका भी सीधा-सीधा गरीब लोगों को फायदा हुआ है। जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों को विकास के लिए धन मुहैया करवाया। जिससे सीधे जनमानस को लाभ मिलेगा।

16/03/2017/1905/RG/AG/2

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले चार वर्षों में विकास के जो कार्य हुए हैं, उनका विवरण मैं यहां सदन में रखना चाहता हूं।
मेरे क्षेत्र में बहुत लंबे समय से एक संत महाराज जी डिग्री कॉलेज चलाते थे और उनकी बहुत इच्छा थी कि सरकार इसको टेक ओवर कर ले। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि पिछले प्रवास के दौरान वह टेक ओवर कर लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ-साथ माननीय उद्योग मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में 108 करोड़ रुपये की लागत से एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने जा रहा है जिसका कार्य तेज गति से चला हुआ है। इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में गंगथ में एक सब-तहसील खोली गई है जिसका फायदा

लगभग 17 पंचायतों को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त एक पी.एच.सी. हवाल में खोली गई,

एम.एस. द्वारा जारी

16/03/2017/1910/MS/AG/1

श्री मनोहर धीमान जारी---

कम-से-कम 40 किलोमीटर के एरिये में कोई भी डिस्पेंसरी नहीं थी और वह दो नेशनल हाइवे को जोड़ने वाली थी तथा आए दिन वहां पर दुर्घटनाएं होती रहती थीं। जहां नुरपूर और पठानकोट के बीच में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। 23 स्कूल मेरे इंदौरा विधान सभा क्षेत्र में अपग्रेड किए गए और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि सभी स्कूलों के भवनों के पैसे भी आ गए हैं और काम भी शुरू हो गया है। एक वैटरीनरी हॉस्पिटल गंगथ में आपने दिया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। अभी हाल ही में कांगड़ा प्रवास के दौरान मेरे इंदौरा विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री जी का प्रवास हुआ और कई पुलों और वॉटर सप्लाई स्कीमों का वहां शिलान्यास किया गया। इसके अलावा एस0डी0एम0 कोर्ट खोलने की घोषणा भी की गई। इसके लिए मैं और मेरे क्षेत्र की सारी जनता आपकी सदा आभारी रहेगी। जो वहां अक्षम बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने की घोषणा की गई, मैं इसके लिए भी आपका धन्यवादी हूं। इसी तरह से एक बाईपास मोटली से, जब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रवास से वापिस जा रहे थे तो वहां फाटक बन्द था इसलिए रूकना पड़ा। तो मुझे इन्होंने पूछा कि अब कितनी देर यहां गाड़ी रूकेगी? तो मैंने बोला कि आधा घण्टा रूकना पड़ेगा। इन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों? मैंने कहा कि यहां से 106 ट्रेनें अप-डाउन करती हैं। हालांकि दिल्ली-जम्मू ट्रैक है लेकिन संयोग से हमें पठानकोट ही नजदीक पड़ता है। कई बार तो हमारे मरीजों की गाड़ी में बैठे-बैठे ही मौत हो जाती है। संयोग से वह ट्रैक चार जगहों से गुजरता है और चारों जगह फाटक हैं। मिलमा-मिथल-कंदरौड़ी और मोटली तो ये जो बात मैं सुना रहा हूं, मुख्य मंत्री जी मोटली में बैरियर पर

खड़े थे तो वहां ठीक 20-25 मिनट लगे। मैंने कहा कि एक ट्रेन आएगी तो 15 मिनट और यदि दो निकलेंगी तो 35-40 मिनट का समय लगेगा। तो मुख्य मंत्री जी ने वहां खड़े-खड़े चीफ इंजीनियर को बुलाया और उन्होंने आदेश किए कि यहां से कोई बाईपास निकाला जाए। जब मुझे पूछा तो मैंने रूट बता दिया। मैंने कहा कि आप छोटी गाड़ी के लिए रूट बना दो। लेकिन ये बोलते कि मोटरेबल रोड बनाएंगे और उसी समय इन्होंने उनको आदेश दिए और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि वह लगभग तीन किलोमीटर का रोड

16/03/2017/1910/MS/AG/2

है और उसकी 1 करोड़ 75 लाख रुपये की डी0पी0आर0 भी तैयार हो रही है। इसके अलावा जिन-जिन सड़कों से उस दिन मुख्य मंत्री जी गुजरे थे तो मंच के माध्यम से इन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि आपके विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा मैंने देख ली है और बहुत ही जल्दी इसके लिए पैसे का प्रावधान किया जाएगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि बरसात से पहले सड़कों की मुरम्मत हो जाए तो ठीक रहेगा।

एक वहां आपने धीमान कल्याण बोर्ड का गठन करने की भी बात कही थी। मैं चाहता हूं कि बहुत जल्द ही इसको अमलीजामा पहनाया जाए ताकि लोगों में एक संदेश बना रहे कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं वैसा ही करते हैं।

इसके अलावा भी मेरे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं क्योंकि यह पंजाब के साथ सटा हुआ एरिया है। मैंने पिछली बार यहीं विधान सभा में यह मसला उठाया था कि 70 किलोमीटर के लगभग पंजाब और हिमाचल की सीमा मेरे क्षेत्र में लगती है और संयोग से वहां जो बॉर्डर है, उसमें एक तरफ चक्की खड्ड लगती है, एक तरफ छौंछ खड्ड लगती है और दूसरी तरफ ब्यास है तथा आए दिन वहां झगड़े होते हैं। वे झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि बैड रिवर है। जब बरसात होती है तो लोग रेत और बजरी के लिए लड़ते हैं। वहां क्रैशर लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं,

जारी श्री एस0एस0 द्वारा----

16.03.2017/1915/SS-AG/1

श्री मनोहर धीमान क्रमागतः

पिछली बार भी आपने आश्वासन दिया था और यह काम शुरू भी हुआ था, नूरपुर की बाऊंडरी तक हो गया लेकिन जहां से मेरे विधान सभा क्षेत्र का हलका लगता है वहां काम नहीं हुआ। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि बहुत जल्द इसकी हदबंदी की जाए। पंजाब की सीमा के साथ सटे होने के कारण मेरे इलाके में नशा बहुत बुरी तरह घर कर गया है। मैं कांगड़ा पुलिस को शाबाशी देता हूं कि उन्होंने एक साल के अंतराल में इस पर 90 परसैंट अंकुश लगा दिया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसी तरीके से काम करे और इसे जड़ से खत्म करे क्योंकि मेरे इलाके का नौजवान इसकी चपेट में आ गया है।

दूसरी मेरे इलाके की बहुत गम्भीर समस्या है कि अधिक खड्डे होने के कारण वहां क्रैशर बहुत तादाद में लगे हैं। यहां उद्योग मंत्री जी बैठे हैं। मैं क्रैशर के खिलाफ नहीं हूं। खनन के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन अवैध खनन के खिलाफ हूं। वे कहीं भी मापदंड पूरे नहीं करते। नशा वहां इतनी भयंकर दशा में चल रहा था कि केवल एक महकमा यानी पुलिस वालों ने उस पर कंट्रोल कर लिया है। लेकिन यह अवैध खनन, जिसे रोकने के लिए 17-18 महकमे हैं, यह अवैध खनन क्यों खत्म नहीं होता? यह बात मुझे समझ नहीं आई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर लोगों ने एक सलोगन बना लिया है कि नशा नौजवान को खत्म कर देगा और खनन किसानों को खत्म कर देगा। यह गम्भीर समस्या है इसलिए मैं इसे आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

मेरा क्षेत्र दो हिस्सों में बंटा है। एक, ब्यास के किनारे-किनारे बिल्कुल पंजाब के साथ सटा है और वह बहुत उपजाऊ जमीन है लेकिन खनन के कारण वह सारी बरबाद हो जायेगी। मैं दावे से कहता हूं कि मेरा किसान इतना मेहनतकश है कि अगर इस चीज़ को रोका जाए, वहां नो माइनिंग जोन किया जाए तो वे इतना अनाज पैदा कर सकते हैं कि पूरे

हिमाचल को फीड कर सकते हैं। दूसरा, जो अनोह एरिया है वहां सब्जी की पैदावार बहुत होती है। इसलिए एक सब्जी मंडी मेरे इलाके में

16.03.2017/1915/SS-AG/2

बननी चाहिए। पीछे दो साल पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और मैंने सारे कागज़ात भी विभाग को दे दिये थे, लेकिन आज दिन तक वह काम नहीं हुआ। इसका क्या कारण रहा होगा, पता नहीं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इसको जल्दी खोला जाए। एक अनाज मंडी भी उस इलाके को चाहिए क्योंकि हमारे किसान अनाज तो पैदा कर लेते हैं लेकिन पंजाब की मंडियों में धक्के खाते हैं। उनको अपनी मर्जी के दाम नहीं मिलते हैं, वहां उनका शोषण होता है इसलिए एक अनाज मंडी खोली जाए। इसके अलावा मेरे इलाके में अधिकांश लोगों ने दुधारू पशु रखे हुए हैं और कई लोगों की आजीविका ही दूध बेचकर होती है। मेरे इलाके में जब कभी किसी दुधारू पशु का सीजेरियन करना पड़ता है तो उसको शाहपुर में रैफर किया जाता है जोकि हमारे वहां से 70 किलोमीटर दूर है या फिर उसके लिए पंजाब में गुरदासपुर जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि इंदौरा में एक वैटरिनरी पॉली क्लीनिक खोली जाए ताकि किसानों को राहत मिले।

दूसरा, हमारे इलाके में किन्नू, आम, संतरा, लीची, नीम्बू आदि की अधिक मात्रा में पैदावार होती है, महाजन साहब ने तो कोल्ड स्टोरेज के लिए बोला, वह भी होना चाहिए लेकिन

जारी श्रीमती के0एस0

16.03.2017/1920/केएस/एएस/1

श्री मनोहर धीमान जारी---

मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई प्रोसैसिंग युनिट लग जाए ताकि किसान के फल व सब्जी का वहीं समाधान हो और वह पंजाब में जा कर धक्के न खाए। अपनी चीज पैदा करके दूसरी स्टेट में जा कर धक्के न खाए। इन सभी बातों को माननीय मुख्य मंत्री के समक्ष लाना चाहता था। यह जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर रखा मैं इसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

16.03.2017/1920/केएस/एएस/2

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष् महोदय, माननीय सदस्य ने इनके चुनाव क्षेत्र से जुड़ी माइनिंग का यहां पर जिक्र किया है। इनके चुनाव क्षेत्र में 41 क्रशर हैं और मेरे ख्याल में हिमाचल प्रदेश में सबसे पैक्ड कंसिच्युएंसी अगर क्रशर के हिसाब से होगी तो इनकी है। उनमें से अभी 25 क्रशर चल रहे हैं। काफी क्रशर ने जो स्टेट का पैसा देना है पांच सौ रुपये के हिसाब से जो कैल्कुलेट हुआ है वह भी करोड़ों रुपयों में है। जिसके लिए हम उन सभी को नोटिस देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस एरिया की ये बात कर रहे हैं, एक तो दुर्भाग्य है या किसी समय में हुआ होगा वह चाहे डमटाल है, कंदरौड़ी है, मंड है, जितने भी इनके एरियाज़ हैं, 1990-91-92 के दौर में वहां पर बहुत क्रशर लगे। कल हमने आपको लिस्ट भी प्रोवाईड की है। मैक्सिमम क्रशर लगे और वे बॉर्डर की वजह से लगे। जिस एरिया को ये कह रहे हैं कि उसको नो माईनिंग एरिया घोषित कर दिया जाए या उसकी पैमाईश कराई जाए तो वहां पर 6 क्रशर हिमाचल के लगे हैं और सात पंजाब के लगे हैं। अगर हम हिमाचल के बन्द कर देते हैं तो पंजाब के लिए खुली छूट हो जाएगी और पंजाब वालों के लिए वह सारा एरिया ओपन हो जाएगा। माननीय सदस्य से हम कन्सल्टेशन करेंगें क्योंकि वहां पर बाऊंडरी का डिस्प्यूट है और वह सैटल ही नहीं हो पा रहा है । बहुत बार कोशिश की है कि पंजाब और हिमाचल की बाऊंडरी डिस्प्यूट सैटल हो जाए। हम एक बार फिर कोशिश करेंगें कि वह डिस्प्यूट सैटल हो। फायदा तो तभी होगा। अगर दोनों तरफ के क्रशर बन्द हों। अगर आप हिमाचल के क्रशर बन्द करवा देते हैं तो पंजाब वालों के लिए वह ओपन ग्राऊंड हो जाएगा। मैं यह स्थिति स्पष्ट करना चाहता था।

16.03.2017/1920/केएस/एएस/3

अध्यक्षः अब श्री विनोद कुमार जी चर्चा में भाग लेंगें।

श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2017-18 का जो बजट पेश किया, उस बजट के विषय में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वैसे तो काफी विस्तार से इस बजट को ले कर यहां पर चर्चा हुई है लेकिन फिर भी बजट से पहले जैसे अनुमान लगाया जा रहा था, काफी लोग इस बजट को ले कर काफी चर्चाएं भी कर रहे थे लेकिन जैसे बजट पेश किया गया, मुझे लगता है कि इस बजट से इस प्रदेश का कोई भी वर्ग आज खुश नहीं है। प्रदेश का हर नागरिक आज इस बजट से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस बजट के विषय में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जैसे कहा भी है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया और वह भी मरी हुई, इस बजट से यही प्रतीत होता है।

अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात शिक्षा के क्षेत्र से शुरू करना चाहूंगा। यह बात सही है कि प्रदेश की सरकार ने अनेकों नए स्कूल खोले हैं। अनेकों स्कूलों को अपग्रेड भी किया है और हम इस बात को मानते हैं लेकिन इतने नए स्कूलों को खोलने के बावजूद भी, इतने नए स्कूलों को अपग्रेड करने के बावजूद भी आज आप देख रहे हैं कि दिन-प्रतिदिन सरकारी स्कूलों में जिस तरह से बच्चों की तादाद घटती जा रही है

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

16.3.2017/1925/av/as/1

श्री विनोद कुमार------- जारी

उसका क्या कारण है? मेरा मानना है कि उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम घोषणाओं की झड़ी तो लगा रहे हैं लेकिन स्कूल के अंदर बच्चों के लिए बैठने की अच्छी

व्यवस्था कैसी हो, उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर कैसे हो इस बात को लेकर के हम लोगों को कहीं-न-कहीं चिन्तन करना होगा। इस बात पर चिन्तन करते हुए हमें चार साल का समय हो गया है लेकिन यह सरकार इस विषय को लेकर के बिल्कुल भी गम्भीर नहीं है। मैं पूरे प्रदेश की बात न करता हुआ अपने चुनाव क्षेत्र नाचन की ही बात करूंगा। आज भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर कोई भी टीचर नहीं है। अगर किसी स्कूल में है भी तो केवल एक-एक अध्यापक है। वह अध्यापक खुद इस बात को सोचने के लिए विवश हो जाता है कि मैं स्कूल की डाक को तैयार करूं या उस डाक को आगे भेजूं। बच्चों को पढ़ाऊं या घंटी बजाऊं, कौन सा काम करूं। इस बात को लेकर वह अध्यापक भी आज दुःखी है। उसको भी यह समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या-क्या करे। हमें इस बात को बोलते-बोलते चार वर्ष हो गये हैं कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए कम-से-कम अध्यापकों का होना बहुत ही आवश्यक है। मगर जहां पर एक स्कूल खोलने की बात होती है वहां पर हम चार-चार स्कूल खोल रहे हैं जिसके कारण आज हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। यह उन भोले-भाले बच्चों के साथ कहीं-न-कहीं बहुत बड़ा धोखा है। मेरे नाचन विधान क्षेत्र में जी0पी0एस0 चन्दैस, जी0पी0एस0सरयाच, जी0पी0एस0 भटैड़ा इत्यादि अनेकों स्कूल ऐसे हैं जहां पर आज भी एक-एक अध्यापक ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर सरकार आज भी बच्चों को बैठने के लिए कमरों की व्यवस्था नहीं कर पाई है। कुछ स्कूलों को खुले हुए 7-8 साल हो गये हैं लेकिन उन स्कूलों के पास आज भी अपने भवन नहीं है। मेरे नाचन विधान सभा क्षेत्र में जी0पी0एस0 कटवांडी, जी0पी0एस0 प्लौटा,

16.3.2017/1925/av/as/2

जी0पी0एस0 ओढ़ीधार, जी0पी0एस0 नालू, जी0पी0एस0 पलोता इत्यादि कई स्कूल हैं जहां पर बच्चों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जब-जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस पार्टी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की याद आती है।

लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि जब आप बैकडोर के माध्यम से एंट्रियां करते हैं जिसमें चाहे पी0टी0ए0 की भर्ती की बात हो, चाहे पी0ए0टी0 की बात हो, चाहे एस0एम0सी0 की बात हो या फिर आउट सोर्स की बात हो। ये जितनी भी भर्तियां हुई हैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोस्टर लागू नहीं किया गया। लेकिन मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि

श्री वर्मा द्वारा जारी

16/03/2017/1930/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

श्री विनोद कुमार..... जारी।

आपने वाले विधान सभा के चुनाव में यही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब-जब चुनाव आते हैं, तब-तब बात उस गरीब को ले करके की जाती है, उस गरीब परिवार को ले करके की जाती है, लेकिन आजादी के 68 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन गरीबों की गरीबी तो नहीं गई, वे गरीब आज भी उसी तरह से गरीब हैं। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि 68 वर्षों में गरीबी तो नहीं गई, लेकिन उन गरीबों ने इस देश से ही कांग्रेस को खत्म कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां पर बात की गई कि प्रदेश में 42 नये सरकारी कॉलेज खोले गये और हिमाचल प्रदेश में अब 119 सरकारी कॉलेज हो गये हैं। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाना चाहूंगा कि नाचन विधान सभा क्षेत्र से एक बार नहीं, अनेकों बार डैपूटेशन उनके साथ मिलने आया कि हटगढ़ में हमें भी एक कॉलेज चाहिए, क्योंकि हटगढ़ हमारा केन्द्र बिन्दु है और उसके आस-पास लगभग 25 से 30 पंचायतें आती है। एक नहीं अनेकों बार हमने विधान सभा के अंदर, प्लानिंग की बैठक के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी को इस विषय से अवगत करवाया और कहा कि जहां आपने इतने कॉलेज दिए हैं, तो क्यों न मण्डी जिला के नाचन विधान सभा क्षेत्र को भी एक कॉलेज दे दिया जाये। लेकिन उन्होंने वहां की जनता की एक बात नहीं मानी, जिसका सबसे बड़ा कारण हम यही समझते हैं, यहां पर सदन में चर्चा भी हुई कि माननीय मुख्य मंत्री जी किसी भी क्षेत्र से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते, ऊपर का हिमाचल, नीचे का

हिमाचल या बीच का हिमाचल में कोई भेदभाव नहीं करते, लेकिन नाचन विधान सभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते, वहां पर कॉलेज नहीं दिया गया। मैं उनके ऊपर भेदभाव करने का आरोप लगाता हूं। इसके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष जी मैं हैल्थ विभाग को लेकर भी इतना ही कहना चाहूंगा कि हैल्थ मिनिस्टर हमारे मण्डी जिला से संबंध रखते हैं। यहां पर जिस तरह से प्रदेश की पूरी रिपोर्ट दी गई है कि हिमाचल प्रदेश में 21 सिविल अस्पताल खोले गये हैं, 34 सामाजिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये और 96 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं। लेकिन आज भी अधिकतर स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं, जहां पर स्टॉफ नहीं हैं। मैंने एक बार नहीं, अनेकों इस विषय में माननीय मंत्री जी से चर्चा की , परन्तु आज तक आश्वासन ही मिलता रहा। मैं नाचन विधान सभा

16/03/2017/1930/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

क्षेत्र के विषय में कहना चाहूंगा कि झूंगी में एक पी0एच0सी0 है, वहां पर एक ही डॉक्टर का पद सृजित हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से झूंगी पी0एच0सी0 में डॉक्टर नहीं है। इसके साथ ही एक पी0एच0सी0 जाच में पड़ती है, वहां पर भी एक ही डॉक्टर का पर सृजित हैं, लेकिन वहां पर भी डॉक्टर नहीं है। कनैड में भी हमारी एक पी0एच0सी0 हैं, वहां पर भी एक डॉक्टर का पद सृजित हैं, वहां पर भी डॉक्टर नहीं है। इसके अलावा चौक में एक पी0एच0सी0 है, जहां डॉक्टर के 2 पद सृजित हैं, लेकिन एक डॉक्टर ही अपने सेवाएं दे पा रहा है। अभी जिस गोहर की बात आदरणीय मंत्री जी कर रहे थे, उस सिविल हॉस्पिटल को अपग्रेड हुए लगभग 3 वर्ष का समय हो चुका है, लेकिन मुझे 3 साल चीखते-चिल्लाते हो गये हैं, वहां पर अभी भी 8 में से 2 डॉक्टर ही अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा भी था कि एक सप्ताह के अन्दर डॉक्टर आ जाएंगे, लेकिन अभी तक माननीय मंत्री जी वह डॉक्टर नहीं पहुंचे हैं। इसके साथ-साथ एक हॉस्पिटल रत्ती में भी है, वहां पर भी 6 डॉक्टरों के पद सृजित हैं और केवल 2 ही डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी एक मार्च को एक एक्सिडेंट सैंजी पंचायत में हुआ था। जब हम 15-20 पेशेंट उस हॉस्पिटल में लेकर गये, तो एक ही डॉक्टर था और एक डॉक्टर इतने पेशेंट को कैसे देख सकता है, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। सुन्दरनगर में 100 बैडिड हॉस्पिटल है और अभी जो एक्सिडेंट हुआ था, उस एक्सिडेंट होने के कारण बहुत से लोगों के वहां पर ऑपरेशन होने थे। जब मैंने वहां पर डॉक्टर से बात की कि आप ऑपरेशन क्यों नहीं कर

रहे हो? तो डॉक्टर ने कहा कि यहां पर एनेस्थिसिया नहीं है, जिसके कारण हम किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कम-से-कम एक डॉक्टर वहां पर भेज दें, ताकि वहां पर निरंतर ऑपरेशन हो सकें।

श्रीमती एन0एस0 ..... द्वारा जारी।

16/03/2017/1935/एन0एस0/डी0सी0/1

श्री विनोद कुमार..... जारी।

इसके अलावा भी एक नहीं अनेकों बातें हैं। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि हमारी जो पी0एच0सी0 बग्गी है, वहां पर एंबुलेंस पी0एच0सी0 बग्गी के नाम से आई है, लेकिन पिछले कई महीनों से वह एंबुलेंस अपनी सेवायें वहां पर नहीं दे रही है। जब मैंने सी0एम0ओ0 से बात की तो उन्होंने कहा कि ये आर्डर ऊपर से हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो एंबुलेंस आपने बग्गी पी0एच0सी0 के लिए दी है, उस एंबुलेंस को बग्गी में ही भेजने का मैं आपसे निवेदन करता हूं, ताकि वहां की जनता को उसका ठीक से लाभ मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आई0पी0एच0 विभाग के विषय में कुछ कहना चाहूंगा कि यहां पर आई0पी0एच विभाग को लेकर भी बड़ी-बड़ी बातें और चर्चाएं की गई और उसमें कहा गया कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल मिले, लेकिन इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आज भी हमें सुबह 6 बज़े से 10 बज़े तक फोन आते हैं, तो उन फोनों में लगभग 80 से 90 परसेंट यही कहा जाता है कि हमारे यहां पानी नहीं है या पानी ठीक नहीं है। मैं तो आई0पी0एच0 के विभाग को इतना ही कहना चाहूंगा कि आप स्वच्छ पेयजल देने की जहां तक बात कर रहे हैं, तो यह कैसे संभव हो पाएगा, क्योंकि जो फिल्टर टैंक बने हुए हैं, वे खराब हो चुके हैं और पानी सीधा, चाहे खड्डों से आपने उठाया है, चाहे कूहलों से पानी आपने उठाया है, वह पानी सीधा लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है, जिसके कारण बीमारियां फैल रही है। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में आपने देखा होगा कि मौवीसेरी और सयांज पंचायत में डायरिया फैला। इसी तरह से नौण और चैलचौक में भी पीछे डायरिया

फैला था, जिसका डॉक्टर ने एक ही कारण बताया था कि आपने यहां फिल्टर बैड नहीं लगे हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में -(व्यवधान)-

अध्यक्षः श्री सुरेश भारद्वाज जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुरेश भारद्वाज श्री आर0के0एस0 ..... द्वारा जारी।

16/03/2017/1940/RKS/As/1

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का सत्र लगा हुआ है। माननीय मंत्रीगण सदन में बैठे हुए हैं और माननीय सदन बहुत गंभीर विषय 'प्रदेश के बजट अनुमानों' पर चर्चा कर रहा है। लेकिन ऑफिसर्ज़ गैलरी टोटली खाली है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये अधिकारी विधान सभा को जिला परिषद/पंचायत समिति समझने लगे हैं। यहां पर ऑफिसर्ज़ गैलरी में कोई भी कार्यवाही को नोट करने वाला नहीं है। विधान सभा की कार्यवाही विभागों में नहीं जाती है। हमारे बोलने और विधान सभा को चलाने के लिए जो इतना खर्चा होता है उसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए विधान सभा से चीफ सैक्रेटरी को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधिकारी यहां पर क्यों उपस्थित नहीं होते हैं? अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न आपका है, क्योंकि अध्यक्ष के निर्देश से विधान सभा चलती है। आपकी डायरेक्शन सरकार को जानी चाहिए और अधिकारियों को यहां पर बुलाकर उनके विरूद्ध एक्शन लेना चाहिए। अगर इस विषय पर हमें प्रीवलेज़ लाना पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ प्रीवलेज़ भी लाएंगे।

अध्यक्षः आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह सारी कार्यवाही नोट हो रही है। (व्यवधान)... परन्तु प्रश्न यह है कि अधिकारियों को यहां बैठना चाहिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो मामला माननीय सुरेश भारद्वाज जी ने उठाया है, यह गंभीर मामला है। हम इस बात को मानते हैं कि अधिकारियों को यहां गैलरी में बैठकर काम करना चाहिए। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो अधिकारी

यहां पर मौजूद नहीं हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हर विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी होती है। प्लानिंग और फाइनैंस का हर अधिकारी यहां पर होना चाहिए। इसलिए कल से हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारी, अधिकारी दीर्घा में मौजूद रहें और दोंनों तरफ से जो चर्चा की जाती है, संबंधित विभागीय अधिकारी उस चर्चा को नोट करें।

16/03/2017/1940/RKS/As/2

श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में उठाऊ पेयजल योजना चचोट-चैलचौक का शिलान्यास वर्ष 2012 को आदरणीय रविन्द्र सिंह जी ने किया था। लेकिन आज 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस स्कीम का काम पूरा नहीं हुआ है। मैंने इस मसले को विधान सभा प्रश्न व माननीय मंत्री जी के सामने एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार उठाया। लेकिन यह कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ। इसके साथ ही उठाऊ पेयजल योजना मौवीसेरी का काम भी पूरा नहीं किया गया है। जहां तक पी.डब्ल्यू.डी. विभाग की बात है, हम इतना कह चुके हैं कि सरकार के 'कान में जूं तक नहीं रेंग' पा रही है। हमने हर बैठक में सरकार से आग्रह किया है कि हमने जितनी भी एम.एल.एज. प्रायोरटी में सड़कें डाली हैं, उन सड़कों की डी.पी.आर्ज. को तैयार किया जाए। इसके अलावा जो खराब सड़कें हैं उनको ठीक किया जाए। लेकिन न वह डी.पी.आर्ज. बनी और न ही खराब सड़कें ठीक हुई । जिला मंडी के अंदर यदि मैं सभी विधान सभा क्षेत्रों की बात करूं तो इन सभी चुनाव क्षेत्रों में मुझे नहीं लगता कि 10 प्रतिशत सड़कें भी विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत तैयार हुई हो। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस तरह का भेदभाव जिला मंडी के साथ क्यों हो रहा है? मेरे विधानसभा क्षेत्र की गोहर-देवीधार सड़क का इतना बुरा हाल है कि वहां सड़क कम और गड्ढे ज्यादा हैं। वहां आपको गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। आप खुद सोचने को विवश हो जाएंगे कि यह सड़क कभी पक्की भी हुई थी या ऐसी ही थी। इसके अलावा चैलचौक से मौवीसेरी,

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

16.03.2017/1945/SLS-AG-1

श्री विनोद कुमार..जारी

चैलचौक से पण्डोह, धनोटू से रवाहंडा, खटेरू से सुन्दरनगर, ओल्ड शिमला-मण्डी रोड, किलिंग से स्यां, स्यां से बाली वाया बिहारटा, कटलोग से भगवानपुर आदि सड़कों का हाल बहुत खराब है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो सड़कें खराब हैं उनको ठीक करने की चिंता की जाए।

यहां पर दैनिक मज़दूरी बढ़ाने की बात की गई। कहा गया कि जब आपकी सरकार सत्ता में आई थी तो दिहाड़ी 150 रुपये थी जिसे बढ़ाकर अब 210 रुपये किया गया है। हम इस बात को मानते हैं। क्या यह बहुत है?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप वाईंड अप कर रहे हैं?

श्री विनोद कुमार : सर, मुझे अभी 5-7 मिनट और लगेंगे।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक 8.00 बजे अपराह्न तक बढ़ाई जाती है।

श्री विनोद कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, इस महंगाई के ज़माने में उस गरीब मज़दूर को ठगा गया है क्योंकि केवल 10 रुपये ही उसकी दिहाड़ी बढ़ाई गई है। यह इस सरकार ने ऊंट के मुंह में जीरा डालने का काम किया है।

यहां पर वृद्धा, विधवा तथा अपंग पैंशन को बढ़ाने की बात की गई। यह बात सही है कि इसे 450 से 650 रुपये किया गया है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जब 2003 से 2007 तक प्रदेश में आपकी सरकार थी तो आपने एक भी रुपया न वृद्धा पैंशन का, न विधवा पैंशन का और न अपंग पैंशन का बढ़ाया था। जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने 200 रुपये से इसे

450 रुपया किया था और यह दोगुणा से ऊपर किया था। आपने राजनीति करते हुए यहां भी उन गरीबों के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है।

16.03.2017/1945/SLS-AG-2

यहां पर घोषणाओं को लेकर अनेकों बातें हुईं कि मुख्य मंत्री जी की सभी घोषणाएं सत्य होती हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2014 में माननीय मुख्य मंत्री मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो दिनों के प्रवास पर आए थे। उन्होंने वहां प्लौटा स्कूल को अपग्रेड करने की घोषणा की थी जो आज तक नहीं हुआ। उन्होंने प्लौटा पंचायत में आयुर्वेदिक डिसपैंसरी खोलने की घोषणा की थी जो आज तक नहीं खुली। इसके अलावा मुख्य मंत्री जी ने एक और घोषणा की थी। हमारी लोट पंचायत में गराड़ीघाट नामक स्थान हैं जहां पर उन्होंने आयुर्वेदिक डिसपैंसरी खोलने की घोषणा की थी लेकिन आज तक वह नहीं खुली। इसी तरह मेरे विधान सभा क्षेत्र में उन्होंने अनेकों घोषणाएं की हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं।

यहां पर अच्छे दिनों की बात की गई। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं यही कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश को 1998 तक केवल 3 नेशनल हाईवे मिले थे। वह भी सुरक्षा की दृष्टि से दिए गए थे। लेकिन जब प्रोफ़ेसर प्रेम कूमार धूमल की भाजपा सरकार बनी और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेई जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही थी तो उस समय हिमाचल को 9 नेशनल हाईवे दिए गए। इस तरह उन 3 नेशनल हाईवे को मिलाकर कुल 12 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश को मिले। उसके बाद जब प्रदेश में 2007 से लेकर 2012 तक हमारी सरकार रही तब हिमाचल प्रदेश को 4 और नेशनल हाईवे दिए गए।

जारी .. गर्ग जी द्वारा

16/03/2017/1950/RG/AG/1
श्री विनोद कुमार-----जारी

तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश को 68 वर्षों में 17 नेशनल हाइवे दिए गए जिसमें से 13-14 नेशनल हाइवे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में मिले और अब अढ़ाई वर्षों में रिकॉर्ड नेशनल हाइवे हिमाचल प्रदेश को मिले हैं।

Speaker : Wind up please.

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं ज्यादा लंबी बात न करता हुआ दो लाईनें कहकर समाप्त करुंगा और मैं इस सरकार को इतना ही कहना चाहूंगा कि

सपने वो सच होते हैं जिन सपनों में जान होती है,
पंखों से कुछ नहीं होता मित्रों ,हौंसलों से उड़ान होती है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बजट यहां प्रस्तुत किया गया है मैं उसका घोर विरोध करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171 004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 16 मार्च, 2017 **सचिव ।**